© भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

http://agua.cag.gov.in

Printed at Shiva Offset Press, Dehradun Ph. 0135-2715748

सत्यमेव जयते

राज्य के वित्त पर
भारत के नियन्त्रक, महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

उत्तराखण्ड सरकार

विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन		v
2.	कार्यकारी सारांश		vii
	अध्याय-1 **राज्य सरकार का वित्त**		
3.	चालू वर्ष के राजकोषीय लेनदेन का सार	1.1	2
4.	राज्य के संसाधन	1.2	5
5.	राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	8
6.	संसाधनों का उपयोग	1.4	12
7.	व्यय की गुणवत्ता	1.5	19
8.	सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण	1.6	22
9.	परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.7	26
10.	ऋण-वहन क्षमता	1.8	28
11.	राजकोषीय असंतुलन	1.9	31
12.	निष्कर्ष	1.10	34
13.	संस्तुतियाँ	1.11	35
	अध्याय- 2 **वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण**		
14.	प्रस्तावना	2.1	37
15.	विनियोग लेखे का सारांश	2.2	37
16.	वित्तीय जबावदेही एवं बजट प्रबन्धन	2.3	38
17.	विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन	2.4	45
18.	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.5	47
19.	बजट प्रक्रिया में कमियाँ	2.6	49
20.	चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम	2.7	50
21.	निष्कर्ष	2.8	51
22.	संस्तुतियाँ	2.9	52
	अध्याय- 3 **वित्तीय प्रतिवेदन**		
23.	उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	3.1	53
24.	विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	3.2	54
25.	दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि	3.3	54
26.	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ तथा अन्य व्यय के अन्तर्गत बुकिंग	3.4	55
27.	निष्कर्ष	3.5	56
28	संस्तुतियाँ	3.6	57

परिशिष्ट

स0	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट -1	राज्य का परिचय (उत्तराखण्ड)	59
परिशिष्ट 1.1	भाग अः सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना भाग बः वित्त लेखे का विन्यास	61/62
परिशिष्ट -1.2	भाग अः राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि भाग बः राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005	63/66
परिशिष्ट -1.3	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	69
परिशिष्ट -1.4	भाग अः वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार भाग बः 31 मार्च 2012 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	73/77
परिशिष्ट -1.5	वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत राज्य बजट से बाहरी अन्तरित निधियों को दर्शाती विवरणी	80
परिशिष्ट -1.6	विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के सारांशित वित्तीय विवरण	82
परिशिष्ट -2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता ₹ 1 करोड़ से अधिक थी या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था	83
परिशिष्ट -2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें व्ययाधिक्य प्रत्येक में ₹ 1 करोड़ से अधिक थी या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था	86
परिशिष्ट -2.3	ऐसे प्रकरण जिसमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	87
परिशिष्ट -2.4	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ 1 करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए	90
परिशिष्ट -2.5	₹ 10 लाख या अधिक की बचत(निधियों के उपयोग में कमी) / आधिक्य में परिणत निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	91
परिशिष्ट -2.6	वर्ष 2011-12 के दौरान किए गए भारी अभ्यर्पण	93
परिशिष्ट -2.7	भाग अः वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण *(₹ 50 लाख या अधिक)* भाग बः अन्तिम आधिक्य के बावजूद अभ्यर्पण	94/95
परिशिष्ट -2.8	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ 10 करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया	96
परिशिष्ट -2.9	₹ 1 करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया	97
परिशिष्ट -2.10	30/31 मार्च 2012 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण	99
परिशिष्ट -2.11	व्यय की तीव्रता	101
परिशिष्ट -2.12	वर्ष 2011-12 तक के लंबित डी. सी. बिल	103

परिशिष्ट - 3.1	विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखो के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण	104
परिशिष्ट -3.2	दुर्विनियोग, चोरी/हानि आदि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/अवधिवार विवरण (वे मामलें जिनमें मार्च 2012 के अन्त में अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी)	105
परिशिष्ट -3.3	चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्री की हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	106
परिशिष्ट -4.1	शब्दावली	107

प्राक्कथन

(1) यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

(2) इस प्रतिवेदन के अध्याय-1 में राज्य सरकार के 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के वित्त लेखे की जाँच से उत्पन्न प्रकरणों पर की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सम्मिलित हैं।

(3) इस प्रतिवेदन के अध्याय-2 में राज्य सरकार के 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न प्रकरणों पर की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सम्मिलित हैं।

(4) अध्याय-3 वित्तीय प्रतिवेदन कार्य पर वर्ष के दौरान सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजस्व एवं सामान्य खण्डों से सम्बंधित विभागों में विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के विषयनिष्ठ आकलन के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन का उद्देश्य राज्य सरकार को वास्तविक आँकड़ों से, जो सामयिक स्थिति पर आधारित हैं, अवगत कराना है ताकि सरकार के सुनिष्पादित एवं दुर्निष्पादित योजनाओं/कार्यक्रमों की बेहतर जानकारी हो सके। विश्लेषण पर परिदृश्य प्रस्तुत करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 तथा 2011-12 के बजट प्राक्कलन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की तुलना करने का प्रयास किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि म ले प) का प्रतिवेदन, एफ आर बी एम अधिनियम के पश्चात् पाँच वर्षों से अधिक से सरकार के वित्त पर टिप्पणियाँ की जा रही है और पाँच प्रतिवेदन पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं। चूंकि ये टिप्पणियाँ, सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अंश के रूप में थीं, ऐसा अनुभव किया गया कि राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के विशाल आकार में छुपे रूप से पड़े रहते थे। इस सद्-उद्देश्यपरक परन्तु सर्व-सम्मिलित प्रतिवेदन का प्रत्यक्ष परिणाम यह था कि इन निष्कर्षों के वित्तीय प्रबन्धन भाग को उचित ध्यानाकर्षण प्राप्त नहीं हुआ। एक बार फिर राज्य वित्त को प्रमुखता दिलाने की आवश्यकता को मान्यता मिलने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के वित्त पर एक पृथक प्रतिवेदन, इस चुनौती पर, समुचित लेखापरीक्षा प्रतिक्रिया माना गया है। तदनुसार, प्रतिवेदन वर्ष 2009 से, भारत के नि म ले प ने, "**राज्य वित्त पर प्रतिवेदन**" शीर्षक से एक पृथक खण्ड निकालने का निर्णय लिया। इस प्रयास में यह चौथा प्रतिवेदन है।

प्रतिवेदन

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष पर उत्तराखण्ड सरकार के लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा उपलब्ध कराता है। यह प्रतिवेदन, तीन खण्डों में है।

अध्याय 1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2012 को उत्तराखण्ड सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह, बजट से इतर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित केन्द्रीय निधियों के एक संक्षिप्त लेखे सहित वचनबद्ध व्यय में रुझान, ऋण लेने की पद्धति पर एक अन्तर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय 2 विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदान-वार विवरण एवं वह ढंग, जिससे सेवा उपलब्ध करने वाले विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों का प्रबन्धन किया गया, देता है।

अध्याय 3 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रतिवेदनीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन की सूची है। लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण संबंधी विवरण भी इस अध्याय में दिए गए हैं। इनके साथ ही, इस अध्याय में ऐसे मामलों का विस्तृत विवरण भी शामिल है जो सरकारी विभागों में दुर्विनियोग/हानि के अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है। प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न स्रोतों से एकत्र किये गये अतिरिक्त आँकड़े भी हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय सुधार पथ: उत्तराखण्ड, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम (एफ आर बी एम अधिनियम), 2005 पारित करने वाले शुरुआती राज्यों में एक है। उत्तराखण्ड राज्य ने वर्ष 2006-07 से आगे राजस्व आधिक्य प्राप्त करने के लक्ष्य की उपलब्धि प्राप्त की परन्तु इस प्रवृत्ति को नहीं बनाए रख सका तथा वर्ष 2009-10 में राजस्व घाटे में परिणत हुआ। तथापि, राज्य 2010-11 में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक लाने में कामयाब रहा। अंततः चालू वर्ष में (2011-12) राजस्व घाटा आधिक्य में बदल गया। राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा चार *प्रतिशत* (पुनरीक्षित) के निर्धारित लक्ष्य से नीचे जारी रहा, जैसा कि 2007-08 से एफ आर बी एम में परिकल्पित किया गया था। तथापि, राजकोषीय घाटे को भी 2010-11 के दौरान में कम करके तर्कसंगत सीमा (जी एस डी पी का 3.5 *प्रतिशत*) के अन्दर लाया गया था। चालू वित्त वर्ष के लिए ₹ 1757 करोड़ (जी एस डी पी का 1.85 *प्रतिशत*) का राजकोषीय घाटा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक से बहुत निम्न है।

पूँजीगत व्यय को उच्च प्राथमिकता: एफ आर बी एम अधिनियम में पूँजीगत व्यय के प्राथमिकीकरण के लिए कोई विशिष्ट मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। यद्यपि, राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 के बजट के साथ राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत अपने मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण में तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के प्रति वचनबद्धता की है जो यह व्याख्यान करता है कि वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटा जी एस डी पी का 3.5 *प्रतिशत* होना चाहिए, जिसे वर्ष 2013-14 तक पुनः कम करके 3 *प्रतिशत* तक लाया जाएगा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, राज्य सरकार को उधार कम लेना पड़ेगा और इससे निकट भविष्य में पूँजीकरण हेतु कम निधियाँ उपलब्ध होंगी। यद्यपि, चालू वित्त वर्ष में सरकार ने वर्ष 2010-11 की तुलना में 25 *प्रतिशत* अधिक निधियों के पूँजीकरण की व्यवस्था की।

यद्यपि इस वर्ष राज्य, राजस्व आधिक्य प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे को कम करने में कामयाब रहा लेकिन उधारियों (₹ 1,320 करोड़) के माध्यम से, घाटे के वित्तपोषण से बचने के लिए, घाटे की स्थिति पर नियन्त्रण रखने के प्रयास किये जाने चाहिए।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल गत तीन वर्षों में लगभग नगण्य (किए गए निवेश पर 0.02 *प्रतिशत*) था जबकि सरकार ने इस निवेश के लिए उधार ली गई निधियों पर 7.60 *प्रतिशत* की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।

सरकार को निवेशों में धन की बेहतर उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु ऐसी कम्पनियों/निगमों की पहचान करनी चाहिए, जो कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रतिफल देते हों और अपने उच्च लागत उधारियों के प्रतिस्थापन को सिद्ध करे।

ऋण वहन क्षमता: तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 में उत्तराखण्ड के लिए निर्धारित लक्ष्य (41.10 *प्रतिशत*) के सापेक्ष ऋण- जी एस डी पी[1] अनुपात ने 2008-09 से 2011-12 तक के 29 *प्रतिशत* से 24.80 *प्रतिशत* की निम्नोनमुखी प्रवृति दर्शायी।

[1] प्रचलित/बाजार दरों पर। हालांकि, पिछले प्रतिवेदनों में ऋण-जी एस डी पी अनुपात स्थिर, मूल्यों की जी एस डी पी पर आकलित किया जाता था।

वित्तीय वर्ष के अन्त में जमाव से बचने के लिये उधारियों की तिथिपत्र सुस्थापित रखना तथा ऋण भुगतानों की परिपक्वता की रूपरेखा की स्पष्ट समझ, विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन में दीर्घकालिक लाभ देंगे।

भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित निधियों की अनदेखी: यहाँ उपभोगित राशियों की निगरानी हेतु न तो कोई एकल अभिकरण है और न ही कोई तैयार आँकड़े उपलब्ध है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में किसी वित्तीय वर्ष विशेष में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली मुख्य झण्डारोही योजनाओं व अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं, जो भारत सरकार द्वारा सीधे वित्त पोषित है, के अन्तर्गत वास्तव में कितना व्यय हुआ है।

इन निधियों के उचित लेखांकन को सुनिश्चित करने के लिए किसी पद्धति को व्यवहार में लाना होगा और इसके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु अद्यतन सूचनाओं को राज्य सरकार तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा वैधता प्रदान की जानी चाहिये।

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियन्त्रण :

राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रियाएँ इस वर्ष के दौरान सुदृढ़ नहीं थीं जिसमें बजटीय त्रुटियाँ, निरन्तर बचत[2], आधिक्य, प्रावधान के बिना व्यय और चालू वित्त वर्ष में प्रतिपूर्ति किए बिना आकस्मिकता निधि से आहरण शामिल था। बहुत से प्रकरणों में प्रत्याशित बचत या तो अभ्यर्पित नहीं की गई या फिर साल के एकदम अन्त में मार्च महीने में अभ्यर्पित की गई जिससे अन्य विकास प्रयोजनों हेतु इन निधियों की उपलब्धता की कोई गुंजाइश नहीं बची। कई विभागों द्वारा आवश्यकता से अधिक आहरण, समुचित स्पष्टीकरण के बिना पुनर्विनियोग का आश्रय लेकर तथा निधियों के प्रावधान के बिना व्यय करके वित्तीय नियमों को ताक पर रख दिया गया था। वित्तीय वर्ष के अन्त में निधियों की अवमुक्ति तथा पर्याप्त निधियों का अभ्यर्पण चिन्ता का विषय है क्योंकि निधियों का सार्थक रुप से प्रयोग नहीं किया जा सका था।

[2] जिसको निधियों के उपयोग में कमी के रूप में भी बताया जा सकता है।

वित्तीय प्रबन्धन में ऐसी कमियों से बचने के लिये बजटीय नियन्त्रण को सख्ती से निगरानी किया जाना चाहिये। वित्तीय वर्ष के अन्त में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण आदेश जारी करने से बचा जाना चाहिए। आकस्मिक बिलों के सार के नियत समयावधि के दौरान समायोजन सुनिश्चित करने हेतु नियन्त्रण-अधिकारियों द्वारा एक नजदीकी एवं कठोर अनुश्रवण तंत्र व्यवहार में लाया जाना चाहिए।

वित्तीय प्रतिवेदन: विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं तथा विनिर्देशों का राज्य सरकार द्वारा किया गया अनुपालन असन्तोषजनक था जैसा कि ऋण एवं अनुदानों के विरूद्ध विभिन्न अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब से स्पष्ट है। कुछ विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा वार्षिक लेखा के प्रस्तुतीकरण में भी विलम्ब पाए गए थे। चोरी, हानि तथा दुर्विनियोग के प्रकरण भी थे।

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लम्बित वार्षिक लेखों के अन्तिमीकरण के लिए सरकारी विभागों को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये। दुर्विनियोग के प्रकरणों में दोषियों को दण्डित करने हेतु विभागीय जाँचों में तेजी लाएं।

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

उत्तराखण्ड का परिचय

उत्तराखण्ड, भारत सरकार द्वारा राज्यों के संवर्गीकरण पर आधारित विशेष श्रेणी राज्य (एस सी एस) है। उत्तराखण्ड को प्राप्त विशेषाधिकारों में भारत सरकार (भा स) द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है जिसका 90 *प्रतिशत* अंश अनुदान एवं 10 *प्रतिशत* ऋण का अनुपात होता है जो अविशेष श्रेणी राज्यों से भिन्न है जिन्हें 70 *प्रतिशत* ऋण एवं 30 *प्रतिशत* केन्द्रीय सहायता के अनुपात में केन्द्रीय अनुदान प्राप्त होता है।

इसके बावजूद, राज्य ने बीते दशक में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि देखी तथा वर्ष 2002-03 से 2011-12 तक की अवधि के लिए इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद[1] (स रा घ उ) प्रचलित दरों पर मिश्रित वार्षिक विकास दर 19.41 *प्रतिशत* रही **(परिशिष्ट-1)**।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (वर्ष 2000 का अधिनियम संख्या 29) के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 84,79,562 की जनसंख्या वाले 13 जिलों को नवीन उत्तराखण्ड राज्य के लिए 9 नवम्बर 2000 की गठन तिथि से स्थानान्तरित किया गया था। यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान उत्तराखण्ड सरकार के वित्त का विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के समस्त रुझान के दृष्टिगत, गत वर्ष से सम्बन्धित प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। राज्य सरकार के मुख्य राजकोषीय सकलों में बृहद परिवर्तन, वर्ष 2009-10 के राजस्व आधिक्य का राजस्व घाटे में परिवर्तित हो जाना था, जो पिछले वर्ष लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) हो गया और अंततः चालू वर्ष में राजस्व आधिक्य (₹ 716 करोड़) में परिवर्तित हो गया। चालू वर्ष में, राजकोषीय घाटा ₹ 1,757 करोड़ पर, जी एस डी पी के लगभग 1.85 *प्रतिशत* के आस-पास टिका रहा, जो कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक से काफी नीचे है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम 2005 (तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर मार्च 2011 में संशोधित) और राज्य की मध्यावधि राजकोषीय नीति (एम टी एफ पी) द्वारा, राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ (एफ सी पी) का सारांश **परिशिष्ट 1.2 (भाग ब)** में दिया गया है।

[1] परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेनदेन का सार

तालिका-1.1, गत वर्ष (2010-11) के सापेक्ष चालू वर्ष (2011-12) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेनदेन का सार प्रस्तुत करती है जबकि **परिशिष्ट-1.4** गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका-1.1

चालू वित्तीय वर्ष के राजकोषीय संचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण				
विभिन्न मदें	2010-11	2011-12	विभिन्न मदें	2010-11	2011-12		
	कुल	कुल		कुल	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	कुल
भाग-अः राजस्व							
राजस्व प्राप्तियाँ	**11,608.16**	**13,691.24**	राजस्व व्यय	**11,621.07**	10,654.11	2,321.08	**12,975.19**
कर राजस्व	4,405.47	5,615.62	सामान्य सेवाएँ	4,180.15	4,471.39	3.72	4,475.11
करेत्तर राजस्व	678.06	1,136.13	सामाजिक सेवाएँ	5,169.49	4,368.07	1,651.58	6,019.65
संघीय करों/शुल्कों का अंश	2,460.07	2,866.04	आर्थिक सेवाएँ	1,863.75	1,435.85	665.78	2,101.63
भारत सरकार से अनुदान	4,064.56	4,073.45	सहायता अनुदान और अंशदान	407.68	378.80	-	378.80
भाग -बः पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	पूँजीगत परिव्यय	**1,854.84**	245.94	2,071.00	**2,316.94**
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**84.87**	**90.65**	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	**59.68**	13.79	233.04	**246.83**
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	**2,427.18**	**2,335.52**	लोक ऋणों की चुकौत्तियाँ*	**519.36**	--	--	**1,015.78**
--	--	--	आकस्मिकता निधि को विनियोग**	**515.00**	--	--	**(-)400.00**
आकस्मिकता निधि	**581.62**	**126.13**	आकस्मिकता निधि	**536.71**	--	--	**69.07**
लोक लेखा प्राप्तियाँ	**18,703.51**	**19,668.05**	लोक लेखा संवितरण	**17,608.18**	--	--	**19,832.00**
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	**538.91**	**1,229.41**	अंतिम रोकड़ शेष	**1,229.41**	--	--	**1,085.19**
योग	**33,944.25**	**37,141.00**	**योग**	**33,944.25**	--	--	**37,141.00**

** इसमें अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अधीन निवल लेनदेन शामिल नहीं हैं।*

*** ₹ 85 करोड़ का आकस्मिक संग्रह निधि, 2010-11 के दौरान ₹ 515 करोड़ करके बढ़ा दिया था तथा 2011-12 के दौरान ₹ 400 करोड़ करके कम कर दिया तथा 2011-12 के अंत तक ₹ 200 करोड़ पर स्थित था।*

इस प्रकार यह विदित होगा कि:

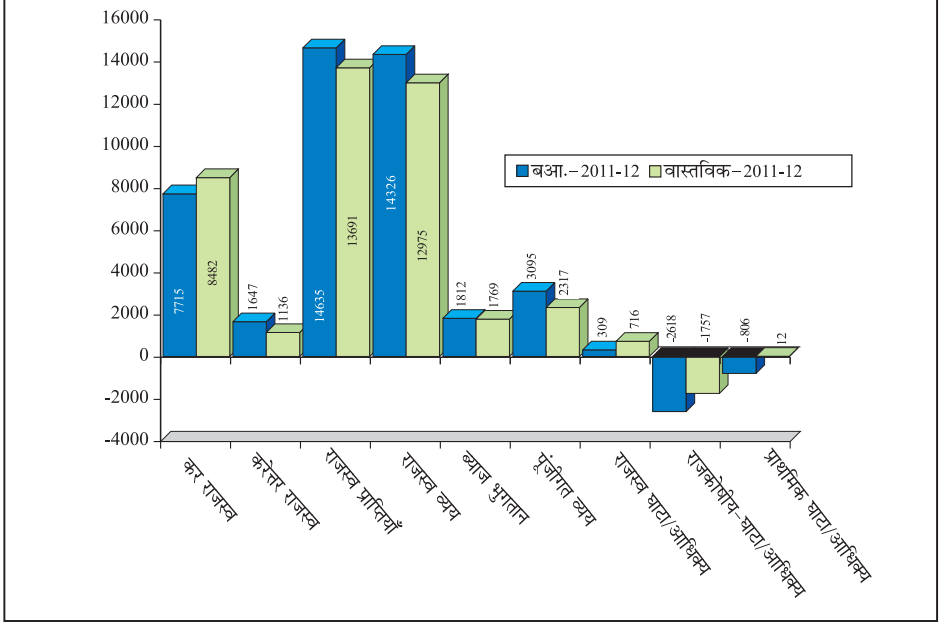
- राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष के सापेक्ष ₹ 2,083 करोड़ (17.94 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 1,210 करोड़), करेत्तर राजस्व (₹ 458 करोड़) और संघ के करों/शुल्कों में राज्य के अंश (₹ 406 करोड़) में बढ़ोतरी के कारण थी।
- पिछले साल के सापेक्ष इस वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 1,354 करोड़ (11.65 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई, जैसा कि अनुवर्ती **प्रस्तर-1.4.1** में वर्णित है।
- पिछले साल के सापेक्ष इस वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में गत वर्ष से ₹ 462 करोड़ (24.91 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जैसा कि अनुवर्ती **प्रस्तर 1.4.1** में वर्णित है।
- ऋण एवं अग्रिमों की वसूली ₹ 85 करोड़ (2010-11) से बढ़कर ₹ 91 करोड़ (6.81 *प्रतिशत*) हो गयी। वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों के वितरण ₹ 187 करोड़ बढ़े (₹ 60 करोड़ से ₹ 247 करोड़) जो मुख्यतः यातायात (₹ 100 करोड़) और ऊर्जा क्षेत्र (₹ 71 करोड़) को अधिक वितरण के कारण हुआ।
- वर्ष 2011-12 के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 92 करोड़ की कमी दर्ज हुई।
- उचन्त एवं विविध (₹ 906 करोड़) तथा आरक्षित निधि (₹ 496 करोड़) के अन्तर्गत वृद्धि के कारण लोक लेखा प्राप्तियाँ ₹ 965 करोड़ बढ़ गई। यह प्रेषण (₹ 204 करोड़), जमा एवं अग्रिम (₹ 133 करोड़) और लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 100 करोड़) में कमी से प्रतिसंतुलित हुई। उचन्त एवं विविध (₹ 1,650 करोड़), आरक्षित निधियाँ (₹ 592 करोड़) और लघु बचतें, भविष्य निधि (₹ 143 करोड़) में वृद्धि के कारण लोक लेखा संवितरण ₹ 2,224 करोड़ **(परिशिष्ट-1.4)** बढ़ गया जो प्रेषण (₹ 41 करोड़) और जमा एवं अग्रिम (₹ 120 करोड़) में कमी से प्रतिसंतुलित हुआ।
- वर्ष 2010-11 के अन्तिम अवशेष की तुलना में वर्ष के अन्त में राज्य का रोकड़ शेष ₹ 144.22 करोड़ कम हो गया।

राजकोषीय घाटा, जो वर्ष 2010-11 में ₹ 1,843 करोड़ था, घटकर ₹ 1,757 करोड़ (स रा घ उ का 1.85 *प्रतिशत*) तक नीचे आ गया, जिससे कि राज्य की राजकोषीय दशा में और सुधार हुआ। वर्ष 2011-12 में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक नीचे लाने के पश्चात, मुख्यत: राज्य की राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,669 करोड़ की वृद्धि करने के कारण - जो 2010-11 के ₹ 5,083 करोड़ से 2011-12 में ₹ 6,752 करोड़ हो गयी- सरकार चालू वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 716 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त करने में सफल हुई।

बजट आकलनों के वास्तविक वसूलियों/व्यय से विचलन के अनेक कारण हो सकते हैं। यह बजट बनाने के अवसर पर घटनाओं का पूर्वाभ्यास या अनुमान न होना अथवा व्यय या राजस्व के कम/अधिक आकलन के कारण हो सकता है। यद्यपि, राजस्व की वास्तविक वसूली एवं इसका संवितरण, विविध कारकों, कुछ

आन्तरिक और वाह्य, पर आधारित होता है। **चार्ट 1.1** कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों हेतु बजट आकलन (ब आ) एवं वास्तविक आँकड़े प्रस्तुत करता है।

चार्ट- 1.1: चयनित राजकोषीय मापदण्ड: वास्तविक आँकड़ो के सापेक्ष बजट आकलन (₹ करोड़ में)



2011-12 के दौरान, विभिन्न घटकों के सम्बन्ध में बजट आकलनों के सापेक्ष वास्तविक की तुलना ने मिश्रित रूझान को दर्शाया:

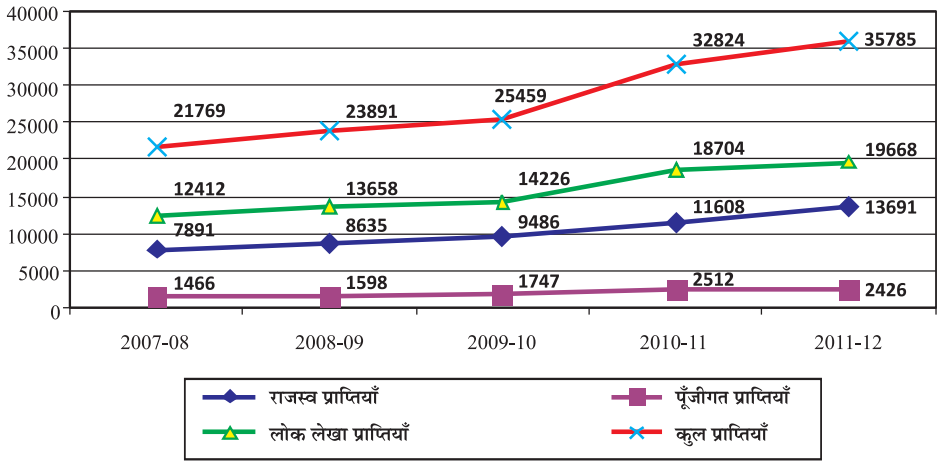
- सहायता अनुदान के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति ₹ 1,200 करोड़ (23 *प्रतिशत*) के कारण समग्र राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 944 करोड़ कम थी। यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में करेत्तर राजस्व ने सीधे चढ़ाव दर्शाया, वह चालू वर्ष के बी ई के सापेक्ष ₹ 511 करोड़ (31 *प्रतिशत*) कम था, जबकि राज्य का कर राजस्व बी ई के मुकाबले ₹ 767 करोड़ (10 *प्रतिशत*) अधिक था।
- राजस्व व्यय वर्ष के बजट आकलनों से ₹ 1,351 करोड़ (9 *प्रतिशत*) कम था।
- मुख्यत: शिक्षा, ऊर्जा और पर्यटन के अन्तर्गत कम संवितरण के कारण पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत व्यय ₹ 778 करोड़ (25 *प्रतिशत*) तक अप्रयुक्त रहा।
- राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे तथा प्रारम्भिक घाटे के लिये वर्ष 2011-12 के बजटीय मुख्यानुमान, बजटीय लक्ष्यों के बहुत उपर तथा एफ आर बी एम, अधिनियम 2005 (2010-11 में संशोधित) तथा ते वि आयोग संस्तुतियों के बराबर थे **(चार्ट-1.1)**।

1.2 राज्य के संसाधन

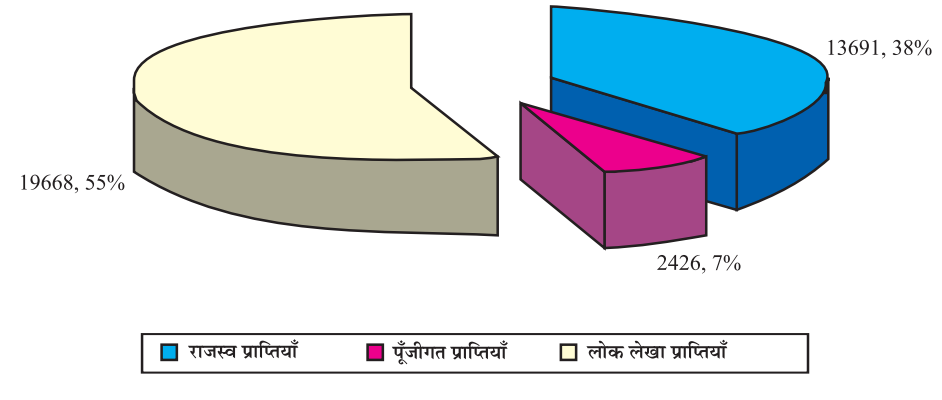
1.2.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजी प्राप्तियाँ तथा लोक लेखा प्राप्तियाँ-कुल प्राप्तियों की तीन स्रोत हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों को गठित करती है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय कर एवं शुल्कों में राज्य का अंश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत राजस्व प्राप्तियाँ- जैसे विनिवेशों से उत्पन्न आय, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/ वाणिज्यिक बैंकों से लिया गया ऋण) से ऋण की प्राप्तियाँ तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। प्राप्ति के अन्य क्षेत्र लोक लेखे से संग्रहण हैं। **तालिका 1.1** चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जैसा इसके वार्षिक वित्तीय लेखे **(परिशिष्ट-1.1)** में अभिलेखित है; जबकि **चार्ट 1.2,** वर्ष 2007-12 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों का चित्रण करता है। **चार्ट 1.3** चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटकों को चित्रित करता है।

चार्ट- 1.2: प्राप्तियों की प्रवृत्ति



चार्ट- 1.3: वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्तियों की संरचना *(₹ करोड़ में)*



वर्ष 2007-08 में सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 21,769 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 35,785 करोड़ (64.39 *प्रतिशत*) हो गयी। वर्ष 2011-12 की ₹ 35,785 करोड़ की प्राप्तियों में से 54.96 *प्रतिशत* प्राप्तियाँ लोक लेखे से थी जबकि कुल प्राप्तियों का 38.26 *प्रतिशत* व 6.78 *प्रतिशत* भाग राजस्व प्राप्तियों व उधारों आदि से आया।

गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 17.94 *प्रतिशत* बढ़ गईं। पिछले वर्ष की वृद्धि 22 *प्रतिशत* थी और राज्य की प्राप्तियों में इसके संघटक में अल्पवृद्धि (2.89 *प्रतिशत*) प्रदर्शित हुई। यद्यपि, पूँजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत इस वर्ष ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली ने गत वर्ष की तुलना में 6.81 *प्रतिशत* वृद्धि प्रदर्शित की, जबकि पिछले वर्ष की वृद्धि 30.91 *प्रतिशत* थी (**तालिका-1.1 में संदर्भित**)।

लोक लेखा प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

- लघु बचत, भविष्य निधि आदि के अन्तर्गत प्राप्तियाँ, विगत वर्ष की तुलना में ₹ 100 करोड़ भविष्य निधि में कम प्राप्तियों के कारण घट गई थीं।
- गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान आरक्षित निधियाँ ₹ 496 करोड़ बढ़ गईं। यद्यपि, जमा व अग्रिम में ₹ 133 करोड़ की कमी हुई। आन्तरिक ऋण के परिशोधन हेतु शोधन निधि में राज्य सरकार का निवेश (₹ 25 करोड़) एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में निर्धारित मानकीय आँकड़ों (गत वर्ष की समाप्ति पर खुले बाजार ऋणों के बकाए का तीन *प्रतिशत* अर्थात ₹ 217 करोड़) से कम था, परिणामस्वरूप आरक्षित निधियों के अन्तर्गत प्राप्तियों में ₹ 192 करोड़ की कमी हुई।
- उचन्त एवं विविध प्राप्तियाँ (₹ 897 करोड़) वर्ष के दौरान मुख्यतः चेकों एवं देयकों हेतु उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत हुई वृद्धि के कारण, ₹ 906 करोड़ (7.91 *प्रतिशत*) से बढ़ गई। यह उचन्त शीर्ष, चेकों के जारी करते समय जमा दिखाया जाता है तथा चेकों के नकदीकरण के बारे में बैंक से सूचना की प्राप्ति पर उसे समाशोधित किया जाता है।

1.2.2 राज्य के बजट से इतर राज्य के क्रियानव्यन अभिकरणों को अन्तरित निधियाँ

केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माने गये विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रिर्यान्वयन हेतु राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों[2] को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियाँ अन्तरित की जाती हैं। ये निधियाँ, राज्य बजट/राज्य कोषागार तन्त्र के माध्यम से नहीं आती हैं। अतः राज्य की प्राप्तियाँ एवं व्यय तथा इसके साथ-साथ उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय आँकड़े/मापदण्ड अधो-आंकलित रहे। समुच्चय संसाधनों की उपलब्धता पर एक निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करने के लिए, राज्य के क्रियानव्यन अभिकरणों को सीधे तौर पर अन्तरित निधियाँ **परिशिष्ट-1.5** में दर्शायी गयी हैं। बृहद कार्यक्रमों/योजनाओं को अन्तरित महत्वपूर्ण धनराशि **तालिका 1.2** में दर्शायी गई है।

[2] परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

तालिका-1.2

राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियों की महत्वपूर्ण धनराशियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना के कार्यक्रम का नाम	क्रियान्वयन अभिकरण का नाम	वर्ष 2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा अवमुक्त कुल निधियाँ
1.	आजीविका	डी आर डी ए और पी एम यू	22.12
2.	प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास योजना	राज्य साक्षरता अभियान	28.47
3.	स्वायत्त संस्थान एवं व्यावसायिक निकाय	वाडिया हिमालयन भू-विज्ञान संस्थान	46.96
4.	टी एच डी सी इण्डिया लिमिटेड में इक्विटी बढ़ाना	टी एच डी सी लिमिटेड	45.00
5.	वन एवं वन्य प्राणी संस्थाओं को सहायता अनुदान	एफ आर आई और डब्ल्यू आई आई	116.07
6.	आई आई टी डी एच ई(ओ एस सी समेत)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	120.00
7.	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	डी आर डी ए	373.51
8.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	डी एम	28.00
9.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम	एस डब्लयू एस एम उत्तराखण्ड	75.57
10.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	131.18
11.	विशेष श्रेणी राज्यों (उत्तर पूर्व के अलावा) के लिए पैकेज	सिडकुल	75.51
12.	इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलेपमेन्ट फॉर डेस्टिनेशनस् एन्ड सर्किट्स	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद	75.53
13.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा मा शि अ)	उत्तराखण्ड सब के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद	34.07
14.	जल स्रोत अनुसंधान और विकास	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	8.57
15.	ग्रामीण आवास (इ आ ओ)	डी आर डी ए	58.29
16.	सर्व शिक्षा अभियान	उत्तराखण्ड सब के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद	208.92
17.	पी पी पी के द्वारा 1396 आई टी आई्यों का उच्चीकरण	आई टी आई की आई एम सी समिति	35.00
18.	औषधि निर्मात्री प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण	आई एम पी सी लिमिटेड	24.00
योग			**1,506.77**

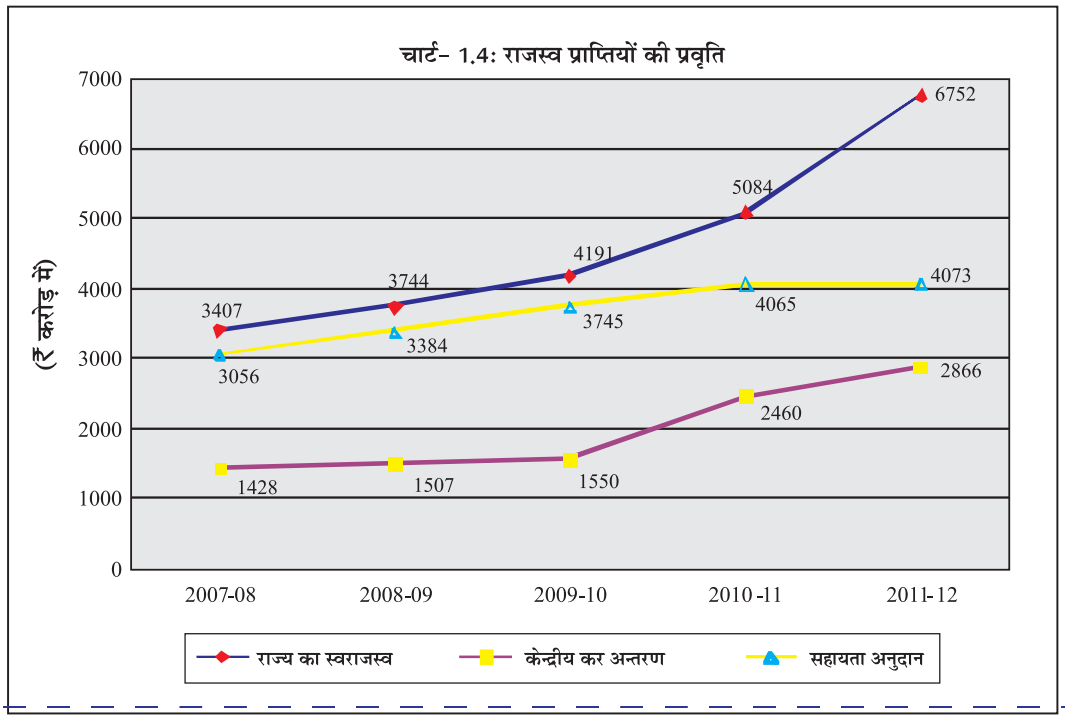
स्रोतः कन्ट्रोलर जनरल ऑफ एकाउन्टस वैबसाइट का सेण्ट्रल प्लान योजना मानिटिरिंग सिस्टम

तालिका 1.2 सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के अधीन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के विविध मंत्रालयों से उत्तराखण्ड में विभिन्न अभिकरणों द्वारा सीधे प्राप्त महत्वपूर्ण राशियों की निधियों को दर्शाती हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान इन निधियों का अधिकांश अंश प्राप्त करने वाले कार्यक्रम (i) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना- ₹ 373.51 करोड़ (18.31 *प्रतिशत*), (ii) सर्व शिक्षा अभियान- ₹ 208.92 करोड़ (10.24 *प्रतिशत*), (iii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ₹ 131.18 करोड़ (6.43 *प्रतिशत*), (iv) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ₹ 75.57 करोड़ (3.70 *प्रतिशत*), (v) वन व वन्य प्राणी संस्थाओं को सहायता अनुदान ₹ 116.07 करोड़ (5.69 *प्रतिशत*), (vi) विशेष श्रेणी राज्यों (उत्तर पूर्व के अलावा) ₹ 75.51 करोड़ (3.70 *प्रतिशत*) तथा (vii) इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलेपमेन्ट फॉर डेस्टिनेशनस् एन्ड सर्किट्स ₹ 75.53 करोड़ (3.70 *प्रतिशत*) थे। इस प्रकार, वर्ष 2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 2040 करोड़ **(परिशिष्ट-1.5)** के अन्तरण से, राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹ 35,785 करोड़ से बढ़कर ₹ 37,825 करोड़ हो गयी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा सीधे क्रियान्वयन अभिकरणों को स्थानान्तरित निधियों के अनुश्रवण हेतु कोई एकल अभिकरण उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार तत्काल रूप से कोई आँकडे उपलब्ध नहीं हैं जिससे ज्ञात हो कि किसी विशेष वर्ष में चिन्हित योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं जिन्हें राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है पर वास्तविक रूप से व्यय की गयी निधि कितनी है।

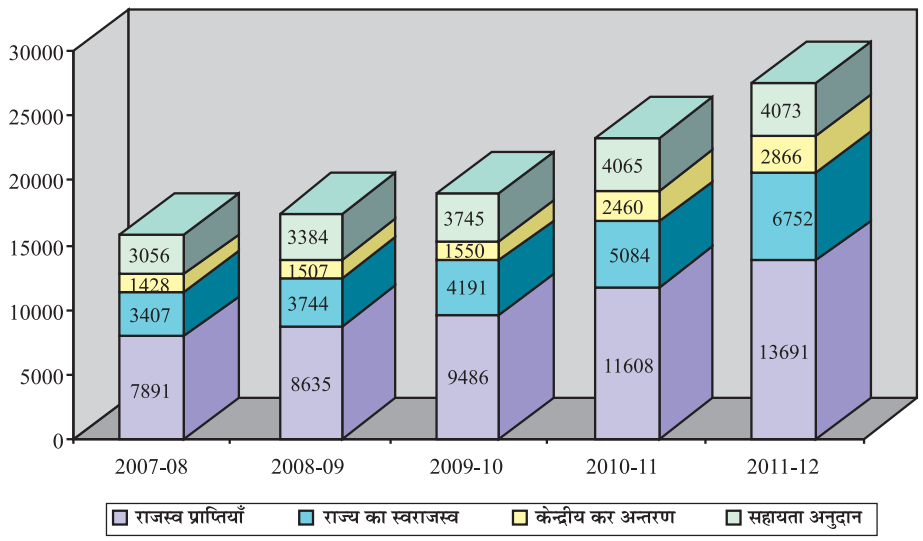
1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे की **विवरणी-11**, सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करती है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों के संघटक और प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट-1.3** में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमशः चार्ट **1.4** तथा **1.5** में भी चित्रित किया गया है।

चार्ट- 1.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति



चार्ट- 1.5: राजस्व प्राप्तियों के घटक (₹ करोड़ में)



राजस्व प्राप्तियों ने 2007-08 से 2011-12 की अवधि में निरंतर वृद्धि दर्शाई। यह 13.32 *प्रतिशत* की औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2007-08 में ₹ 7,891 करोड़ से वर्ष 2011-12 में बढ़कर ₹ 13,691 करोड़ हो गयी।

केन्द्रीय कर अन्तरणों एवं सहायता अनुदान के समुच्चय का कुल राजस्व में 50.68 *प्रतिशत* योगदान रहा जबकि वर्ष 2011-12 के दौरान 49.32 *प्रतिशत* राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के निजी कर एवं करेत्तर राजस्व से हुईं।

औसतन, वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि में राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 44.77 *प्रतिशत* योगदान स्वयं राज्य की निजी कर प्राप्तियों का रहा **(चार्ट 1.5)**। इससे भारत सरकार से सहायता अनुदान पर राज्य की निरन्तर निर्भरता दर्शित हुई, क्योंकि राज्य अपने कर-आधार को विस्तृत करने में अक्षम रहा।

स रा घा उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को निम्न **तालिका-1.3** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-1.3:

स रा घा उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा) *(₹ करोड़ में)*	**7,891**	**8,635**	**9,486**	**11,608**	**13,691**
रा प्रा की वृद्धि दर *(प्रतिशत)*	7.03	9.43	9.86	22.37	17.94
रा प्रा / स रा घा उ *(प्रतिशत)*	17.21	15.41	13.32	14.08	14.38
उत्प्लावकता अनुपात[3]					
स रा घा उ के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	0.29	0.43	0.37	1.36	1.16
स रा घा उ के संदर्भ में राज्य के स्वंय के करों की उत्प्लावकता	0.37	0.50	0.64	1.45	1.78

[3] परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शाई। वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान वृद्धि दर लगभग स्थिर थी, लेकिन वर्ष 2010-11 में पुन: 22.37 *प्रतिशत* बढ़ गयी। वर्ष 2011-12 की वृद्धि दर में 4.43 *प्रतिशत* की कमी दर्ज हुई और 17.94 *प्रतिशत* पर रही। स रा घा उ के संदर्भ में राज्य के निजी करों की उत्प्लावकता अनुपात वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान एक से भी नीचे थी और 2010-11 में वृद्धि दर्शायी। तथापि पिछले वर्ष की तुलना में, चालू वर्ष में, स रा घा उमें वृद्धि के सापेक्ष वृद्धित कर राजस्व उगाही दर्शाती हुई राज्य के निजी कर पुन: उच्चत्तर उत्पलावकता, दिखाई। वर्ष 2011-12 में, स रा घा उ में प्रत्येक एक *प्रतिशत* के वृद्धि के लिए राज्य के निजी कर 1.78 *प्रतिशत* पर वृद्धित हुए।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों, केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण तथा आयोजनागत योजनाओं आदि हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता के आधार पर किया जाता है, अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का निर्धारण इसके अपने स्रोतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें निजी कर एवं करेत्तर स्रोतों से प्राप्त राजस्व समाविष्ट हैं।

कर राजस्व

कर राजस्व वर्ष 2010-11 के ₹ 4,405 करोड़ से 27.49 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 5,616 करोड़ हो गया। व्यापार, बिक्री आदि से प्राप्त कर ने न केवल कर राजस्व के एक बड़े अंश (65 *प्रतिशत*) के रूप में योगदान दिया अपितु गत वर्ष की तुलना में 24 *प्रतिशत* की वृद्धि भी दर्ज की।

करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व (एन टी आर) वर्ष 2008-09 में थोड़ा सा सुधार दिखाने के उपरान्त, वर्ष 2009-10 में 10 *प्रतिशत* कम हुआ। तथापि वर्ष 2010-11 के दौरान एन टी आर पुन: 7.28 *प्रतिशत* मूल्य वर्द्धित हुआ। वर्ष 2011-12 के दौरान, यह, महत्वपूर्ण रूप से 67.56 *प्रतिशत* बढ़ा। करेत्तर राजस्व ₹ 1,136 करोड़ पर राजस्व प्राप्तियों का 8.30 *प्रतिशत* था।

एन टी आर में महत्वपूर्ण बढ़त पूर्ववर्ती सम्मिश्र राज्य उत्तर प्रदेश के पेंशन देयताओं का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के मध्य प्रभाजन के कारण था। परिणामत: उत्तराखण्ड राज्य को, उत्तर प्रदेश से ₹ 400 करोड़ प्रभाजन के रूप में प्राप्त हुए।

वर्ष 2011-12 के दौरान करेत्तर राजस्व के प्रमुख अंशदाताओं में वानिकी एवं वन्य जीव (₹ 234 करोड़), अलौह एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 113 करोड़) एवं ब्याज प्राप्तियाँ (₹ 51 करोड़) सम्मिलित थे। वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 की अवधि में एन टी आर में ब्याज प्राप्तियों का औसत योगदान 7.38 *प्रतिशत* था।

तालिका-1.4: वास्तविक आँकड़ों के सापेक्ष अनुमान/निर्धारण की तुलना

(₹ करोड़ में)

मुख्य रजकोषीय परिवर्तियाँ	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किया गया निर्धारण	एफ सी पी में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्धारण	*प्रतिशत* (एफ सी पी बनाम ते वि आ के निर्धारण)	वास्तविक आँकड़े	*प्रतिशत* (वास्तविक बनाम एफ सी पी मुख्यानुमान)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राज्य का स्व राजस्व	4,848	4,760	98	5,616	118
करेत्तर राजस्व	893	1,647	184	1,136	69

स्रोतः तेरहवें वित्त आयोग की प्रतिवेदन, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन (उत्तराखण्ड शासन) व वित्त लेखे

जैसा कि **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) द्वारा मुख्य अनुमानों की तुलना में राज्य के अपने संसाधन से यह प्रकट हुआ कि वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 5,616 करोड़ का कर राजस्व, वर्ष हेतु ते वि आ द्वारा किये गये ₹ 4,848 करोड़ के मानकीय निर्धारण को पार कर गया।

राज्य के अपने कर राजस्व वर्ष के दौरान भी राजकोषीय सुधार पथ (एफ सी पी) में राज्य सरकार द्वारा परिलक्षित लक्ष्य ₹ 856 करोड़ बढ़े और मध्यावधि राजकोषीय पथ विवरण (एम टी एफ पी एस) में निर्धारित लक्ष्य (₹ 5,582 करोड़) के लगभग बराबर रहे।

₹ 1136 करोड़ पर एन टी आर भी ते वि आ के मुख्य अनुमानों की तुलना में ₹ 243 करोड़ अधिक था। यद्यपि, एन टी आर के अधीन वास्तविक प्राप्ति एफ सी पी की तुलना में ₹ 511 करोड़ कम थी लेकिन एम टी एफ पी एस (₹ 1,044 करोड़) की तुलना में 92 करोड़ अधिक थी।

केन्द्रीय कर अन्तरण

संघीय करों तथा शुल्कों के राज्यांश के रूप की प्राप्तियाँ, 2010-11 के ₹ 2,460 करोड़ से 16.50 *प्रतिशत* बढ़कर 2011-12 में ₹ 2,866 करोड़ हो गयी थीं। केन्द्रीय अन्तरण में समग्र वृद्धि (₹ 406 करोड़), मुख्यतः निगम कर (₹ 167 करोड़), सेवा कर (₹ 97 करोड़), सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर कर (₹ 76 करोड़) और निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 65 करोड़) पर हुई वृद्धि के कारण थी।

सहायता अनुदान

वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 **(चार्ट 1.5)** की अवधि में भारत सरकार से सहायता अनुदान ने वृद्धि दर्शायी थी। यह वर्ष 2007-08 में ₹ 3,056 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 4,073 करोड़ हो गयी। चालू वर्ष के दौरान नाममात्र वृद्धि (₹ 9 करोड़) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के योजनागत स्कीमों (₹ 587 करोड़) और केन्द्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदानों (₹ 106 करोड़) में वृद्धि के कारण थी, जो विभिन्न आयोजनेतर अनुदानों (₹ 673 करोड़) और केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदानों (₹ 11 करोड़) से प्रतिसंतुलित हुई।

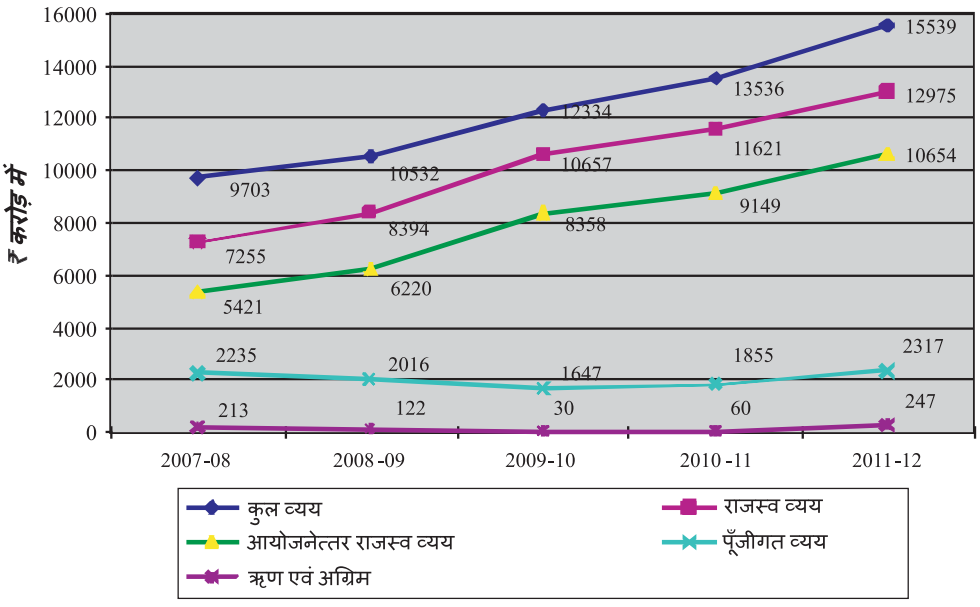
1.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रमुख व्यय दायित्व राज्य सरकार के सुपुर्द होते हैं। राजकोषीय दायित्व विधायन के ढांचे के अन्तर्गत, घाटे अथवा उधार द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय अवरोध होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया विशेषकर विकासपरक और सामाजिक क्षेत्रों की ओर उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो। व्यय के आवंटन के विश्लेषण पर चर्चा नीचे की गई है:

1.4.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.6 पाँच वर्षों (2007-08 से 2011-12) की अवधि में कुल व्यय के संघटकों को दर्शाता है तथा इनके संघटकों को 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'क्रियाकलापबद्ध व्यय' दोनों के सन्दर्भ में क्रमशः **चार्ट 1.7 एवं 1.8** में चित्रित किया गया है।

चार्ट 1.6: कुल व्यय: प्रवृत्तियाँ एवं संघटक



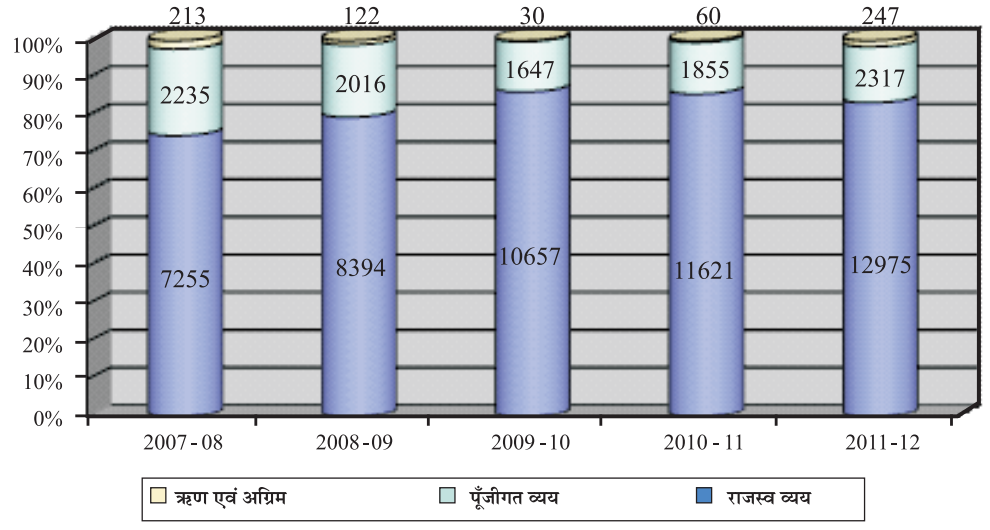
राज्य का कुल व्यय (टी ई): वर्ष 2007-12 के दौरान 13.48 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की औसत दर पर बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान कुल व्यय में ₹ 2,003 करोड़ (14.80 *प्रतिशत*) की बढ़ोतरी राजस्व व्यय व पूँजीगत व्यय में क्रमशः ₹ 1,354 करोड़ व ₹ 462 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। ऋण व अग्रिमों का संवितरण भी ₹ 187 करोड बढ़ा।

राजस्व व्यय (आर ई): चालू वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि (₹ 1,354 करोड़) (i) सामान्य सेवाओं (₹ 295 करोड़), (ii) सामाजिक सेवाओं (₹ 850 करोड़), (iii) आर्थिक सेवाओं (₹ 238 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई जो कि सहायता अनुदान एवं अंशदान (₹ 29 करोड़) में कमी से प्रतिसंतुलित हुई।

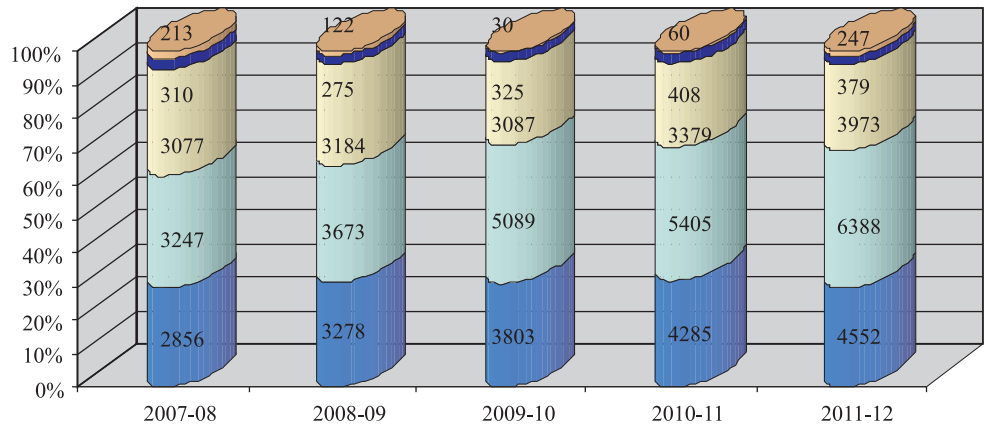
पूँजीगत व्यय : पूँजीगत व्यय में वर्ष के दौरान वृद्धि (₹ 462 करोड़) (i) सामाजिक सेवाओं (₹ 134 करोड़) तथा (ii) आर्थिक सेवाओं (₹ 356 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। जो सामान्य सेवाओं में (₹ 28 करोड़) कटौती से प्रतिसंतुलित हुई। कुल व्यय के *प्रतिशत* के रूप में इसने वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के दौरान विचलन-शील प्रवृत्ति दर्शाई जो वर्ष 2007-08 में 23.03 *प्रतिशत* तथा वर्ष 2011-12 में 14.91 *प्रतिशत* था। पूँजीगत व्यय में 2008-09 और 2009-10 में कमी हुई लेकिन पिछले दो वर्षों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाई और चालू वर्ष में ₹ 2,317 करोड़ पर रहा। तथापि वास्तविक व्यय, राज्य सरकार द्वारा उनके एफ सी पी (₹ 3,095 करोड़) तथा एम टी एफ पी एस (₹ 2,524 करोड़) में परिकल्पित लक्ष्य (₹ 3,095 करोड़) के नीचे था।

व्यय के इन घटकों का सापेक्ष अंश हाल ही (2009-12) में अपरिवर्तित रहा। गैर विकासात्मक समझे जाने वाले ब्याज भुगतानों सहित सामान्य सेवाओं पर व्यय का अंश वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 के दौरान लगभग स्थिर रहा। सामाजिक सेवाओं का व्यय वर्ष 2010-11 के 40 *प्रतिशत* से थोड़ा बढ़कर वर्ष 2011-12 में 41 *प्रतिशत* हो गया। आर्थिक सेवाओं ने वर्ष 2007-08 से वर्ष 2010-11 की अवधि में घटने की प्रवृत्ति दर्शाई और 2011-12 में लगभग अपरिवर्तित बना रहा।

चार्ट- 1.7: कुल व्यय: इसके घटकों के अंश में प्रवृत्तियाँ *(₹ करोड़ में)*



चार्ट- 1.8: कुल व्यय: क्रियाकलापों की प्रवृत्तियाँ *(₹ करोड़ में)*



राज्य का **राजस्व व्यय,** 15.07 *प्रतिशत* की औसत वार्षिक दर से 2007-08 से 2011-12 के दौरान 78.84 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 7,255 करोड़ से ₹ 12,975 करोड़ हो गया।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान राज्य का **आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (एन पी आर ई)** 96.53 *प्रतिशत* बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान, एन पी आर ई में वृद्धि (₹ 1,505 करोड़) मुख्यतः वेतन (₹ 507 करोड़), ब्याज अदायगियों, (₹ 289 करोड़) और सहायतानुदानों (₹ 176 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

राज्य के राजस्व व्यय में **आयोजनागत राजस्व व्यय (पी आर ई)** के अंश में 2007-09 के दौरान लगभग स्थिरता बनी रही, लेकिन वर्ष 2009-10 से अनुगामी वर्षों में ह्रासोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शाई। इसकी अपनी वृद्धि दर भी चालू वर्ष में कमीमान (6.11 *प्रतिशत*) रही। चालू वर्ष के दौरान पी आर ई में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 151 करोड़ की कमी मुख्यतः शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति (₹ 104 करोड़), जलापूर्ति एवं स्वच्छता (₹ 97 करोड़) और ग्राम्य विकास (₹ 123 करोड़) के अन्तर्गत व्यय के कारण थी। यह सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार (₹ 89 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 44 करोड़) तथा कृषि (₹ 58 करोड़) के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि से भागीय रुप से प्रतिसंतुलित हुई।

पुनः वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए नीचे **तालिका 1.5** वास्तविक एन पी आर ई का राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर किये गये अनुमानों के संदर्भ में ब्यौरा देती हैं।

तालिका-1.5

वर्ष 2011-12 के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

आयोजनेत्तर व्यय (एन पी आर ई)	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारण	राज्य सरकार द्वारा निर्धारण		
		एफ सी पी	एम टी एफ पी एस	वास्तविक
	7,920	12,803	13,153	10,654

स्रोतः तेरहवें वित्त आयोग की प्रतिवेदन, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन (उत्तराखण्ड शासन) व वित्त लेखे

चालू वर्ष के दौरान एन पी आर ई, (₹ 10,654 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग (₹ 7,920 करोड़) द्वारा निर्धारित मानकीय निर्धारण से ₹ 2,734 करोड़ (34.52 *प्रतिशत)* अधिक हो गया किन्तु यह क्रमशः राजकोषीय सुधार पथ (₹ 12,803 करोड़) और मध्यकालिक राजकोषीय नीति (₹ 13,153 करोड़) में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित प्रक्षेपण से कम था।

1.4.2 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन और पारिश्रमिक पर व्यय, पेंशन और उपदान शामिल होते हैं। **तालिका 1.6** और **चार्ट 1.9** वर्ष 2007-12 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं।

तालिका-1.6:

वचनबद्ध व्यय के घटक

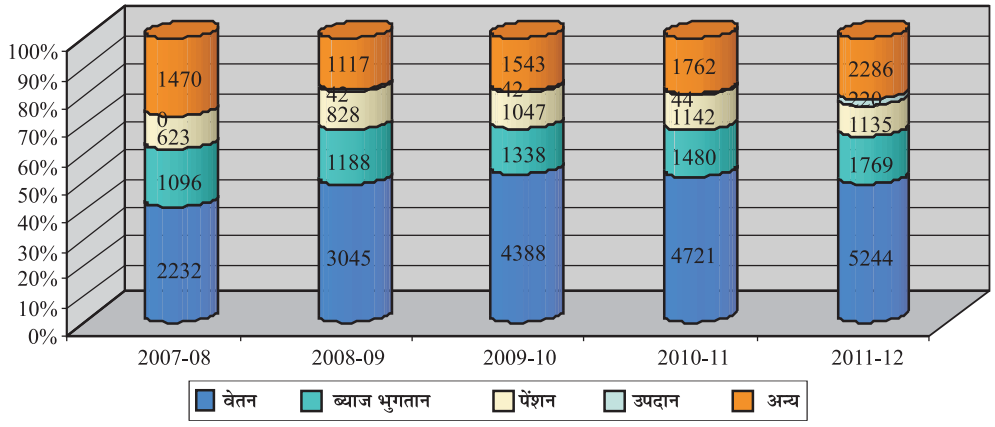
(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12		
					बी ई	वास्तविक	भिन्नता का *प्रतिशत*
वेतन और पारिश्रमिक जिसमें	2,232	3,045 (*35*)	4,388 (46)	4,721 (41)	5,308	5,244	(-) 1.22
आयोजनेत्तर शीर्ष	2,020	2,728	4,114	4,464		4,971	
योजनागत शीर्ष*	212	317	274	257		273	
ब्याज भुगतान	1,096	1,188 (*14*)	1,338(14)	1,480 (13)	1,812	1,769	(-) 2.37
पेंशन पर व्यय	623	828 (*10*)	1,047(11)	1,142 (10)	1,392	1,135	(-) 18.46
उपदान	…	42 (*0.50*)	42(0.44)	44	351	220	(-) 37.32
कुल वचनबद्ध व्यय	**3,951**	**5,103**	**6,815**	**7,387**	**8,863**	**8,368**	(-) 5.59
अन्य घटक	1,470	1,117	1,543	1,762	2,282	2,286	--
कुल एन पी आर ई	**5,421**	**6,220**	**8,358**	**9,149**	**11,145**	**10,654**	--
कुल राजस्व व्यय	**7,255**	**8,394**	**10,657**	**11,621**	**14,326**	**12,975**	**--**
राजस्व प्राप्तियाँ	**7,891**	**8,635**	**9,486**	**11,608**	**14,635**	**13,691**	**--**

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत को इंगित करते हैं।

चार्ट-1.9: 2007-2011 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वचनबद्ध व्यय का अंश

(लेबल में मूल्य ₹ *करोड़ में*)



*केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वेतन एवं पारिश्रमिक भुगतान भी आयोजनागत शीर्ष में शामिल हैं।

2007-08 में वचनबद्ध व्यय जो राजस्व प्राप्तियों के 50.07 *प्रतिशत* था, विद्यमान वर्ष के दौरान 61.12 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। राज्य सरकार को चाहिए कि वचनबद्ध व्यय को सन्निहित करने हेतु कदम उठायें क्योंकि विकासपरक कार्यकलापों के लिए व्यय करने हेतु सरकार के लिए यह कोइ गुंजाइश नहीं छोड़ता है।

वेतन एवं पारिश्रमिक

वेतन पर व्यय, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियानव्यन के कारण वर्ष 2008-09 में ₹ 3,045 करोड़ से 44 *प्रतिशत* (₹ 1,343 करोड़) बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹4,388 करोड़ हो गया था । यद्यपि वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान वेतन पर व्यय क्रमश: 7.59 *प्रतिशत* और 11.08 *प्रतिशत* ही बढ़ा। इन दो वर्षों में वेतन व्यय तेरहवें वित्त आयोग के अनुमानों से अधिक था। तथापि चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य (₹ 5,670 करोड़) से एफ सी पी में (₹ 5,670 करोड़) तथा एम टी एफ पी एस (₹ 5,410 करोड़) में काफी नीचे थे।

तेरहवें वित्त आयोग के मानकों में नियत है कि वेतन मद के अन्तर्गत व्यय, राजस्व व्यय के ब्याज भुगतानों व पेंशन का शुद्ध 35 *प्रतिशत* होना चाहिए, जबकि चालू वर्ष में वेतन पर वास्तविक व्यय 50 *प्रतिशत* था।

पेंशन भुगतान

राज्य सरकार ने पेंशन दायित्वों का अनुमान ऐतिहासिक वृद्धि दर के आधार पर लगाया था न कि वास्तविकता के आधार पर। वर्ष 2011-12 में पेंशन पर व्यय ₹ 1,135 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का 8.29 *प्रतिशत* था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान पेंशन भुगतान लगभग स्थिर बने रहे। चालू वर्ष के

दौरान पेंशन भुगतान, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा, चालू वर्ष के लिए निर्धारित मानक (₹ 1,208 करोड़) से अत्यधिक कम था। (ते वि आ के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.7)।

राज्य सरकार ने भविष्य में बढ़ते पेंशन दायित्व से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए 01 अक्टूबर 2005 या उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना भी लागू की है।

ब्याज भुगतान

जैसा कि **तालिका 1.6** में दर्शित है, वर्ष 2007-12 की अवधि में ब्याज भुगतान पिछले ऋणों के कारण 61.41 *प्रतिशत* बढ़ गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान ब्याज भुगतान में आन्तरिक ऋणों[4] पर ब्याज (₹ 1,326 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 369 करोड़), अन्य देयताएँ (₹ 36 करोड़) और भारत सरकार से लिए हुए ऋण एवं अग्रिम (₹ 38 करोड़) शामिल थे। चालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 1,769 करोड़) राजस्व प्राप्तियों का 12.93 *प्रतिशत* था, जो कि चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार के राजकोषीय सुधार पथ द्वारा निर्धारित लक्ष्य ₹ 1,812 करोड़ से निम्न थे और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा चालू वर्ष हेतु निर्धारित मानक (₹ 1,599 करोड़) से ₹ 170 करोड़ अधिक था। यद्यपि, राज्य की एम टी एफ पी एस में ब्याज भुगतान लक्ष्य ₹ 1,415 करोड़ था।

1.4.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान द्वारा प्रदत्त सहायता राशि **तालिका-1.7** में प्रस्तुत है।

तालिका-1.7-: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					ब आ	वास्तविक
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	301.42	198.99	267.99	488.49	473.19	403.45
नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ	110.93	106.20	122.47	154.72	202.78	175.76
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएं	198.85	168.57	202.25	252.96	372.28	203.04
विकास अभिकरण	514.53	588.44	571.47	526.00	625.04	409.35
चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	28.69	38.89	44.52	71.23	122.49	86.98
ऊर्जा (उत्तराखण्ड विद्युत निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उत्तराखण्ड विद्युत निगम)	134.52	69.79	24.39	7.50	10.05	6.32
कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण	153.67	217.73	98.62	151.15	226.93	205.54
सहकारिता	17.16	3.49	13.22	9.56	7.25	7.30

[4] परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य पालन	14.53	31.51	14.79	13.16	8.65	8.65
सचिवालय आर्थिक सेवाएँ एवं पर्यटन	59.21	27.51	11.43	18.43	59.50	29.34
सामाजिक सुरक्षा एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	108.73	122.77	133.65	97.46	231.05	211.10
सरकारी कम्पनियाँ/सांविधिक निगम	-	-	13.41	--	--	--
अन्य संस्थाएं	39.34	85.46	357.83	131.61	71.66	31.12
योग	**1,681.58**	**1,659.35**	**1,876.04**	**1,922.27**	**2,410.87**	**1,777.95**
राजस्व व्यय के *प्रतिशत* के रूप में सहायता	*23.18*	*19.77*	*17.60*	*16.54*	*16.83*	*13.70*

स्रोतः वी एल सी प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को प्रदत्त कुल सहायता वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 की अवधि में घटती बढ़ती वृद्धि दर्शाई। इन निकायों को सहायता चालू वर्ष के दौरान ₹ 144 करोड़ (7.51 *प्रतिशत*) से कम रही। विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थाओं, विकास अभिकरणों को प्रदत्त सहायता राशि कुल वित्तीय सहायता का 46 *प्रतिशत* थी।

इस वर्ष के दौरान सहायता में कमी, मुख्यतः शैक्षिक संस्थाओं (₹ 85 करोड़) और विकास अभिकरणों (₹ 117 करोड़) के अन्तर्गत थी जो कृषि (₹ 54 करोड़) और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण (₹ 114 करोड़) के लिए दी गयी सहायता में वृद्धि के कारण प्रतिसंतुलित हुई।

स्थानीय निकाय: परिचय, कार्यों का अवक्रमण, निधि और लेखाकरण, लेखापरीक्षा कार्य और प्रतिवेदन कार्य की व्यवस्था

परिचय:

उत्तराखण्ड राज्य नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया। प्रधान महालेखाकार (ले एवं हक) उत्तराखण्ड, देहरादून के प्रशासनिक नियत्रंण में वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून का कार्यालय 2004 में स्थापित हुआ। भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में सन् 2012 में, लेखा प्रकार्यों के पुन:संरचना के पश्चात, वरिष्ठ उप महालेखाकार (एल बी ए और ए) उत्तराखण्ड के कार्यालय को, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून के सामाजिक एवं एल बी सेक्टर के साथ मिला दिया गया है।

उत्तराखंड में पी आर आई की 7,649 लेखापरीक्षित इकाईयाँ हैं जिनकी तीन श्रेणियाँ हैं-ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत तथा यू एल बी की 63 लेखापरीक्षित इकाईयाँ हैं, जैसे - नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक और एल बी के लेखा अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

पी आर आई और यू एल बी के कार्य

73वें संविधान संशोधन 1993 में वर्णित और 11वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 जी) में सूचीबद्ध कार्यों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्य है और 74वें संविधान संशोधन 1993 और 12वीं अनुसूची में (अनुच्छेद 243 डब्ल्यू) सूचीबद्ध अनुसार यू एल बी के लिए 18 कार्य है। उपरोक्त परिकल्पित कार्यों में से 2006 में उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य के पंचायतीराज संस्थाओं के तीन सोपानों को केवल 14 कार्य तथा नगरीय स्थानीय संस्थाओं को नौ कार्य हस्तान्तरित किए।

कार्यकर्ताएँ

पी आर आई और यू एल बी को प्रदत्त प्रकार्यों से संबंधित कार्यकर्ताओं को अभी तक उत्तराखण्ड के पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के तीनों सोपानों को हस्तान्तरित नहीं किया गया था। तथापि, इन कार्यों से संबंधित सरकारी आदेशों को पहले ही, राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा निर्गमित किया जा चुका है।

लेखाकरण, लेखापरीक्षा कार्य और प्रतिवेदन कार्य की व्यवस्था

स्थानीय निकायों द्वारा बजट एवं लेखाओं के रखरखाव तैयार करने के लिए, पूरे भारत में एकरूपेण, बजट तथा लेखाकरण फार्मेट भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि म ले प) द्वारा निर्धारित किया गया है। वर्ष 2005 में राज्य सरकार ने इन सभी फार्मेटों को पी आर आई-ओं तथा यू एल बी-यों के लिए अपना लिया है।

पी आर आई-यों तथा यू एल बी-यों जो मुख्यतः संघ या राज्य सरकारों के समेकित निधियों से वित्तीयित हैं, की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 जहाँ भी लागू हो, की धारा 14 के अन्तर्गत, नि म ले प द्वारा संपादित है। राज्य सरकार ने भी पी आर आई-यों तथा यू एल बी-यों की लेखापरीक्षा, नि म ले प (क श से) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अधीन तकनीकी निदर्शन व आधार व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सी ए जी को सौपा है। तदनुसार, जो पी आर आई-यां तथ यू एल बी यां नि म ले प के (क श से) अधिनियम 1971 की धारा 14 के कार्यक्षेत्र में नही आते उनकी लेखापरीक्षा, सी ए जी (क श से) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अधीन ली जाती है। इस प्रकार की लेखापरीक्षा सम्पादन से उत्पन्न लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के नियम 155 के अधीन वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के रूप में राज्य सरकार को सूचित की जाती है।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतया उसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती हैं। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन पहलुओं को समाहित करती है यथा, व्यय की पर्याप्तता (जैसे लोक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान); किये गये व्यय की दक्षता और प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण)।

1.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

तालिका 1.8 चालू वर्ष के दौरान विकासपरक व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूँजीगत व्यय के सापेक्ष राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को विश्लेषित करती है

तालिका-1.8

2007-08 और 2011-12 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स व्य/स रा घ उ	वि व्य #/स व्य	सा क्षे व्य/स व्य	पूं व्य/स व्य
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2007-08	21.16	67.21	33.46	23.03
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2011-12	16.32	68.26	41.11	14.91

स व्य : सकल व्यय, वि व्य : विकासपरक व्यय, सा क्षे व्य : सामाजिक क्षेत्र में व्यय

विकासपरक व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय, विकासपरक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

स्रोतः (1) स रा घ उ के लिए सूचना राज्य के अर्थ एवं संख्या निदेशालय से एकत्र की गयी थी। (**परिशिष्ट-1.2 भाग अ**)

राजकोषीय प्राथमिकता राज्य द्वारा श्रेणी विशेष के व्यय को दी गई प्राथमिकता को इंगित करती है। 2007-08 के सापेक्ष 2011-12 में व्यय पद्धति की तुलनात्मक अध्ययन पर पाया गया कि:

- सरकार का सकल व्यय स रा घ उ के अनुपात के रूप में 2007-08 से 2011-12 में निम्नतर था।
- सकल व्यय के अनुपात के रूप में विकासपरक व्यय (वि व्य) वर्ष के दौरान लगभग 1.05 *प्रतिशत* बढ़ गया है।
- सकल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र व्यय लगभग आठ *प्रतिशत* बढ़ा।
- यद्यपि पूँजीगत व्यय चालू वर्ष के दौरान 25 *प्रतिशत* बढ़ा, लेकिन सकल व्यय (स व्य) में पूँजीगत व्यय का अनुपात लगभग आठ *प्रतिशत* तक कम हुआ।

1.5.2 व्यय करने की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास मदों पर लोक व्यय के महत्व के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार के लिए उचित व्यय औचित्यपूर्ण कदम उठाना तथा कोर पब्लिक एवं मेरि गुड्स[5] के प्रावधान पर जोर देना महत्वपूर्ण हैं। विकासपरक व्यय[6] हेतु आवंटन में सुधार के अतिरिक्त, आसन्न वर्षों में विशेषकर ऋण सेवाओं में गिरावट के कारण उत्पन्न राजकोषीय अन्तराल के मद्देनजर, किये हुए व्यय की दक्षता पूँजीगत व्यय के कुल व्यय से अनुपात (और/अथवा स रा घ उ) एवं विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रखरखाव पर होने वाले राजस्व व्यय के समानुपात से भी परिलक्षित होता है। कुल व्यय (और/अथवा स रा घ उ) में इन घटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, उतना ही व्यय की गुणवत्ता को बेहतर करेगा। जहाँ, एक ओर **तालिका 1.9** चालू वर्ष व गत वर्ष के दौरान बजटीय आवंटन की तुलना में राज्य के समग्र व्यय से सम्बन्धित विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है, वहीं **तालिका 1.10,** चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किए गये पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

[5] **परिशिष्ट 4.1** की शब्दावली का संदर्भ लें।

[6] **परिशिष्ट 4.1** की शब्दावली का संदर्भ लें।

कुल व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय के अंश ने वर्ष 2007-12 की अवधि के दौरान 50 *प्रतिशत* की औसत दर पर अन्तर्वर्षीय विविधता दर्शायी। विकासपरक पूँजीगत व्यय के अंश ने भी अन्तर्वर्षीय विविधता प्रदर्शित की लेकिन 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान थोड़ा बढ़ गया। तथापि, वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 की अवधि में समग्र विकासपरक व्यय में 63 *प्रतिशत* की बढ़ोत्तरी हुई।

तालिका-1.9

विकास परक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासपरक व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बी ई	वास्तविक
विकासपरक व्यय (अ से स)	6,521 (67)	6,973 (66)	8,205 (66)	8,842 (65)	11,957 (67)	10,607 (68)
अ. विकासपरक राजस्व व्यय	4,290 (44)	5,015 (48)	6,638 (54)	7,033 (52)	8,799 (49)	8,121 (52)
ब. विकासपरक पूँजीगत व्यय	2,034 (21)	1,842 (17)	1,538 (12)	1,750 (13)	2850 (16)	2,240 (14)
स. विकासपरक ऋण एवं अग्रिम	197 (2)	116 (1)	29 (0.23)	59 (0.44)	308 (2)	246 (2)

कोष्ठक के आँकड़े समग्र व्यय के प्रतिशत को इंगित करते हैं।

तालिका-1.10

चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2010-11			2011-12		
	कु व्य पर पूँ व्य का अनुपात	रा व्य में अंश		कु व्य पर पूँ व्य का अनुपात	रा व्य में अंश	
		वे एवं पा	परि एवं मर		वे एवं पा	परि एवं मर
सामाजिक सेवाएँ (सा से) मुख्य घटकों पर व्यय						
सामान्य शिक्षा	0.70	19.07	0.006	0.73	19.99	0.003
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.54	3.89	0.036	0.60	3.91	0.027
जलापूर्ति, स्वच्छता और आवासीय एवं शहरी विकास	0.20	0.048	.013	0.76	0.04	0.010
सा से पर कुल व्यय	**1.74**	**24.22**	**0.07**	**2.37**	**25.00**	**0.06**
आर्थिक सेवाएँ (आ से) मुख्य घटकों पर व्यय						
कृषि एवं संबद्ध क्रिया कलाप	0.14	3.54	0.16	1.67	3.37	0.13
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	2.56	1.66	0.29	2.93	1.54	0.19
विद्युत एवं ऊर्जा	0.41	-	-	0.27	-	-
परिवहन	6.94	0.10	0.006	5.52	0.10	0.55
आ से पर कुल व्यय	**11.19**	**6.71**	**0.46**	**12.03**	**6.41**	**0.89**
सा से + आ से पर कुल व्यय	**12.93**	**30.93**	**0.53**	**14.41**	**31.41**	**0.94**

कु व्यः कुल व्यय, पूँ व्यः पूँजीगत व्यय, रा व्यः राजस्व व्यय, वे एवं पाः वेतन एवं पारिश्रमिक, परि एवं मरः परिचालन एवं मरम्मत।

यद्यपि, पूँजीगत व्यय के प्राथमिकीकरण से सम्बन्धित कोई विशेष मापदण्ड एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित नहीं किये गये हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 के बजट के साथ राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत अपने एम टी एफ पी एस में तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के प्रति वचनबद्धता दर्शायी है जिनमें स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटा स रा घ उ का 3.5 *प्रतिशत* होगा और वर्ष 2013-14 तक इसे कम करके तीन *प्रतिशत* लाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार उधार कम लेगी तथा निकट भविष्य में पूँजीकरण हेतु निधियाँ कम होंगीं। तथापि चालू वित्त वर्ष में सरकार ने वर्ष 2010-11 की तुलना में 25 *प्रतिशत* अधिक निधियों के पूंजीकरण की व्यवस्था की।

वर्ष 2011-12 के दौरान, राजस्व व्यय के *प्रतिशत* के रूप में वेतन तथा पारिश्रमिक सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर लगभग स्थिर बना रहा। राजस्व व्यय के *प्रतिशत* के रूप में परिचालन एवं मरम्मत व्यय चालू वर्षों के दौरान आर्थिक सेवाओं में मूल्यवर्द्धित हआ।

1.6 सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण

एफ आर बी एम ढाँचे के उपरान्त राज्य से न केवल अपने राजकोषीय घाटे (व उधार) को निम्न स्तर पर रखने वरन् अपने पूँजीगत ऋण एवं अग्रिम सहित व्यय और निवेश की जरूरतों को वहन करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भर होने के क्रम में, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने एवं ऋण से प्राप्त निधियों की लागत को अप्रत्यक्ष उपदान के रूप में अपने बजट से वहन करने के बजाय वसूल किये जाने तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। यह खण्ड, पूर्व वर्षों के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्यय का मोटे तौर पर वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.6.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2012 को विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं सम्बन्धी सूचना **तालिका 1.11** में दी गयी है।

तालिका-1.11

अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत*	पुनरीक्षित आगणन में लागत वृद्धि	31 मार्च 2012 को संचयी वास्तविक व्यय
लोक निर्माण विभाग	46	183.31	--	--	102.90
सिंचाई	17	70.37	--	--	18.90
योग	**63**	**253.68**			**121.80**
** राज्य सरकार द्वारा 31.03.2012 तक किये गये अन्तिम पुनरीक्षण के अनुसार परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत को इंगित करता है।*					

स्रोतः वित्त लेखे

वित्त लेखे के **परिशिष्ट 10** ने दर्शाया कि पूर्णता हेतु नियत 63 परियोजनाएँ 31 मार्च 2012 को अपूर्ण रही।

1.6.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2012 को सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं (**तालिका 1.12**) में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था अर्थात पिछले 3 सालों के निवेश के एक *प्रतिशत* से भी कम, जबकि सरकार ने वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 के दौरान ऋणों पर 7.60 *प्रतिशत* औसत दर पर ब्याज दिया।

तालिका-1.12

निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ऋणों की लागत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वर्ष के अन्त तक निवेश *(₹ करोड़ में)*	1,005	1,071	1,240	1,296	1,338
प्रतिफल *(₹ करोड़ में)*	0.53	0.23	0.07	0.21	0.05
प्रतिफल (*प्रतिशत*)	0.05	0.02	0.01	0.02	*[7]
सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर (*प्रतिशत*)	7.99	7.75	7.64	7.34	7.83
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अन्तर (*प्रतिशत*)	7.94	7.73	7.63	7.32	7.83

स्रोतः वित्त लेखे

निवेश एवं प्रतिफल पर इस संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। इस प्रकार, मानक तैयार करने तथा कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक लाभ से जुड़ी परियोजनाओं को चिन्हित करने की आवश्यकता है।

मुख्य लाभार्थियाँ थीं- (i) उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 577 करोड़) और (ii) उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 802 करोड़)। तथापि इन निगमों ने वर्ष 2010-11 के अन्तिमीकृत लेखा में क्रमशः ₹ 1,948 करोड़ और ₹ 170 करोड़ की कुल हानियाँ संचित की।

1.6.3 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलाप भी कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय प्रबन्धित उपक्रमों द्वारा भी निष्पादित किये जाते हैं। सरकार द्वारा किए गए निवेशों की उस वर्ष तक जिस वर्ष तक के प्रोफार्मा लेखे

[7] गणन योग्य नहीं।

तैयार कर लिए गए हैं, विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेशित पूँजी का प्रतिफल **परिशिष्ट-1.6** में दिया गया है। तीन कम्पनियों के अन्तिम लेखाओं की जाँच में यह पाया गया था किः

- राज्य सरकार द्वारा सरकारी सिंचाई कार्यशाला, रूड़की में ₹ 1.89 करोड़ का निवेश, उस वित्तीय वर्ष के अन्त तक किया गया था, जब तक उसके लेखे तैयार (अर्थात वर्ष 2009-10) कर लिए गये थे ।
- कुल तीन उपक्रमों, अर्थात सिंचाई कार्यशाला, रूड़की, आर एफ सी, हल्द्वानी तथा आर एफ सी, देहरादून, में से केवल सिंचाई कार्यशाला के 2009-10 तक के लेखे तैयार थे। वर्ष 2007-08 तक यह लाभार्जन का उपक्रम था, परन्तु तत्पश्चात शुद्ध हानि दर्ज की गयी। अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार इन तीन विभागीय उपक्रमों की कुल संचित हानियाँ ₹ 46 करोड़ की थी।
- वर्ष 2011-12 के दौरान इन विभागीय उपक्रमों द्वारा कोई भी लेखा अन्तिम नहीं किया गया।

1.6.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को ऋण एवं अग्रिम राशि भी उपलब्ध कराती रही है। **तालिका-1.13** 31 मार्च 2012 को बकाया ऋण एवं अग्रिमों, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका-1.13

राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियाँ/ऋण की लागत की मात्रा	2009-10	2010-11	2010-11	
			ब आ	वास्तविक आँकड़े
प्रारम्भिक शेष	777.87	743.09	--	717.90
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम राशि	30.05	59.68	307.91	246.83
वर्ष के दौरान चुकता की गई राशि	64.83	84.87	--	90.65
अंतिम शेष	**743.09**	**717.90**		**874.08**
निवल वृद्धि	(-) 34.78	(-) 25.19		(+) 156.18
ब्याज प्राप्तियाँ	0.82	7.98		0.62
बकाया ऋणों एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्तियाँ *प्रतिशत* के रूप में	0.11	1.11		0.07
राज्य सरकार के अदत्त राजकोषीय दायित्वों के *प्रतिशत* के रूप में ब्याज भुगतान	7.14	6.85		7.49
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर (*प्रतिशत*)	7.03	5.74		7.42
अदत्त बकाया, जिनकी शर्तें नियत की जा चुकी हैं	राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई			

स्रोतः वित्त लेखे व वार्षिक वित्त विवरणी (उत्तराखण्ड सरकार)

सरकार ने वर्ष 2010-11 के ₹ 60 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 247 करोड़ ऋण दिये, जो कि पिछले वर्ष से ₹ 187 करोड़ अधिक थे।

बकाया ऋणों एवं अग्रिमों ब्याज के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ, चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में निम्नतम थी। वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाये गये बाजार ऋणों की औसत ब्याज दर 7.83 *प्रतिशत* थी, जबकि राज्य सरकार द्वारा, विभिन्न संस्थाओं, निगमों/सरकारी कम्पनियों और सरकारी कर्मचारियों आदि को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज की दर केवल 0.07 *प्रतिशत* थी, जो कि वर्ष 2009-10 में बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 7 *प्रतिशत* के लक्ष्य के सापेक्ष थी।

बारहवें वित्त आयोग ने संस्तुति दी कि बकाया पड़े ऋणों एवं अग्रिमों पर कम से कम 7 *प्रतिशत* प्रतिफल पूर्वानुमानित अवधि के अन्तिम वर्ष (2009-10) तक श्रेणीबद्ध ढंग से प्राप्त किया जाना चाहिए, जिस लक्ष्य को राज्य सरकार वर्ष 2011-12 में भी प्राप्त नहीं कर पायी। 31 मार्च 2012 तक सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण ₹ 874 करोड़ थे। मुख्य लाभार्थी, ऊर्जा (₹ 415 करोड़) एवं कृषि (₹ 295 करोड़) क्षेत्र थे। उत्तराखण्ड विद्युत निगम और उत्तराखण्ड ग्रामीण विद्युतीकरण ऊर्जा निगम दोनों को प्रदत्त ऋण का अधिकांश मिलाकर ऊर्जा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 323 करोड़ था।

1.6.5 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.14 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों से किये गये निवेश को इंगित करती है।

तालिका-1.14
रोकड़ शेष और रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2011 को	31 मार्च 2012 को	वृद्धि(+)/ कमी(-)
रोकड़ शेष	1,229.41	1,085.18	(-)144.23
रोकड़ शेष से निवेश (अ से द)			
अ. भारत सरकार के ट्रेजरी बिल	…	50.21	(+)50.21
ब. भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	…	---	---
स. अन्य प्रतिभूतियाँ, यदि कोई हो तो विवरण दें	…	---	---
द. अन्य निवेश	…	---	---
उद्धिष्ट शेष से निवेश का निधिबद्ध विवरण			
i. सिकिंग फण्ड निवेश लेखा	878.62	902.36	(+)23.74
ii. प्रत्याभूति विमोचन निधि	25.00	25.00	---
ब्याज वसूली	13.78	10.40	(-)3.38

स्रोतः वित्त लेखे

अन्तिम रोकड़ शेष गत वर्ष (₹ 1,229.41 करोड़) की अपेक्षा चालू वर्ष (₹ 1,085.18 करोड़) के अन्त में ₹ 144.23 करोड़ घट गया।

राज्य सरकार ने रोकड़ शेष से ₹ 927.36 करोड़ की नैमित्तिक निधि सृजित की। यही राशि नैमित्तिक निधि से भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशित की गई तथा वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 10.40 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। वर्ष 2011-12 के दौरान रोकड़ शेष पर प्राप्त ब्याज 1.06 *प्रतिशत* था जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपनी उधार राशियों पर 7.83 *प्रतिशत* की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। राज्य सरकार ने ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं लिया और वर्ष 2011-12 के दौरान अधिकतम दिनों के लिए ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम शेष बनाये रखने में समर्थ थी। तथापि, वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह में अस्थायी शेष ने सरकार को 73 (साधारण और विशेष) अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम को प्राप्त करने के लिए मजबूर किया। वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य को ₹ 0.88 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में देना पड़ा।

1.7 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

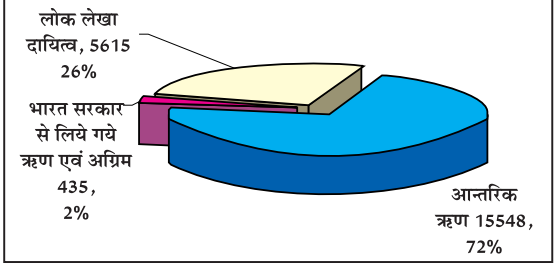
1.7.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्व की संरचना एवं वृद्धि

विद्यमान सरकारी लेखापद्धति में, सरकारी स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों, जैसे भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया है। तथापि, सरकारी लेखे, सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। **परिशिष्ट-1.4 (भाग-ब)** में 31 मार्च 2011 की समतुल्य स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2012 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। इस परिशिष्ट में दायित्वों में मुख्यतः आन्तरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं तथा परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं।

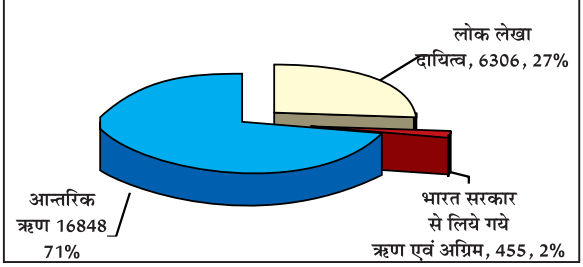
1.7.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया पड़े राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट-1.3**, **परिशिष्ट-1.4** व राज्य वित्त लेखे के **विवरण 6** में प्रस्तुत किया गया है तथापि, पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्वों की संरचना **चार्ट 1.10 और 1.11** में प्रस्तुत की गई है।

चार्ट-1.10: 31.03.2011 को बकाया राजकोषीय दायित्वों की संरचना (₹ *करोड़ में*)



चार्ट-1.11: 31.03.2012 को बकाया राजकोषीय दायित्वों की संरचना (₹ *करोड़ में*)



ऋण- स रा घा उ अनुपात वर्ष 2011-12 (24.80 *प्रतिशत*) के लिए, वर्ष 2010-11 (26.19 *प्रतिशत*) से 1.39 *प्रतिशत* कम था। यह अनुपात तेरहवें वित्त आयोग के उस वर्ष के लिए, निर्धारित मापदण्ड (41.10 *प्रतिशत*) से नीचे था। समग्र राजकोषीय दायित्व वर्ष 2007-08 के ₹ 14,392 करोड़ से 64.04 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 23,609 करोड़ हो गये थे। राज्य के देयताएँ जो वर्ष 2011-12 के अन्त में ₹ 23,609 करोड़ के थे उसमें मुख्य रूप से लोक ऋण (₹ 17,304 करोड़), लघु बचत एवं भविष्य निधि (₹ 4,449 करोड़) और अन्य दायित्व (₹ 1,856 करोड़) शामिल थे। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय दायित्वों में वृद्धि मुख्यतः आन्तरिक ऋण तथा लघु बचत एवं भविष्य निधि आदि के कारण थी, जो क्रमशः ₹ 1,300 करोड़ एवं ₹ 626 करोड़ तक बढ़ गये थे। राजकोषीय देयताओं में वृद्धि विभिन्न वर्षों में कम बढ़ी। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में यह 9.31 *प्रतिशत* बढ़ी। वर्ष के दौरान स रा घा उ के सापेक्ष इन दायित्वों में उत्प्लावकता 0.60 थी, जो यह इंगित करती थी कि स रा घा उ में प्रत्येक *प्रतिशत* बिन्दु के लिए राजकोषीय दायित्व 0.60 *प्रतिशत* बढ़ गये थे। ये दायित्व राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 1.72 गुना एवं अपने संसाधनों का 3.50 गुना थे। राज्य में प्रारम्भ से ही खुले बाजार ऋणों की भुगतान वापसी के लिए सिंकिग फण्ड चलन में है और राज्य सरकार को पिछले वर्ष के बकाया पड़े बाजार ऋणों के तीन *प्रतिशत* की दर से अंशदान करना है। तथापि, राज्य सरकार ने इस उद्देश्य हेतु देय ₹ 217 करोड़ के विरूद्ध इस वर्ष केवल ₹ 25 करोड़ प्रदत्त किया।

1.7.3 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूतियाँ, उधार लेने वाले जिसके लिये प्रत्याभूति दी गयी है, के दोषी रहने पर राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व हैं।

राज्य विधायिका द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत उस अधिकतम सीमा के निर्धारणार्थ कोई भी कानून पारित नहीं किया गया, जिसके अन्तर्गत सरकार राज्य समेकित निधि की प्रतिभूति पर प्रत्याभूतियाँ दे सके। एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में यह विहित है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होते समय विद्यमान, राज्य सरकार के किसी नियम या कानून के अन्तर्गत अथवा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या कानून द्वारा, निर्धारित सीमा से अधिक राशि पर प्रत्याभूति नहीं देगी। तथापि, प्रत्याभूतियों की सीमा तय करने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक कोई कानून पारित नहीं किया है।

वित्त लेखे के **विवरण संख्या 9** के अनुसार, अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा प्रत्याभूतियाँ दी गई थी तथा विगत तीन वर्षों में बकाया प्रत्याभूतियाँ **तालिका-1.15** में दी गई हैः

तालिका-1.15

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2009-10	2010-11	2011-12
प्रतिभूति की अधिकतम राशि	125	2,122	2,722
प्रतिभूति की बकाया राशि	1,511	1,511	1,739
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिभूति की अधिकतम राशि का *प्रतिशत*	1.32	18.28	19.88
एफ आर बी एम अधिनियम/कोई अन्य अधिनियम अथवा राज्य के आदेश के अनुसार मानदण्ड	एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 के परिपालन में राज्य सरकार द्वारा कोई भी नियम नहीं बनाया गया है।		

स्रोतः वित्त लेखे

सरकार ने ₹ 25 करोड़ की प्रत्याभूति संग्रह उत्थित प्रत्याभूतियों के निपटान के लिए एक 'प्रत्याभूति विमोचन निधि' गठित किया है।

राज्य सरकार ने प्रत्याभूति देने योग्य निर्धारित सीमाओं के लिए, एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 के अनुसरण में, कोई नियम नहीं बनाये हैं। उपरोक्त की अनुपस्थिति में यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका कि सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति सीमाओं के दायरे में थी।

प्रत्याभूति बनाम राजस्व प्राप्तियों की अधिकतम राशि का *प्रतिशत*, 2009-10 के 1.32 *प्रतिशत* से बढ़कर 2011-12 में 19.88 *प्रतिशत* हो गया। 31 मार्च 2012 तक बकाया प्रत्याभूति की राशि उर्जा क्षेत्र (₹ 1,187 करोड़), सहकारिताओं (₹ 475 करोड़) और चार अन्य संस्थाओं (₹ 77 करोड़) के विरूद्ध थी।

1.8 ऋण-वहन क्षमता

राज्य सरकार के ऋणों के विस्तार के अलावा राज्य की ऋण वहन क्षमता को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। यह खण्ड, ऋण स्थिरीकरण, ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता, उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतानों के अनुपात द्वारा मापित) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के संदर्भ में राज्य सरकार की ऋण-वहन क्षमता का आकलन करता है। **तालिका 1.16** वर्ष 2009-10 से आरम्भ करते हुए तीन वर्षों की अवधि हेतु इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण-वहन क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका-1.16

ऋण वहन क्षमता : सूचक एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण वहन क्षमता के सूचक[8]	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण स्थायित्विकरण[9] (मात्रात्मक विस्तार + प्राथमिक घाटा)	(+) 2,083	(+) 1,592	(+) 1,811
ऋणेतर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)[10]	(-)940	(+) 1,224	(+) 664
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता[11]	261	820	308
ब्याज/भुगतानों का भार (ब्याज भुगतान/रा प्रा अनुपात)	14.10	12.75	12.92

तालिका-1.16 की प्रवृत्तियाँ दर्शाती हैं कि वर्ष 2009-10 के दौरान मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्रारम्भिक घाटा धनात्मक (₹ 2,083 करोड़), थे जो कि वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 1,592 करोड़ तक उतर गये। तथापि वर्ष के दौरान उच्चोन्मुखी प्रवृति दर्शायी और वर्ष 2011-12 के अन्त में ₹ 1,811 करोड़ पर रहा। ऋण- स रा घा उ अनुपात जो वर्ष 2007-08 में 31.40 *प्रतिशत* था, चालू वर्ष के दौरान 24.80 *प्रतिशत* तक उतर गया। उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में, ऋण- स रा घा उ अनुपात 24.80 *प्रतिशत* पर था, जो तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित लक्ष्य (41.10 *प्रतिशत*) से अत्यधिक नीचे था।

ऋण स्थायित्व और इसकी वहन क्षमता का दूसरा सूचक, बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्रारम्भिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण-वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियाँ,[12] बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्रारम्भिक व्यय को पूरा कर सकतीं। धनात्मक संसाधन अंतराल राज्य के ऋणों को संभालने की क्षमता को मजबूत करता हैं। **तालिका 1.16** वर्ष 2008-11 की अवधि हेतु परिभाषित संसाधन अंतराल को इंगित करती है।

राज्य ने वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10 में ऋणात्मक संसाधन अंतराल का अनुभव किया था लेकिन 2010-11 और 2011-12 के दौरान यह धनात्मक हो गया जो बदले में 2010-11 में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक नीचे ले आया और अंततः राज्य ने चालू वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य (₹ 716 करोड़) प्राप्त किया। वर्ष 2010-11 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 1,843 करोड़) को तर्क संगत सीमा तक नीचे लाया गया था, जो चालू वर्ष के दौरान (स रा घा उ का 1.85 *प्रतिशत*) ₹ 1,757 करोड़ तक और नीचे आ गया।

[8] **परिशिष्ट 4.1** की शब्दावली का संदर्भ लें।
[9] **परिशिष्ट 4.1** की शब्दावली का संदर्भ लें।
[10] **परिशिष्ट 4.1** की शब्दावली का संदर्भ लें।
[11] **परिशिष्ट 4.1** की शब्दावली का संदर्भ लें।
[12] **परिशिष्ट 4.1** की शब्दावली का संदर्भ लें।

ऋण छूट वर्ष 2007-10 के दौरान उच्चत्तर स्तर पर रहा था तथा वर्ष 2010-11 में थोड़ा सुधरे (0.83) जिससे यह इंगित होता है कि इस अवधि के दौरान पुरानी ऋण देयताओं को समाप्त करने के लिए ऋण निधियों का बढ़-चढ़ कर प्रयोग किया जा रहा है (**परिशिष्ट-1.3**)। तथापि, वर्ष 2011-12 के दौरान इसने उच्चोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शाई। चालू वर्ष के दौरान आन्तरिक ऋण छूट, नई ऋण प्राप्तियों का 29.12 *प्रतिशत* थी; भारत सरकार के ऋणों में छूट 56.59 *प्रतिशत* थी जबकि अन्य देयताओं के प्रकरण में चुकौतियाँ नयी प्राप्तियों के 83.35 *प्रतिशत* थीं। यह प्रवृत्तियाँ इस तथ्य की ओर इंगित करती हैं कि सरकार का ध्यान पुरानी ऋण देयताओं की समाप्ति की ओर प्रतीत होता है।

राज्य की परिपक्वता रूप रेखा नीचे **तालिका 1.17** एवं **चार्ट 1.12** में प्रदत्त है।

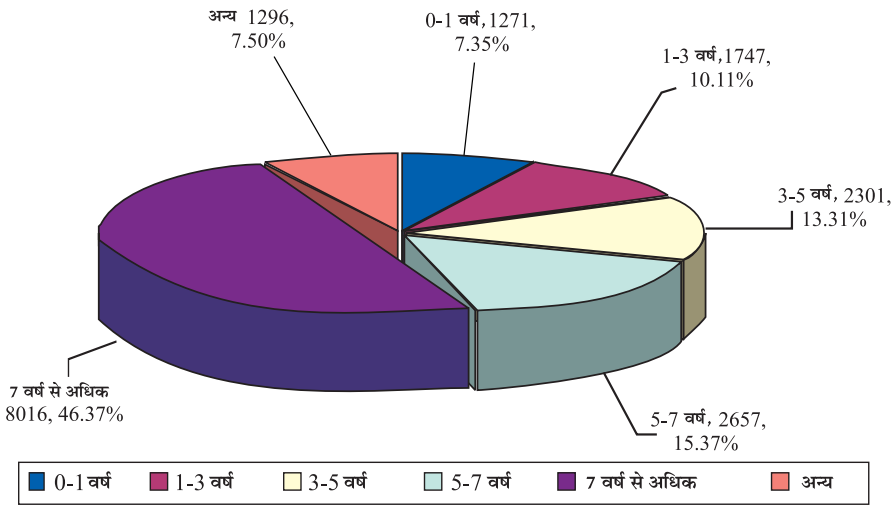
तालिका-1.17

लोक ऋण की परिपक्वता रूप रेखा

परिपक्वता रूप रेखा	राशि *(₹ करोड़ में)*	कुल लोक ऋण पर प्रतिशतता
0-1 वर्ष	1,271	7.35
1-3 वर्ष	1,747	10.11
3-5 वर्ष	2,301	13.30
5-7 वर्ष	2,657	15.37
7 वर्ष से अधिक	8,016	46.37
अन्य (राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी)	1,296	7.50
योग	**17,288**	**100**

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट-1.12: लोक ऋण की परिपक्वता रूप रेखा (₹ *करोड़ में*)



स्रोतः वित्त लेखे

व्यय-दायित्व के निर्वहन हेतु सरकार को और अधिक उधार लेना पड़ा जैसा कि विगत पाँच वर्षों में किसी भी वर्ष में राजकोषीय आधिक्य उपलब्ध नहीं था। 31 मार्च 2012 को लोक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूप रेखा दर्शाती है कि 46.37 *प्रतिशत* लोक ऋण सात वर्षों या अधिक की परिपक्वता में था।

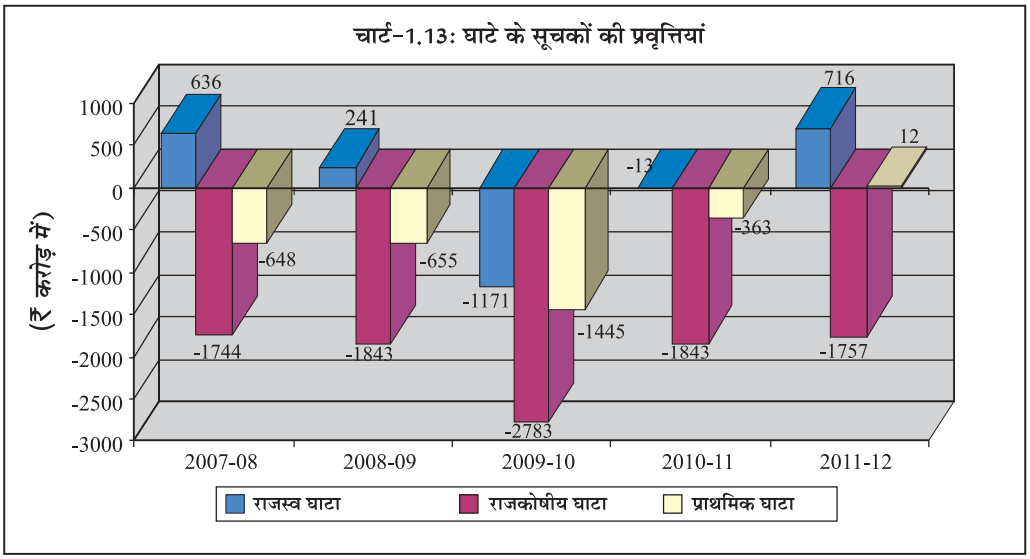
1.9 राजकोषीय असंतुलन

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारम्भिक घाटा-एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में राजकोष के समस्त असन्तुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य के अन्तराल को प्रस्तुत करता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का एक सूचक है। पुनः किस तरह घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और जुटाए गये संसाधनों को प्रयुक्त किया जाता है, यही इसके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड, इन घाटों की प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण एवं वित्त पोषण के ढंग तथा एफ आर बी एम अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के आकलन को भी प्रस्तुत करता है।

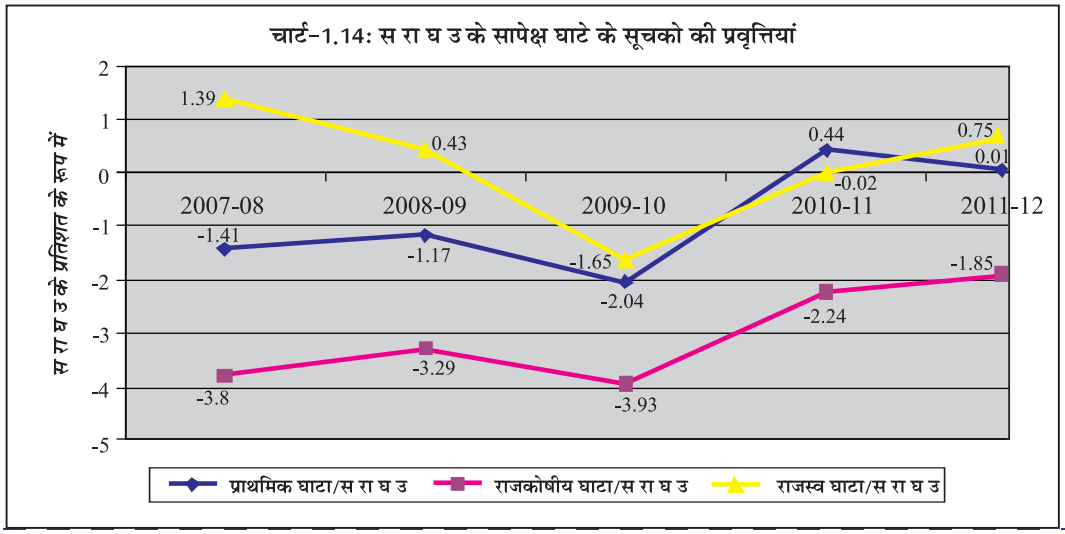
1.9.1 घाटे की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.13 एवं **1.14,** 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि में घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।

चार्ट-1.13: घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियां



चार्ट-1.14: स रा घ उ के सापेक्ष घाटे के सूचको की प्रवृत्तियां



राज्य ने 2007-08 से 2008-09 तक राजस्व आधिक्य का अनुभव किया जो 2009-10 में मुख्यतः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन से घाटे में बदल गया। तथापि राज्य वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक नीचे लाने में और वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 716 करोड़ का आधिक्य प्राप्त करने में कामयाब रहा। राजकोषीय घाटा वर्ष 2010-11 में कम किया गया और एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में निर्धारित चार *प्रतिशत* लक्ष्य से नीचे स रा घ उ का 2.24 *प्रतिशत* था। सरकार के द्वारा राजकोषीय समेकन के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप ही 2011-12 में भी राजकोषीय घाटे में उतार हुई। ₹ 1,757 करोड़ का राजकोषीय घाटा, स रा घा उ के 1.85 *प्रतिशत* पर वर्तमान रूप में टिका है और इस संदर्भ में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 3.5 *प्रतिशत* के अन्तर्गत ही है।

वर्ष 2007-09 तक कुछ नियन्त्रण में रहने वाले प्राथमिक घाटे ने 2009-10 (₹ 1,445 करोड़) में मात्रात्मक उछाल लिया था और वर्ष 2010-11 में नीचे (₹ 363 करोड़) आ गया और चालू वर्ष में सकारात्मक बन गया है।

1.9.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त-पोषण पद्धति

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में एक संरचनात्मक बदलाव हुआ जैसा कि **तालिका 1.18 में** परिलक्षित है।

तालिका-1.18

राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजकोषीय घाटे का विघटन						
1	राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+)	(+) 636	(+) 241	(-) 1,171	(-) 13	(+)716
2	पूँजीगत व्यय	(-) 2,235	(-) 2,016	(-) 1,647	(-) 1,855	(-) 2,317
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)145	(-) 68	(+) 35	(+) 25	(-)156
राजकोषीय घाटे की वित्त-पोषण पद्धति*						
1	बाजार ऋण	733	884	460	890	1,159
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 16	(-) 19	(-)5	16	20
3	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	195	120	672	921	332
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	213	204	70	182	131
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	155	531	1,066	870	626
6	जमा एवं अग्रिम	142	61	229	46	33
7	उचन्त एवं विविध	138	(-) 331	722	(-) 331	(-)412
8	प्रेषण	85	(-) 238	(-)129	(-) 303	(-)466
9	अन्य	55	127	(-)6	242	190
10	कुल आधिक्य/घाटा(नकद शेष)	44	504	(-) 296	(-) 690	144
11	सकल राजकोषीय घाटा	**1,744**	**1,843**	**2,783**	**1,843**	**1,757**

स्रोतः वित्त लेखे

राजस्व आधिक्य जो कि 2009-10 में घाटे में बदल गया था, राजस्व व्यय में अत्यल्प उछाल के कारण चालू वर्ष के दौरान पुनः आधिक्य की ओर प्रवृत हुआ। राज्य वर्ष 2010-11 में राजस्व घाटे को कम करके लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक लाने में कामयाब हो पाया और चालू वर्ष में राजस्व आधिक्य (₹ 716 करोड़) प्राप्त किया। राजकोषीय घाटा (₹ 1,757 करोड़) बड़ी मात्रा मे बाजार की उधारियों (₹ 1,159 करोड़) और राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों (₹ 332 करोड़) से प्रबन्धित किया गया। यद्यपि, वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में वृद्धि (24.91 *प्रतिशत*) हुई, राजकोषीय घाटे को तर्कसंगत सीमा अर्थात् स रा घ उ के 3.5 *प्रतिशत* तक (तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार) चालू वर्ष के दौरान नीचे लाया गया (स रा घा उ का 1.85 *प्रतिशत*)।

1.9.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटा एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित), राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता के सूचक होंगे। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात उस सीमा को इंगित करता है जहाँ तक वर्तमान उपभोग के लिये ऋण निधियों का उपयोग किया गया था। पुनः राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का सतत् उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरंतर कम हो रहा था और ऋणों (राजकोषीय दायित्व) के अंश परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं थे। प्राथमिक घाटे का विभाजन **(तालिका 1.19)** उस सीमा को इंगित करेगा जहाँ तक घाटा पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण रहा है जो राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये वांछनीय हो सकता है।

तालिका-1.19

प्राथमिक घाटा/आधिक्य-संघटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणेतर प्राप्तियाँ*	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) /आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-) /आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2007-08	7,959	6,159	2,235	213	8,607	(+) 1,800	(-) 648
2008-09	8,689	7,206	2,016	122	9,344	(+) 1,483	(-) 655
2009-10	9,551	9,319	1,647	30	10,996	(+)232	(-) 1,445
2010-11	11,693	10,141	1,855	60	12,056	(+) 1,552	(-) 363
2011-12	13,782	11,206	2,317	247	13,770	(+)2,576	(+)12

** लोक ऋण प्राप्तियों से इतर प्राप्तियाँ अर्थात ऐसी प्राप्तियाँ जिन्हें वापस नहीं किया जाता है*

- ऋणेतर प्राप्तियाँ 2007-08 से 2011-12 तक 73.16 *प्रतिशत* बढ़ी और प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं। तथापि, अन्तराल जो 2009-10 में काफी कम हो गया था, पुन: 2010-11 और 2011-12 में उच्चोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शायी।
- कुल प्राथमिक व्यय में 2007-08 की तुलना में 2011-12 के दौरान ₹ 5,163 करोड़ की वृद्धि हुई, यह वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 5,047 करोड़ की सीमा तक प्राथमिक राजस्व व्यय की वृद्धि के कारण थी।
- प्राथमिक राजस्व आधिक्य, जिसने 2009-10 में तीव्र उतार दर्शाया, पुन: पिछले दो वर्षों के दौराना तीव्र उच्चोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शाई।
- चालू वर्ष के दौरान, प्राथमिक घाटा, गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि होने के कारण प्राथमिक आधिक्य में परिवर्तित हुआ।

1.10 निष्कर्ष

पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,083 करोड़ (17.94 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः संघ के करों व शुल्कों में राज्य के अंश (₹ 406 करोड़), राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 1,210 करोड़) और गैर कर राजस्व (₹ 458 करोड़) में बढ़ोत्तरी के कारण थी। राज्य की व्यय पद्धति उदघाटित करती है कि कुल व्यय के *प्रतिशत* के रूप में राजस्व व्यय चालू वर्ष में बढ़ा तथा सम्पतियाँ सृजन के लिए अपर्याप्त स्रोतों को छोड़ते हुये करीब 83.50 *प्रतिशत* रहा। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (एन पी आर ई) में विगत वर्ष की तुलना में 16.45 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

वर्ष 2011-12 के दौरान वेतन पर व्यय 46.66 *प्रतिशत* था और एन पी आर ई के एक बड़े अंश को खपत करने की निरंतरता बनाए रहा। वर्ष 2011-12 में पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 1,135 करोड़ था जो राजस्व प्राप्तियों का 8.29 *प्रतिशत* था। पेंशन भुगतान, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक (₹ 1,208 करोड़) से अत्यधिक कम था **(तेरहवें वित्त आयोग की प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.7**)। राज्य को आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के घटकों को नियंत्रित करने के लिए उपाय ढूंढने चाहिए तथा ब्याज कटौती के लिए आवश्यकता आधारित उधार पर आश्रित रहना चाहिए।

गत वर्ष की तुलना में 2011-12 में राज्य के पूँजीगत व्यय में ₹ 462 करोड़ **(प्रस्तर 1.4.1)** की वृद्धि हुई जो मुख्यतः (i) सामाजिक सेवाओं (ii) आर्थिक सेवाओं में वृद्धि के कारण थी। कुल व्यय के *प्रतिशत* के रूप में पूँजीगत व्यय ने वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 की अवधि में विचलनशील प्रवृत्ति दर्शाई जो वर्ष 2007-08 में 23 *प्रतिशत* व वर्ष 2011-12 में 15 *प्रतिशत* थी। चालू वर्ष में इसने पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि (25 *प्रतिशत*) दर्शाई लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने एफ सी पी (₹ 3,095 करोड़) और एम टी एफ पी एस (₹ 2,524 करोड़) में निर्धारित लक्ष्य से नीचे (₹ 2,317 करोड़) रहा।

विकासपरक पूँजीगत व्यय के अंश ने भी अन्तर्वर्षीय भिन्नता दर्शाई लेकिन वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान थोड़ा सा बढ़ गया तथापि समग्र विकासपरक व्यय वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान 63 *प्रतिशत* बढ़ गया। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में सरकार के निवेश पर पिछले तीन वर्षों में औसत प्रतिफल लगभग नगण्य था जबकि सरकार ने वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक अपने ऋणों पर औसतन 7.60 *प्रतिशत* की दर से ब्याज भुगतान किया।

राज्य ने वर्ष 2007-08 से वर्ष 2008-09 तक राजस्व आधिक्य अनुभव किया जो वर्ष 2009-10 में मुख्यतः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यन्वयन के कारण घाटे में बदल गया तथापि राज्य वर्ष 2010-11 में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक लाने में कामयाब हो पाया था और चालू वर्ष के दौरान ₹ 716 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त कर लिया।

राजकोषीय घाटा को जो कि 2009-10 के दौरान उच्च स्तर पर था और स रा घा उका 3.93 *प्रतिशत* था, 2010-11 और 2011-12 में 3.5 *प्रतिशत* की तर्कसंगत सीमा तक नीचे लाया गया था। 2011-12 के दौरान ₹ 1,757 करोड़ का राज्य राजस्व घाटा, राजकोषीय समेकन को दर्शाता हुआ स रा घा उ के 1.85 *प्रतिशत* पर टिका रहा।

वर्ष 2011-12 के अंत में राज्य के रोकड़ शेष में ₹ 144 करोड़ की कमी हुई और भारतीय रिजर्व बैंक में नकद शेषों के निवेश व भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश पर प्राप्त ब्याज नगण्य (1.06 *प्रतिशत*) था, जबकि सरकार ने 7.83 *प्रतिशत* की औसत ब्याज दर पर ऋण लिया। तथापि, राज्य निम्नतम नकद शेष बना रख पाया और वर्ष के दौरान ओवर ड्राफ्ट सुविधा का सहारा नहीं लिया।

2011-12 में ऋण- स रा घ उ अनुपात, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक 41.10 *प्रतिशत* से काफी नीचे, 24.80 *प्रतिशत* पर था। पिछले पाँच वर्षों में, राज्य ने पहली बार प्राथमिक आधिक्य की स्थिति (₹ 12 करोड़) चालू वर्ष में प्राप्त कर ली। वित्तीय वर्ष के अन्त में जमाव से बचने के लिये, ऋणों का विवरण बनाए रखना तथा ऋण भुगतानों की परिपक्वता की रूपरेखा की स्पष्ट समझ रखना, विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन में दीर्घकालिक लाभ देगी।

वर्ष 2011-12 के दौरान, ₹ 2,040 करोड़ की एक बड़ी धनराशि सीधे राज्य क्रियानव्यन अभिकरणों को अन्तरित की गयी। तथापि, इन निधियों को राज्य बजट/राजकोष पद्धति के माध्यम से नहीं दिया गया। जैसे कि यह निधियाँ राज्य बजट के बाहर रहती है, इनके उपयोग का अनुश्रवण करने के लिये एक भी अभिकरण नहीं है और तत्काल रूप से उपलब्ध कोई ऐसे आँकड़े नहीं है ताकि किसी विशेष वर्ष में प्रमुख चिन्हित योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में वास्तव में कितना व्यय हुआ है-आंका जाए।

1.11 संस्तुतियाँ

सरकार को चाहिए कि:

- सभी परियोजनाओं को तत्परता से पूरा करने के लिए प्रभावशाली कार्ययोजना तैयार करें ताकि लोग समय पर परिलक्षित लाभ प्राप्त करें।
- निवेश में धन के बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय लेने हेतु विचार करें।

अध्याय- 2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदान एवं भारित विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय, दत्तमत एवं भारित व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय के सापेक्ष बजट के भारित एवं दत्तमत दोनों मदों के संदर्भ में विनियोग लेखों में उन अधिकृत को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधान को सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय, विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत है और जो व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होना चाहिए, भारित किया गया है। यह, ये भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया ऐसा व्यय विधि, सुसंगत नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

वर्ष 2011-12 के दौरान 31 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति **तालिका 2.1** में दी गयी है:

तालिका-2.1

वर्ष 2011-12 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक	योग	वास्तविक	बचत (-)/
दत्तमत	I राजस्व	1,23,02.30	11,14.20	1,34,16.50	1,11,56.11	(-)22,60.39
	II पूँजीगत	30,93.59	234.46	3328.05	35,85.79	(+)257.74
	III ऋण एवं अग्रिम	307.91	242.11	550.02	246.83	(-)303.19
योग-दत्तमत		**1,57,03.80**	**15,90.77**	**1,72,94.57**	**1,49,88.73**	**(-) 23,05.84**
भारित	IV राजस्व	*20,23.39*	*41.69*	*20,65.08*	*18,28.91*	*(-)2,36.17*
	V पूँजीगत	*1.00*	*4.00*	*5.00*	*4.88*	*(-) 0.12*
	VI लोक ऋण-पुनर्भुगतान	*16,38.73*	-	*16,38.73*	*1924.04*	*(+)285.31*
योग-भारित		**36,63.12**	**45.69**	**37,08.81**	**37,57.84**	**(+) 49.02**
आकस्मिकता निधि में विनियोग (यदि कोई हो)		-	-	-	-	--
कुल योग		**1,93,66.92**	**16,36.46**	**2,10,03.38**	**1,87,46.56**	**(-) 22,56.82**

तालिका 2.1 अनुसार, ₹ 2,256.82 करोड़ की बचत (निधियों के उपयोग में कमी), राजस्व खण्ड (37 प्रकरणों) और पूँजीगत खण्ड (23 प्रकरणों) के अनुदान तथा विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 3,868.22 करोड़ की बचत, पूँजीगत खण्ड के अन्तर्गत चार अनुदानों व एक विनियोग में ₹1,611.40करोड़ के आधिक्य के परिणामस्वरूप थी।

जिन विभागों के विरूद्ध महत्वपूर्ण बचत (₹ 100 करोड़ से ज्यादा) वर्ष के दौरान जानकारी में आयी वे वित्त (₹ 870.47 करोड़), ऊर्जा (₹ 538.31 करोड़), शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति (₹ 449.69 करोड़), अनुसूचित जातियों का कल्याण (₹ 370.13 करोड़), जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (₹ 251.53 करोड़), कल्याण (₹ 219.48 करोड़) तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 192.99 करोड़), ग्राम्य विकास (₹ 158.75 करोड़), खाद्य (₹ 123.52 करोड़) तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (₹ 100.06 करोड़) थे। इसी प्रकार वर्ष 2011-12 के दौरान जिन विभागों में आवंटन पर महत्वपूर्ण व्ययाधिक्य पाया गया उनमें खाद्य (₹ 1,283.25 करोड़), वित्त (₹ 285.32 करोड़), कृषि (₹ 18.33 करोड़), उद्यान विभाग (₹ 4.51 करोड़) तथा लोक निर्माण विभाग (₹ 19.99 करोड़) थे।

पर्याप्त बचत/आधिक्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध करते हुए बचत/आधिक्य (विस्तृत विनियोग लेखे) को उन्हें सूचित किया गया था (जुलाई 2012)। उनके उत्तर अगस्त 2012 तक प्रतीक्षित थे।

2.3 वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबन्धन

2.3.1 व्यय के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम से पता चला कि बचत 55 प्रकरणों में, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं 34 प्रकरणों में कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थीं **(परिशिष्ट-2.1)**। ₹ 3,868.22 करोड़ की कुल बचत के विरूद्ध 10 अनुदानों तथा एक विनियोग से सम्बन्धित 15 प्रकरणों में ₹ 3,142.24 करोड़ (81.23 *प्रतिशत*)[1] की बचत हुई जैसा कि **तालिका-2.2** में प्रदर्शित है।

तालिका-2.2

₹ 50 करोड़ एवं उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
राजस्व-दत्तमत						
1	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2,243.70	55.98	2,299.68	1,719.58	580.10
2	10-पुलिस व कारागार	667.28	43.72	711.00	660.48	50.52

[1] प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक ।

3	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	3,182.44	467.89	3,650.33	3,366.95	283.38
4	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	803.83	16.28	820.11	666.12	153.99
5	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	646.94	2.07	649.01	413.24	235.77
6	15-कल्याण	552.63	94.44	647.07	449.62	197.45
7	19-ग्राम्य विकास	323.11	64.74	387.85	295.14	92.71
8	25-खाद्य	327.52	0.20	327.72	204.20	123.52
9	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	534.49	37.34	571.83	378.20	193.63
पूँजीगत-दत्तमत						
10	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	117.80	32.77	150.57	78.14	72.43
11	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	271.05	16.22	287.27	120.95	166.32
12	19-ग्राम्य विकास	213.88	0	213.88	147.83	66.05
13	21-ऊर्जा	448.92	227.11	676.03	144.11	531.92
14	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	338.69	2.80	341.49	164.99	176.50
राजस्व -प्रभारित						
15	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	*1,974.03*	*38.96*	*2,012.99*	*1,795.04*	*217.95*
योग		**12,646.31**	**1,100.52**	**13,746.83**	**10,604.59**	**3,142.24**

बचत के कारण अगस्त 2012 तक प्रतीक्षित थे।

2.3.2 निरन्तर बचत

19प्रकरणों में, पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹एक करोड़से अधिक की निरन्तर बचत थी (**तालिका-2.3**)।

तालिका-2.3

पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरन्तर बचत को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व-दत्तमत						
1	04-न्याय प्रशासन	18.69	16.29	28.57	29.91	28.05
2	05-निर्वाचन	3.82	3.68	3.65	1.03	4.71
3	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	30.52	67.57	56.74	29.52	43.94
4	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	106.16	394.33	418.97	106.35	580.10
5	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	86.33	122.06	91.88	124.39	153.99
6	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	68.45	88.69	47.75	372.80	235.77
7	15-कल्याण	36.41	93.53	80.43	83.72	197.45

8	16-श्रम एवं रोजगार	38.41	35.29	5.61	12.08	12.39
9	18- सहकारिता	1.39	7.72	1.83	4.87	10.30
10	19 ग्राम्य विकास	49.63	45.13	70.21	75.22	92.71
11	22- लोक निर्माण	29.78	51.18	28.64	34.94	35.43
12	23- उद्योग	14.96	13.08	1.34	5.15	14.47
13	24-परिवहन	10.10	11.56	5.62	2.52	1.37
14	26- पर्यटन	0.71	2.31	2.85	2.92	30.66
15	28-पशुपालन	12.18	7.38	8.49	15.53	4.48
पूँजीगत-दत्तमत						
1	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	24.06	45.12	51.24	8.78	72.43
2	11-शिक्षा,खेलकूद,युवा कल्याण एवं संस्कृति	16.97	14.57	7.80	60.20	166.31
3	15-कल्याण	2.15	6.39	5.09	13.74	22.03
4	23-उद्योग	40.58	5.41	9.55	11.54	13.35

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 में उल्लेख किए जाने के बावजूद भी वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण संख्या में निरन्तर बचत के प्रकरण प्रकाश में आये जो निधियों की आवश्यकता से अधिक निर्धारण का सूचक है। इसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

2.3.3 व्ययाधिक्य

पाँच प्रकरणों में, ₹ 4,095.65 करोड़ का समग्र व्यय अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 1,611.40 करोड़ अधिक था और प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था। इसका ब्यौरा **परिशिष्ट-2.2** में दिया गया है। इनमें से निम्न अनुदानों/शीर्षों (**तालिका 2.4**) में पिछले पाँच वर्षों में निरन्तर व्ययाधिक्य देखा गया है:

तालिका-2.4

वर्ष 2007-12 के दौरान निरन्तर व्ययाधिक्य प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य *की राशि*				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पूँजीगत-दत्तमत						
1	17-कृषि कार्य एवं शोध	14.81	11.72	11.73	30.82	18.33
2	25-खाद्य	367.77	564.40	916.31	1,207.14	1,283.25
योग		**382.58**	**576.12**	**928.04**	**1,237.96**	**1,301.58**

इन अनुदानों/शीर्षों में निरन्तर व्ययाधिक्य काल्पनिक बजट आकलनों का सूचक है। अतः सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्ध हेतु, इन शीर्षों के अन्तर्गत निधियों की आवश्यकता का निर्धारण अधिक यथार्थवादी होना चाहिए ताकि भविष्य में निरन्तर व्ययाधिक्य की पुनरावृत्ति न हो।

निरन्तर व्ययाधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2012)।

2.3.4 *बिना प्रावधान के व्यय*

बजट नियमावली के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि यह देखा गया कि, बिना मूल आकलन/अनुपूरक माँग में कोई प्रावधान एवं बिना इसके पुनर्विनियोजन आदेश के प्रभाव के एक प्रकरण में ₹ 4.51 करोड़ का व्यय कर दिया गया, जैसा **तालिका-2.5** में वर्णित है।

तालिका-2.5

वर्ष 2011-12 के दौरान बिना प्रावधान के किये गये व्यय

(₹ करोड़ में)

अनुदान की संख्या एवं नाम	बिना प्रावधान के व्यय की राशि	कारण/अभ्युक्तियाँ
29-उद्यान विकास (पूँजीगत दत्तमत)	4.51	कारण प्रतीक्षित थे

यद्यपि 31 मार्च 2010 तथा 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था, तथापि राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तथा अद्यतन वर्ष के दौरान बजट प्रावधान के बिना इसी शीर्ष में ₹ 4.51 करोड़ का व्यय किया है जो कि अनियमित व अनधिकृत है और इसके विनियमन की आवश्यकता है।

2.3.5 विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए अनुदान/विनियोग पर व्ययाधिक्य का राज्य विधायिका द्वारा विनियमन किया जाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अन्तर्गत, व्यय के विनियमन की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है, व्ययाधिक्य का विनियमन लोक लेखा समिति (पी ए सी) द्वारा विनियोग लेखों पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् किया जाता है। तथापि, 2005-11 के वर्षों के ₹ 5,782.51 करोड़ की राशि के व्ययाधिक्य का राज्य विधानमण्डल द्वारा विनियमन अब तक किया जाना प्रतीक्षित था। विनियमन हेतु लम्बित व्ययाधिक्य की वर्षवार राशि **तालिका-2.6** में सारांशित है:

तालिका-2.6

विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संख्या		प्रावधान से अधिक व्यय की राशि	विनियमन की स्थिति
	अनुदान/विनियोग	अनुदान/विनियोगों के ब्यौरे		
2005-06	7	7,8,17,20,22,25&29	663.50	राज्य सरकार द्वारा स्थिति सूचित नहीं की गयी
2006-07	6	7,17,20,22,25& 29	935.92	
2007-08	6	7,17,20, 22,25 & 29	733.79	
2008-09	6	7,17,20,22,25&29	1,146.41	
2009-10	7	7,17,18,21,22,25&29	1,007.49	
2010-11	9	10,12,15,17,20,21,22,25 & 29	1,295.40	
योग			**5,782.51**	

विगत वर्षों के अनुदानों/तीन विनियोगों में प्रावधान से अधिक किये गये व्यय को राज्य विधायिका द्वारा शीघ्रातिशीघ्र विनियमन कराने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

2.3.6 वर्ष 2011-12 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

तालिका 2.7 में वर्ष 2011-12 के दौरान चार अनुदानों/एक विनियोग में राज्य की संचित निधि (सी एफ एस) से प्राधिकृत से अधिक व्यय ₹ 1,611.40 करोड़ का सार सम्मिलित है।

तालिका-2.7

2011-12 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

(₹ हजार में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
पूँजीगत-दत्तमत					
1	17	कृषि कार्य एवं शोध	1,59,202	3,42,489	1,83,287
2	22	लोक निर्माण	82,59,241	84,59,122	1,99,881
3	25	खाद्य	36,725	1,28,69,264	1,28,32,539
4	29	उद्यान विकास	0	45,138	45,138
पूंजीगत -भारित					
1	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	*1,63,87,300*	*1,92,40,501*	*28,53,201*
योग			**2,48,42,468**	**4,09,56,514**	**1,61,14,046**

राज्य सरकार/विभाग द्वारा व्ययाधिक्य के कारणों को अगस्त 2012 तक सूचित नहीं किया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक किये गये व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा विनियमित कर लेना चाहिए।

2.3.7 अनावश्यक/अधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 37 प्रकरणों में जिसमें प्रत्येक प्रकरण ₹ 10 लाख या उससे अधिक का था, कुल ₹ 813.24 करोड़ प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि अनुदान के अन्तर्गत किया गया व्यय मूल प्रावधान की सीमा के अंदर ही था जैसा **परिशिष्ट-2.3** में वर्णित किया गया है।

₹ 37.72 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान दो प्रकरणों में अपर्याप्त सिद्ध हुआ, यह कमी प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक थी जिससे ₹ 38.32 करोड़ का व्ययाधिक्य अनाच्छादित पड़ा रहा (**परिशिष्ट 2.4**)।

2.3.8 निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक ही अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ बचतें पुर्वानुमानित हों, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो, निधियों का स्थानान्तरण है। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अधिक या अपर्याप्त सिद्ध हुआ और परिणामस्वरूप 25 उपशीर्षों में ₹ 10 लाख और उससे अधिक बचत/आधिक्य हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-2.5** में वर्णित है। इनमें से सिंचाई विभाग की नई परियोजनाओं के नामे अनुदान संख्या 20- सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण- में ₹ 44.67 करोड़ (₹ 20 करोड़ से अधिक) की बचत हुई। बचत के कारण सरकार द्वारा अगस्त 2012 तक उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

उपर्युक्त प्रकरणों में पर्याप्त बचत प्रदर्शित करती हैं कि सम्बद्ध विभागों द्वारा निधियों को व्यय नहीं किया जा सका जैसा कि योजनाओं के अन्तर्गत प्राक्कलित एवं नियोजित था।

2.3.9 पर्याप्त अभ्यर्पण

16 उपशीर्षों में, योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन न किये जाने या धीमे क्रियान्वयन के कारण पर्याप्त अभ्यर्पण (वे प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान का 50 *प्रतिशत* से अधिक अभ्यर्पित किया गया) हुए। इन 16 योजनाओं में ₹ 103.67 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 89.09 करोड़ (85.93 *प्रतिशत*) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें 6 योजनाओं में शत *प्रतिशत* अभ्यर्पण (₹ 8.94 करोड़) सम्मिलित है जैसा कि **परिशिष्ट-2.6** में विस्तारित है।

2.3.10 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

तीन प्रकरणों में, अभ्यर्पित की गयी राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थी, जो इन विभागों में बजटीय नियन्त्रण की कमी को इंगित करती है। इन प्रकरणों में ₹ 85.84 करोड़ की बचत के विरूद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 105.46 करोड़ थी परिणामस्वरूप ₹ 19.62 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण अविवेकपूर्ण किया गया। विवरण **परिशिष्ट-2.7 अ** में दिये गये हैं।

दो मामलों में (कृषि कार्य व अनुसंधान तथा लोक निर्माण) ₹ 38.32 करोड़ के अन्तिम आधिक्य होते हुए भी ₹ 74.13 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया। विवरण **परिशिष्ट-2.7 ब** में दिये गये हैं।

2.3.11 अनुमानित बचत जो अभ्यर्पित नहीं हुई

बजट नियमावली के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों के लिए जब और जैसे ही बचत का पुर्वानुमान हो जाए, आवश्यक है कि अनुदानों/विनियोगों या उनका एक भाग वित्त विभाग को अभ्यर्पित करें। तथापि, वर्ष 2011-12 के अंत में, 09 अनुदान/विनियोजन ऐसे थे जिनमें ₹ 10 करोड़ या अधिक की बचत हुई फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 1,044.45 करोड़ (कुल बचत का 27.00 *प्रतिशत*) थी (**परिशिष्ट-2.8**)।

इसी प्रकार, ₹ 2,628.31 करोड़ की बचत (वे प्रकरण जिसमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक हुई), में से ₹ 925.69 करोड़ अभ्यर्पित किया गया था और परिणाम स्वरूप ₹ 1,702.62 करोड़ (कुल बचत का 44.02 *प्रतिशत*), अभ्यर्पण नहीं हुआ। इसे **परिशिष्ट-2.9** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त 19 प्रकरणों में (₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों का अभ्यर्पण), ₹ 949.34 करोड़ मार्च 2012 के अंतिम दो कार्य दिवसो में अभ्यर्पित किए गए (**परिशिष्ट-2.10**)। यह अभ्यर्पण के अभिप्रेत प्रयोजन की विफलता का परिचायक है क्योंकि यह धनराशि अन्य विकासात्मक कार्यों के प्रयोग में नहीं लायी जा सकी।

2.3.12 व्यय की तीव्रता

वित्तीय विनियम के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय की तीव्रता से बचना चाहिए। इसके विपरीत, **परिशिष्ट-2.11** में सूचीबद्ध 70 उपमुख्य शीर्षों से सम्बन्धित ₹ 10 करोड़ से अधिक या एक वर्ष में किये जाने वाले कुल व्यय का 50 *प्रतिशत* से अधिक के व्यय अन्तिम तिमाही में या मार्च 2012 में किया गया था। **तालिका-2.8** भी उन मुख्य शीर्षों को दर्शाती है जिनमें 50 *प्रतिशत* से अधिक व्यय या तो वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान किया गया था अथवा अन्तिम माह में किया गया था।

तालिका-2.8

वित्तीय वर्ष 2011-12 के समापन के समय व्यय की तीव्रता के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2012 के दौरान व्यय	
			राशि *(₹ करोड़ में)*	कुल व्यय का *प्रतिशत*	राशि *(₹ करोड़ में)*	कुल व्यय की *प्रतिशतता*
1	2015	28.51	21.56	75.62	13.75	48.23
2	2030	27.56	18.47	67.02	13.68	49.65
3	2045	3.74	2.10	56.25	1.08	28.87
4	2251	0.03	0.03	83.96	0.03	80.88
5	2408	199.73	186.05	93.15	182.88	91.56
6	2701	12.39	7.59	61.25	2.78	22.43
7	2810	9.74	5.47	56.14	4.97	51.01
8	3054	156.45	105.61	67.50	95.24	60.87
9	3451	10.34	8.22	79.49	1.01	9.80
10	4059	65.70	33.63	51.19	13.12	19.97
11	4225	11.93	6.41	53.74	5.19	43.46
12	4235	4.16	3.25	78.14	0.00	0.03
13	4406	16.36	15.56	95.11	12.84	78.51
14	4700	234.70	127.40	54.28	75.79	32.29
15	4702	201.67	110.16	54.63	75.02	37.20
16	4711	15.44	9.77	63.28	0.86	5.61
17	5055	41.67	21.67	52.00	21.67	52.00
योग		**1,040.12**	**682.95**	**65.66**	**519.91**	**49.99**

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 के दौरान इन मुख्य शीर्षों के कुल व्यय ₹ 1,040.12 करोड़ का 65.66 *प्रतिशत* वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में व्यय किया गया। आगे, उपर्युक्त नौ विशिष्ट प्रकरणों में, ₹ 10 करोड़ से अधिक का व्यय अकेले माह मार्च 2012 में किया गया था।

वित्तीय विनियमन के दृष्टिकोण के विपरीत सरकार द्वारा भारी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अन्त में किया गया जो व्यय पर कमजोर वित्तीय नियन्त्रण का सूचक था। ठोस वित्तीय प्रबन्धन के लिए व्यय में एकरूपता बनाये रखा जाना चाहिए।

2.4 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

2.4.1 सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रस्तुतीकरण लम्बित रहना

वित्तीय नियम के अनुसार, प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक सार आकस्मिक बिल (ए सी बिल) में यह सत्यापित करना होता है कि चालू माह की पहली तिथि से पहले के उसके द्वारा आहरित सभी आकस्मिक

प्रभारों के विस्तृत बिल सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षर हेतु अग्रेषित और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित कर दिये गये हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान, ₹ 5.44 करोड़ के ए सी बिलों के विरूद्ध केवल ₹ 1.88 करोड़ के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों (डी सी बिलों) की राशि ही प्राप्त हुई, जिससे जून 2012 तक ₹ 45.03 करोड़ के ए सी बिलों का निस्तारण अवशेष पड़ा रहा। वर्षवार विवरण **तालिका-2.9** में दिया गया है।

तालिका-2.9

सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रस्तुतीकरण लम्बित रहना (जून 2012 के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए सी बिलों की राशि	डी.सी. बिलों की राशि	अवशेष ए सी बिल	
			संख्या	राशि
2009-10	1.41	0.07	14	1.34
2010-11	72.14	32.01	151	40.13
2011-12	5.44	1.88	150	3.56
योग	**78.99**	**33.96**	**315**	**45.03**

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

जैसा कि ऊपर तालिका से देखा जा सकता है, जून 2012 के अंत तक 315 ए सी बिलों की कुल अवशेष धनराशि ₹ 45.03 करोड़ थी। आगे यह भी पाया गया कि कुल बकाया ₹ 45.03 करोड़ में से 28 ए सी बिलों के ज़रिये सचिव, राजस्व व सामान्य प्रशासन द्वारा भारी धनराशि ₹ 16.29 करोड़ (36 *प्रतिशत*) आहरित की गयी (2010-11 के दौरान) तथा डी सी बिलों के अप्रस्तुतीकरण के नामे अभी तक बकाया थी। 2011-12 के कुल बकाया ए सी बिलों में से (₹ 3.56 करोड़), भारी धनराशि ₹ 1.98 करोड़ चुनाव विभाग (56 *प्रतिशत*) से सम्बन्धित थी। वर्ष 2011-12 तक विभागवार लम्बित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों के जो 30 जून 2012 तक के डी सी बिलों के लम्बन को दर्शाता विवरण **परिशिष्ट-2.12 में** दिया गया है।

सार आकस्मिक बिल आहरित किए जाने के बाद लम्बे समय तक विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्रस्तुत न किये जाने से दुर्विनियोजन का जोखिम है और इसलिये इसके सघन अनुश्रवण की आवश्यकता है।

2.4.2 असमाधानित व्यय

व्यय को बजट आवंटनों के अन्तर्गत रखने और उनके लेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को सशक्त करने के लिए वित्तीय नियमों में निहित है कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह उनके अभिलेखों में दर्ज व्यय का समाधान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों में दर्ज व्यय से किया जाना चाहिए। यद्यपि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से विभाग के आँकड़ों के असमाशोधन को इंगित किया जाता रहा है फिर भी इस

सम्बन्ध में नियंत्रण अधिकारियों के पक्ष से चूकें वर्ष 2011-12 के दौरान भी निरंतर जारी रहीं। लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि 13 नियंत्रण अधिकारियों से सम्बन्धित ₹ 10 करोड़ से अधिक के प्रकरण जिनमें ₹ 5,201 करोड़ शामिल हैं, वर्ष 2011-12 के दौरान असमाधानित रहे जो कुल शुद्ध व्यय ₹ 15,539 करोड़ का 33 *प्रतिशत* थे जैसा **तालिका 2.10** में वर्णित हैः

तालिका-2.10

नियंत्रण अधिकारियों की सूची जहाँ 2011-12 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि पूर्णतः असमाधानित रही

(₹ करोड़ में)

क्रमाँक	नियन्त्रण अधिकारी	राशि जिसका समाधान नहीं किया गया
1	सचिव, राजस्व विभाग	192.31
2	सचिव, प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन	101.41
3	प्रमुख सचिव, वित्त/प्रमुख सचिव राज्य सम्पत्ति विभाग	1,766.85
4	निदेशक, कोष व वित्तीय सेवाएँ (निदेशक, लेखा व हकदारी)	1,170.71
5	सचिव, रोजगार	31.83
6	सचिव, लोक सेवा आयोग	13.41
7	सचिव, शिक्षा	197.66
8	सचिव, खेल व युवा कल्याण, देहरादून	151.97
9	प्रमुख सचिव, चिकित्सा/प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	746.32
10	सचिव, श्रम	88.68
11	सचिव, ऊर्जा	51.74
12	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी	53.91
13	प्रमुख सचिव, सामाजिक कल्याण	634.54
योग		**5,201.34**

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

₹ 5,201 करोड़ की भारी रकम का वर्ष 2011-12 के दौरान असमाधानित रह जाने के मुख्य कारण, समाधान हेतु नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा पहल न किया जाना था।

इस प्रकार, गबन तथा निधियों के दुरुपयोग की संभावनाओं के निवारण हेतु सरकार को चाहिए कि संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखाओं के समाधान को सुनिश्चित करें।

2.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना, उत्तराखण्ड आकस्मिक निधि अधिनियम 2001 (2001 के अधिनियम सं0 2) के अन्तर्गत की

गयी है। इस निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और तात्कालिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने हेतु मात्र लेना चाहिए, जिन्हें विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित रखना अवांछनीय होगा। यह निधि एक अग्रदाय के स्वरूप की है तथा इसका वर्तमान संग्रह ₹ 200 करोड़ है (वर्ष के दौरान संग्रह को ₹ 600 करोड़ से ₹ 200 करोड़ तक कम कर दिया गया था)। इस निधि से किसी अग्रिम आहरण की उसी वित्त वर्ष में प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। तथापि, ₹ 69.07 करोड़ के अग्रिम आकस्मिकता निधि से आहरित किये गये जो 31 मार्च 2012 तक समायोजित किये जाने शेष थे जैसा कि नीचे **तालिका 2.11** में दिया गया है।

तालिका-2.11

वर्ष 2011-12 के दौरान आकस्मिकता निधि से किया गया व्यय जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं हुई

(₹ करोड़ में)

क्रमाँक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	पुनर्विनियोग / अभ्यर्पण	योग	वास्तविक व्यय	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	स्वीकृति का माह
1	03	**2013-मंत्रीमण्डल**	62.76	(-)0.98	61.78	61.46	0.94	08/2011 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 & 02/2012
2	06	**2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ**	46.51	(-)0.26	46.25	40.78	0.25	08/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 & 02/2012
3	14	**2220-सूचना व प्रचार**	38.27	(-)1.94	36.33	36.17	6.80	02/2012 & 03/2012
4	17	**6401-कृषि कर्म के लिए ऋण**	15.40	(-)0.40	15	15.00	15.53	09/2011
5	18	**2425-सहकारिता**	42.31	(-)11.47	30.84	32.01	5.14	08/2011 12/2011 01/2012 02/2012 & 03/2012
6	19	**2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम**	319.96	(-)40.00	279.96	240.72	0.15	08/2011
7	19	**4515--अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय**	213.88	0	213.88	147.84	36.16	11/2011 & 12/2011
8	24	**3053-नागरिक विमानन**	6.67	(-)1.18	5.49	5.09	3.41	12/2011 & 02/2012
9	25	**3456-नागरिक पूर्तियाँ**	4.15	0	4.15	2.82	0.09	06/2011
10	26	**5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय**	47.28	0	47.28	28.08	0.50	12/2011
11	28	**2403-पशुपालन**	90.74	0	90.74	87.96	0.10	01/2012
योग			**887.93**	**(-)56.23**	**831.70**	**697.93**	**69.07**	

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि ₹ 69.07 करोड़ के व्यय वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से अग्रिमों के रूप में किये गये तथा उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (वर्ष 2001 के अधिनियम सं. 2) की धारा 5 के अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार इसकी प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान नहीं की गई थी।

सरकार ने वर्ष के दौरान, पूँजीगत व्यय (₹ 37 करोड़) तथा कृषि पालन (₹ 16 करोड़) कार्य हेतु वितरित ऋणों की पूर्ति हेतु आकस्मिकता निधि से अग्रिमों का आश्रय लिया, जो प्रत्याशित थे तथा इसी कारणवश वित्तीय प्रबन्धन के विपरीत थे।

2.6 बजट प्रक्रिया में कमियाँ

वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रियाओं में पायी गई कमियां निम्नानुसार थीः

- लघु शीर्ष 900-क्षेत्र-अ, कर-राजस्व के अन्तर्गत वसूली को दिखाया गया है जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची (खण्ड-I) प्रावधान करती है कि लघु शीर्ष-900 वसूली क्षेत्र-अ, कर-राजस्व के अधीन आने वाले प्रत्येक मुख्य, उप मुख्य व लघु शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जायेगा।
- मुख्य शीर्ष 3454 के अन्तर्गत, लघु शीर्ष 001-निदेशन एवं प्रशासन को मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची में यथोपबन्धित 01-जनगणना की बजाय उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण के नीचे दर्शाया गया है।
- अनुदान संख्या 14 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष 4059 के नीचे, उपमुख्य शीर्ष 60 को 'अन्य' के रूप में दर्शाया गया है। इसे मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची में यथोपबन्धित 'अन्य भवन' के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- अनुदान संख्या 22 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष 2059 में, उपमुख्य शीर्ष 80 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 102 को 'मरम्मत एवं अनुरक्षण' के रूप में दर्शाया गया है, जबकि इसे मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार उपमुख्य शीर्ष 80 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 053 के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
- मुख्य शीर्ष 2245 के अन्तर्गत उपमुख्य शीर्ष 05 को दर्शाया गया है, जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची में उपबन्धित अनुसार दो और उपमुख्य शीर्ष 01- सूखा तथा 02- बाढ़ व चक्रवात, हैं।
- मुख्य शीर्ष 2217 के अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष-04 को 'कस्बों का एकीकृत विकास'- के रूप में दर्शाया गया है जबकि इसे 'झुग्गियों का विकास' के रूप में, मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची में प्रावधानित अनुसार, अंकित किया जाना चाहिए था।
- मुख्य शीर्ष 4235 में, 'अपंगों का कल्याण' लघु शीर्ष 104 के अन्तर्गत दर्शाया गया है जबकि इसे 'वृद्धों, अशक्तों एवं निराश्रितों का कल्याण' होना चाहिए। मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार 'अपंगों का कल्याण' लघु शीर्ष 101 में दर्शाया जाना चाहिए।
- अनुदान संख्या 17 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2402 में लघु शीर्ष 101 एवं 102 को क्रमशः 'मृदा संरक्षण एवं परीक्षण' एवं 'जल संरक्षण' के रूप में दर्शाया गया है, जबकि इन्हें मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार 'मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण' व 'मृदा संरक्षण' के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
- पूर्ववर्ती रिपोर्ट में सूचित किया जाने के बाबजूद भी राज्य सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया है।

2.7 चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण व संस्कृति का समीक्षा हेतु चयन किया गया था जिससे निम्नलिखित उदघाटित हुआः

व्यय की तीव्रता

सामान्य वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि वर्ष के दौरान व्यय, माहवार/त्रैमासिक प्रवाह को ध्यान में रखते हुए एक समान रूप से किया जाना चाहिए। अनुदान संख्या 11 (शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण व संस्कृति) के प्रकरण में उदघाटित हुआ कि 2011-12 के दौरान निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व्यय के समरूप प्रवाह को बनाये नहीं रखा गया जिससे व्यय में तीव्रता आई। विवरण नीचे दर्शाया हैः

तालिका-2.12

अन्तिम तिमाही/मार्च 2012 माह में व्यय की तीव्रता

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष (दत्तमत)	अन्तिम तिमाही में व्यय	मार्च में व्यय	2010-11 के दौरान कुल व्यय	अन्तिम तिमाही में व्यय का *प्रतिशत*	मार्च में व्यय का *प्रतिशत*
1.	2203	35.17	22.37	78.00	45.09	28.68
2.	2204	12.15	6.48	35.06	34.65	18.48
3.	2205	4.37	2.53	11.67	37.45	21.68
योग		**51.69**	**31.38**	**124.73**	**41.44**	**25.16**

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

2011-12 की अन्तिम तिमाही में इस अनुदान के अन्तर्गत तीन मुख्य शीर्षों में व्यय इस तथ्य के साथ कुल व्यय का 41.44 *प्रतिशत* था कि इन शीर्षों में कुल व्यय का 25.16 *प्रतिशत* व्यय अकेले मार्च 2012 में किया गया था जिससे व्यय में तीव्रता आई। यह सरकार के वित्त विभाग द्वारा व्यय को विनियमित करने में आयोजना एवं नियंत्रण का अभाव इंगित करता है।

वर्ष की समाप्ति पर व्यय की तीव्रता निष्फल, निरर्थक या दुर्नियोजित व्यय को बढ़ावा दे सकती है। विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जहाँ तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय करने में तीव्रता से बचने हेतु यथानिर्धारित पूरे वर्ष में एक समान रूप से व्यय किया जाये।

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

एक वित्तीय वर्ष के दौरान, अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत अतिरिक्त निधि की आवश्यकता की मध्यकालिक समीक्षा के उपरान्त पूर्वानुमानित व्ययाधिक्य को पूरा करने हेतु अनुपूरक अनुदान लिये जाते है। तथापि, यह देखा गया कि अनुदान संख्या 11 के दो मुख्य शीर्षों के अधीन, बिना किसी उचित नियोजन के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किये गये थे जैसा नीचे **तालिका-2.13** में सारणीबद्ध हैः

तालिका-2.13

अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त अनुपूरक प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				वास्तविक व्यय	बचत
	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
2203	101.14	12.77	00	113.91	77.52	(-)36.39
4202	271.04	16.22	(-)68.58	218.68	120.95	(-)97.73
योग	**372.18**	**28.99**	**(-)68.58**	**332.59**	**198.47**	**(-)134.12**

अनुदान संख्या 11 के अन्तर्गत दो मुख्य शीर्षों हेतु लिये गये ₹ 28.99 करोड़ अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि दो मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत/सम्पूर्ण बचत स्वयं विभाग द्वारा प्राप्त अनुपूरक अनुदान से अधिक थी। मुख्य शीर्ष - 4202 के अन्तर्गत लिए गए मूल अनुदान का मुख्य भाग ₹ 97.73 करोड़ (36.06 *प्रतिशत*), ₹ 68.58 करोड़ के पुनर्विनियोजन के बावजूद भी विभाग द्वारा अव्ययित रह गया।

निधियों का उचित उपयोग करने हेतु उचित तंत्र सरकार लागू कर सकती है।

अप्रयुक्त प्रावधान

विभिन्न विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के संचालन हेतु वार्षिक वित्त विवरणी में विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए प्रावधान है। अनुदान संख्या 11 में यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्त तक सम्पूर्ण बजट प्रावधान के उपशीर्ष 4202-01-202-19 के अधीन ₹ 1.50 करोड़ अप्रयुक्त रहा। यह सूचित करता है कि आकलित एवं आयोजित अनुसार व्यय किया न जा सका। इसमें निधियों के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

2.8 निष्कर्ष

विभिन्न अनुदानों एवं विनियोगों में ₹ 3868.22 की बचत चार अनुदानों व एक विनियोग में ₹ 1611.40 करोड़ के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई। परिणामस्वरुप ₹ 2256.82 करोड़ की समग्र बचत हुई।

वर्ष के दौरान चार अनुदानों व एक विनियोग के अन्तर्गत पाँच मामलों में अनुमोदित प्रावधान पर ₹ 1,611.40 करोड़ के व्ययाधिक्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

न्यायिक प्रशासन, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, वित्त कर नियोजन, ऊर्जा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, आवासन एवं शहरी विकास, कल्याण, ग्राम्य विकास तथा लोक निर्माण अनुदानों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरन्तर भारी बचत दर्शायी गयी। निधियों का अपर्याप्त प्रावधान और अनावश्यक/अधिक पुनर्विनियोजन के प्रकरण भी थे। अन्तिम तिमाही/वित्त वर्ष के अन्त में व्यय की तीव्रता विभागों में अपर्याप्त बजट नियन्त्रण या इसके अभाव को इंगित करती है। बहुत से प्रकरणों में, पूर्वानुमानित

बचत या तो अभ्यर्पित नहीं की गयी थीं या वर्ष के अन्त में मार्च माह में समर्पित की गयीं जिसके कारण दूसरे विकासात्मक उद्देश्यों हेतु इन निधियों के उपयोग की संभावना नहीं बची थी। आकस्मिकता निधि से स्वीकृत आहरण (यद्यपि कई प्रकरणों को तात्कालिक प्रकृति का न होने के बावजूद आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया था) तथा वर्ष के अन्त तक उसका समायोजन नहीं हुआ था।

वित्तीय प्रबन्धन में इस प्रकार की कमियों से बचने के लिये बजटीय नियन्त्रणों का कड़ाई से पालन किया जाए। अन्तिम क्षणों में निधियों की अवमुक्ति और पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण के आदेशों को जारी करने से बचना चाहिए। सरकार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति केवल अप्रत्याशित एवं तात्कालिक प्रकृति के व्यय को वहन करने के लिए मात्र प्रदान करें तथा निधियों के समय पर समायोजन की प्रणाली को कारगर बनाना चाहिए। नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा कठोर अनुश्रवण तन्त्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि नियत समय सीमा के अन्तर्गत सार आकस्मिकता बिलों के समायोजन को सुनिश्चित किया जा सके।

2.9 संस्तुतियाँ

सरकार यह सुनिश्चित करे कि :

- सभी विभागों को चाहिए कि भारी बचत/आधिक्यों से बचने से बचने के लिए व्यय की रूझान तथा निधियों की वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए यथार्थवादी बजट आकलन प्रस्तुत करें।
- सभी विभागों को चाहिए कि आवंटनों के सापेक्ष व्यय का निकट अनुश्रवण करें तथा अनुदानों पर हो रहे व्ययाधिक्य से कड़ाई तरीके से बचें।
- सभी अनुभागों को चाहिए कि पहले से ही बचतों की संगणना करें तथा उनके अभ्यर्पण नियत तिथि तक करें ताकि निधि की आवश्यकता वाले अन्य विभागों द्वारा इनका प्रभावी उपयोग हो सके।
- प्रचालित नियमों के अन्तर्गत सार आकस्मिकता बिलों पर आहरित अग्रिमों को नियत अवधि के अन्दर समायोजित करने हेतु विभागों में अनुश्रवण तन्त्र लागू हो।

अध्याय- 3

वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचनाओं सहित अच्छी आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, कार्यविधि तथा अनुदेशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसी अनुपालनाओं की स्थिति पर प्रतिवेदन की समयपरक गुणवत्ता, सुशासन के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अनुपालन एवं नियन्त्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली और क्रियात्मक हों तो, रणनीतिक आयोजना, निर्णयन तथा शेयर धारकों के उत्तरदायित्व जैसे प्रबंधात्मक उत्तरदायित्वों की पूर्ति में राज्य सरकार को सहायता पहुँचाते हैं। यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधि एवं अनुदेशों की राज्य सरकार द्वारा की गई अनुपालना की स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

वित्तीय नियमावली में उपबंध है कि विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदत अनुदानों के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये जाने चाहिए तथा सत्यापन के पश्चात उन्हें अन्यथा विनिर्दिष्ट न होने पर, संस्वीकृति तिथि से 18 माहों के अन्दर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। अगस्त 2012 तक ₹ 496.34 करोड़ की राशि के पाँच सौ पच्चीस उपयोगिता प्रमाणपत्र लम्बित थे। इनमें से, ₹ 417.84 करोड़ धनराशि के 385 उपयोगिता प्रमाण पत्र (73.33 *प्रतिशत*) तीन वर्षों तक की अवधि से लम्बित थे तथा तीन वर्षों से ऊपर के ₹ 78.50 करोड़ धनराशि के 140 उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में अवधि-वार विलम्ब **तालिका 3.1** में सारांशित हैः

तालिका-3.1

अगस्त 2012 को उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अवधि-वार बकाये

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्षों की संख्या में विलम्ब की सीमा	लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि
1	0-1	139	131.19
2	1-3	246	286.65
3	3-5	140	78.50
योग		**525**	**496.34**

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या प्राप्तकर्ता ने अभीष्ट उद्देश्य पर ही अनुदान का उपयोग किया है, जिस हेतु उनकी स्वीकृति दी गयी थी। इस प्रकार, प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के शीघ्र प्रस्तुतीकरण हेतु विभागों द्वारा प्रयास किए जाएँ।

3.2 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

अर्द्ध वाणिज्यिक प्रकृति के कार्यकलाप वाले कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षित है कि वे विहित प्रपत्र में वार्षिक रूप से वित्तीय कार्यकलापों के कार्य-चालन परिणाम प्रदर्शित करते हुये प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनके क्रियाकलापों का आकलन कर सके। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के वार्षिक अन्तिमीकृत लेखे, उनके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य तथा अपने कारोबार को संचालित करने में कार्य कुशलता को दर्शाते हैं। लेखों को समय पर अन्तिम रूप न दिये जाने के अभाव में, सरकारी निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान मण्डल की संवीक्षा के अन्तर्गत नहीं आ पाते। परिणामतः, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने व कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु यदि कोई सुधारात्मक उपाय अपेक्षित हों तो वे समय पर नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त, सभी तरह के विलम्ब से, व्यवस्था में हर समय धोखाधड़ी व सार्वजनिक धन के निःस्राव की सम्भावना बनी रहती है।

सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसे उपक्रम अपने लेखे तैयार करें तथा विहित समय सीमा के अन्तर्गत लेखापरीक्षार्थ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करें। सितंबर 2012 तक, तीन ऐसे उपक्रमों में से दो ने लेखे तैयार नहीं किए थे तथा उनके लेखे वर्ष 2003-04 व उसके बाद से बकाये थे। *प्रोफार्मा लेखे* तैयार करने के बकाये व सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति **परिशिष्ट-3.1** में दी गयी है।

लेखे को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से, वित्तीय अनियमितता के जोखिम का पता नहीं लगता, अतः लेखे को तैयार कर लेखापरीक्षा को शीघ्रतम प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

3.3 दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि

लेखापरीक्षा ने मार्च 2012 तक ₹ 3.93 करोड़ की सरकारी राशि के दुर्विनियोग, गबन व चोरी आदि के 17 प्रकरण पाए जिन पर अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार विवरण तथा अवधि-वार विश्लेषण **परिशिष्ट-3.2** में दिया गया है तथा इन मामलों की प्रकृति **परिशिष्ट-3.3** में दी गई है। लम्बित मामलों का अवधि-वार विवरण तथा प्रत्येक संवर्ग में चोरी तथा दुर्विनियोग/हानि के लम्बित मामलों की संख्या को **तालिका 3.2** में सारांशित किया गया है।

तालिका-3.2

31 मार्च 2012 के अनुसार दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि के मामलों की रूपरेखा

लम्बित मामलों का अवधि-वार विवरण			लम्बित मामलों की प्रकृति		
सीमा वर्षों में	मामलों की संख्या	सन्निहित धनराशि (₹ लाख में)	मामलों की प्रकृति/विशिष्टियाँ	मामलों की संख्या	सन्निहित धनराशि (₹ लाख में)
0 - 5	17	392.79	चोरी	02	4.13
5 - 10	---	---			
10 - 15	---	---	दुर्विनियोग/माल की हानि	15	388.66
15 - 20	---	---			
20 - 25	---	---	**योग**	**17**	**392.79**
25 से अधिक	---	---	वर्ष के दौरान अपलिखित हानियों के मामले	--	--
योग	**17**	**392.79**	**कुल लम्बित मामले**	**17**	**392.79**

इनमें से ₹ 50.55 लाख की चोरी, दुर्विनियोग/हानि के चार मामले अन्तिम कार्रवाई हेतु शिक्षा विभाग के पास अनिर्णित पड़े थे जबकि ₹ 301.49 लाख की पर्याप्त राशि के छः मामलों को समाज कल्याण विभाग, पशुपालन विभाग तथा वन विभाग द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना प्रतीक्षित था।

इस प्रकार एक प्रभावपूर्ण पद्धति को दुर्विनियोग, हानि व चोरी के प्रकरणों के शीघ्रतम निस्तारण हेतु स्थापित करने और भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3.4 लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियाँ' तथा 'अन्य व्यय' के अधीन बुकिंग

2011-12 के दौरान 50 मुख्य लेखा शीर्षों (सरकार के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए) के अन्तर्गत ₹ 3,438.94 करोड़ राजस्व लेखा में लघु शीर्ष 'अन्य व्यय' - जो कुल राजस्व व्यय, संबंधित मुख्य शीर्षों के अधीन अभिलिखित - का 26.50 *प्रतिशत* अंश बनता है - के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, 37 मुख्य लेखा शीर्षों (सरकार के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए) के अन्तर्गत कुल राशि ₹ 1,266.23 करोड़ राजस्व लेखा में लघु शीर्ष 'अन्य प्राप्तियाँ', जो कुल राजस्व प्राप्तियों - संबंधित मुख्य शीर्षों के अधीन

अभिलिखित- के 9.25 *प्रतिशत* अंश बनता है, के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। पाँच मुख्य लेखा शीर्षों में व्यय राशि प्रचुर मात्रा में 'अन्य व्यय' के अधीन बुक की गई थी तथा 15 मुख्य लेखा शीर्षों में प्राप्तियों की प्रचुर रकम 'अन्य प्राप्तियाँ' के अधीन बुक की गई थी। वित्तीय लेखाओं में मुख्य योजनाओं का अलग से आरेखण नहीं किया है, तथापि इन लेखाओं के विवरण उप-शीर्ष (योजना) स्तर या निम्न में, अनुदानों के विवरणात्मक माँगों में तथा संबन्धित शीर्ष-वार विनियोजित लेखाओं में सरकार लेखाओं के भाग बनकर आरेखित है।

लघु शीर्ष '800'-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अधीन भारी रकम का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन कार्य में पारदर्शिता/शुद्ध चित्रण को प्रभावित करता है।

3.5 निष्कर्ष

सरकार द्वारा सूत्रबद्ध विभिन्न नियम, कार्यविधियाँ तथा निदेशनों के अनुपालन के संबन्ध में परिकल्पना के अनुसार सरकारी विभागों के अन्दर आन्तरिक नियंत्रण तंत्र कार्यरत नहीं है। विभागीय तौर पर प्रबन्धित सरकारी उपक्रमों द्वारा वार्षिक कच्चे लेखाओं के उपक्रम की मूल आवश्यकताओं के अनुपालन खामियों में तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा ए सी बिलों पर आहरित भारी रकम के असमायोजन में, वित्तीय प्रतिवेदन कार्य परिशुद्ध तथा विश्वासयोग्य नहीं हो सकता। विभिन्न अनुदानित संस्थाओं को दिए गए ऋणों तथा अनुदानों के विरूद्ध प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब सूचित करता है कि सरकार के अनुश्रवण तंत्र के सशक्तीकरण आवश्यक है जैसे 525 की संख्या में 496.34 करोड़ की यू सी जो प्रस्तुतीकरण हेतु नियत थे-प्रधान महालेकार (लेखा व हकदारी) को, लेखाओं के पुन:समाधान तथा निधियों के उचित उपयोग पर निगरानी रखने हेतु, प्रस्तुत नहीं किए गए।

हानि/दुर्विनियोग व चोरी के प्रकरणों में विभागीय जाँचों में दोषियों को दण्डित करने हेतु तेजी लानी चाहिए। भविष्य में इसप्रकार के प्रकरणों को रोकने के लिए सभी संगठनों में आन्तरिक नियंत्रणों में मजबूती लानी चाहिए।

3.6 संस्तुतियाँ

सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु विचार कर सकती है कि :

- अनुदानित संस्थाओं को विशेष प्रयोजन हेतु अवमुक्त अनुदानों के संबन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से प्रस्तुत हों।
- सभी गबन व दुर्विनियोजन प्रकरणों संबंधी विभागीय जाँच में गति लाएँ तथा इन प्रकरणों को रोकने के लिए सभी संगठनों में आन्तरिक नियंत्रणों का सशक्तिकरण करें।
- लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' तथा '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अधीन मुख्य योजनाओं के प्राप्तियों तथा व्यय को सम्मिलित करने के स्थान पर वित्तीय प्रतिवेदन कार्य में शुद्धता लाएँ।

देहरादून (**अश्विनी अत्रि**)
दिनांक **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली (**विनोद राय**)
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट-1

(संदर्भः उत्तराखण्ड का परिचय; पृष्ठ-1)

राज्य का परिचय (उत्तराखण्ड)

अ. सामान्य आँकड़े:

क्रम संख्या	विवरण		आँकड़े
1	क्षेत्रफल		53,483 वर्ग किमी
2	जनसंख्या		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	101.17 लाख
3	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
4	*गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल) (अखिल भारतीय औसत = 27.5 *प्रतिशत*)		*39.60 प्रतिशत*
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 *प्रतिशत*)	*71.60 प्रतिशत*
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 74.0 *प्रतिशत*)	*79.63 प्रतिशत*
6	शिशु मृत्यु** (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 47 प्रति 1000 जीवित जन्म)		38
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा*** (अखिल भारतीय औसत = 63.5)		63.50
8	गिनी गुणांक****		
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.30)	0.28
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय = 0.37)	0.32
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) 2011-12 चालू मूल्य पर		95,201
10	प्रति व्यक्ति जी एस डी पी सी ए जी आर (2002-03 से 2011-12)		17.57 *प्रतिशत*
11	जी एस डी पी सी ए जी आर (2002-03 से 2011-12)		*19.41 प्रतिशत*
12	जनसंख्या वृद्धि (2002-03 से 2011-12)		16.03

ब : वित्तीय आँकड़े

सी ए जी आर (2002-03 से 2011-12)			
विवरण		**आँकड़े (*प्रतिशत* में)**	
सी ए जी आर		**2002-03 से 2010-11**	**2002-03 से 2011-12**
क	राजस्व प्राप्तियों का	17.40	17.46
ख	राजस्व कर का	20.11	20.91
ग	करेत्तर राजस्व का	7.68	13.11
घ	कुल व्यय	16.07	15.92
ड़	पूँजी व्यय	23.67	23.81
च	सामान्य शिक्षा में राजस्व व्यय	16.35	15.51
छ	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में राजस्व व्यय	18.52	17.95
ज	वेतन	20.87	19.74
झ	पेंशन	30.59	26.63

*सामान्य आँकड़ों का स्रोतः बी पी एल (योजना आयोग तथा एन एस एस ओ आँकड़ें, 61 चक्र।

**शिशु मृत्यु दर (एस आर एस बुलेटिन जनवरी 2011), वित्तीय आँकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखे पर आधारित हैं।

*** जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय; गृह मंत्रालय), आर्थिक रिव्यू 2010-11।

****गिनी गुणांक (योजना आयोग तथा एन.एस.एस.ओ. आँकड़ों के अनौपचारिक आकलन, 61 चक्र 2004-05 एम आर पी)।

गिनी गुणांक जनसंख्या में आय की असमानता का माप है। मूल्य दर शून्य से एक हैं, शून्य के समीप असमानता कम हैं; एक के समीप असमानता अधिक है।

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भः प्रस्तर 1.2.1; पृष्ठ-5)

भाग अः सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना

सरकारी लेखों की संरचनाः राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।

भाग- I: समेकित निधिः राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियाँ, ट्रेजरी बिलों के जरिये जुटाए गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि, एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।

भाग- II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि एक प्रकार का अग्रदाय है जो अति आवश्यक आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम देने के लिये विधायिका द्वारा प्राधिकृत होने तक राज्यपाल के स्वेच्छा पर रखा जाता है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग- III: लोक लेखा: कतिपय लेनदेनों से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का अंश नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते है और जिन्हें राज्य विधायिका द्वारा वोट की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट-1.1-क्रमशः

भाग ब: वित्त लेखे का विन्यास	
विवरण	**विन्यास**
खण्ड 1	
विवरण संख्या-1	वित्तीय स्थिति का विवरण।
विवरण संख्या-2	प्राप्ति तथा संवितरण का विवरण।
विवरण संख्या-3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण।
विवरण संख्या-4	समेकित निधि से व्यय का विवरण। लेखे पर कार्य एवं प्रकृति टिप्पणी।
परिशिष्ट I:	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश।
खण्ड 2 **भाग** -I	
विवरण संख्या-5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण।
विवरण संख्या-6	उधारियाँ तथा अन्य दायित्वों का विवरण।
विवरण संख्या-7	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का विवरण।
विवरण संख्या-8	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान का विवरण।
विवरण संख्या-9	सरकार द्वारा दिये गये प्रतिभूति का विवरण।
विवरण संख्या-10	दत्तमत्त तथा प्रभारित व्यय का विवरण।
भाग -II	
विवरण संख्या-11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-12	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-13	लघु शीर्षों द्वारा पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-14	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-15	उधारियाँ तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-16	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-17	राजस्व लेखा को छोड़कर व्यय के लिए निधि के स्रोतों तथा उपयोगों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-18	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-19	नैमित्तिक निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरण।
भाग -III	
परिशिष्ट	
II	वेतन पर तुलनात्मक व्यय।
III	उपदान पर तुलनात्मक व्यय।
IV	सहायतित अनुदान (योजनावार व संस्थावार)।
V	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ।
VI	योजनागत स्कीम व्यय(केन्द्रीय एवं राज्य योजनागत योजनायें)।
VII	राज्य में केन्द्रीय योजना निधियों का कार्यदायी अभिकरणों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण।
VIII	शेषों का सारांश।
IX	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम।
X	अपूर्ण निर्माण कार्य।
XI	वेतन व गैर-वेतन अंश को पृथक्-पृथक् दर्शाते हुए अनुरक्षण व्यय।

परिशिष्ट-1.2

भाग अ

(संदर्भः प्रस्तर 1.5.1; पृष्ठ- 20)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि

एकवर्गीय राजकोषीय समुच्चयों के लिए अनुमानों सहित चयनित राजकोषीय आँकड़ों के लिए तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएँ तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके राजकोषीय दायित्व अधिनियम में तथा अन्य विवरणों में, जो अधिनियम के अन्तर्गत विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित है. (**परिशिष्ट- 1.2 का भाग ब**)। वचनबद्धताएँ/अनुमान, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों के प्रवृत्तियों तथा स्वरूपों के गुणात्मक मूल्याँकन करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी), राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य सम्पादन का अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व और राजकोषीय घाटे को चालू बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के *प्रतिशत* के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जी एस डी पी द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बन्धित राजकोषीय आँकड़ों हेतु उत्प्लावकता गुणांक यह निर्धारित करने के लिए आगणित किया जाता है कि क्या संसाधनों का जुटाव, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ-साथ चलते हैं अथवा ये राजकोषीय समुच्चय, जी एस डी पी के अलावा दूसरे कारकों से भी प्रभावित हैं।

विगत पाँच वर्षों हेतु जी एस डी पी की प्रवृत्तियाँ नीचे दर्शाई हैः

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियाँ

	2007-08	2008-09	2009-10♣	2010-11▼	2011-12▲
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	45,856	56,025	70,851	82,460	95,201
जी एस डी पी की वृद्धि दर	24.62	22.18	26.46	16.39	15.45

स्रोतः निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड

♣ अनन्तिम आगणन ▼ त्वरित आगणन ▲ अग्रिम आगणन

राजकोषीय क्षमता के आगणन हेतु पद्धति

राज्य सरकार की राजकोषीय क्षमता का आगणन करने के लिए, तेरहवें वित्त आयोग में दी गयी निम्न पद्धति अपनाई गयी।

चरण 1: कुल व्यय-जी एस डी पी और पूँ व्यय/वि व्यय/सा से व्यय- कुल व्यय के राष्ट्रीय औसत की गणना करें।

चरण 2: कुल व्यय-जी एस डी पी अनुपात के राष्ट्रीय औसत पर आधारित, कुल व्यय की गणना करें जिससे किसी भी राज्य में कुल व्यय-जी एस डी पी अनुपात, राष्ट्रीय औसत से कम न हो, अर्थात, यदि

कुल व्यय/जी एस डी पी = X

कुल व्यय=X*जी एस डी पी .....(1)

जहाँ X, कुल व्यय-जी एस डी पी अनुपात का राष्ट्रीय औसत है।

जहाँ कहीं भी राज्यों का कुल व्यय-जी एस डी पी अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किये गये थे। जहाँ कहीं भी यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, यह राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

चरण 3: वि व्यय-कु व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय-कुल व्यय के राष्ट्रीय औसत के आधार पर सम्बन्धित वि व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय की गणना करें, जिससे कि किसी भी राज्य में यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम न हों, अर्थात्, यदि

वि व्यय/कु व्यय = Y

वि व्यय = Y* कु व्यय .....(2)

जहाँ Y, वि व्यय-कु व्यय अनुपात का राष्ट्रीय औसत है

(2) में (1) को प्रतिस्थापित करने पर, हम पायेंगे

वि व्यय = Y*X*जी एस डी पी .....(3)

जहाँ कहीं भी राज्यों का वि व्यय-कु व्यय, सा से व्यय-कु व्यय और पूँ व्यय-कु व्यय अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किया गया। जहाँ यह अनुपात औसत से कम था, इन्हें राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

चरण 4: समीकरण (3) के अनुसार आगणित वि व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय के आधार पर, सम्बन्धित प्रति व्यक्ति व्यय की गणना की गयी, अर्थात्

प्र व्य वि व्यय = वि व्यय/ज.....(4)

जहाँ प्र व्य वि व्यय, प्रति व्यक्ति विकास व्यय है और ज जनसंख्या है।

(4) में (3) को प्रतिस्थापित करने पर, हम पायेंगे

प्र व्य वि व्यय = (Y*X*जी एस डी पी)/ज .....(5)

समीकरण (5), समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय उपलब्ध कराता है। यदि समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय, प्रति व्यक्ति व्यय के राष्ट्रीय औसत से कम है, तब राज्य के व्यय का न्यून स्तर राजकोषीय क्षमता में कमी के कारण है। यह, व्यय के वास्तविक स्तर का चित्रण करता है जबकि सभी राज्य सरकारें इन क्षेत्रों को राजकोषीय प्राथमिकता, राष्ट्रीय औसत के बराबर देती है।

राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियाँ और पद्धतियाँ का आकलन करने में प्रयुक्त कुछ चयनित शब्दावलियों की परिभाषा नीचे दी गयी है:

शब्द	गणना के आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
प्राचल (X) की उत्प्लावकता, अन्य प्राचल (Y) के संदर्भ में	प्राचल(X) की वृद्धि दर/प्राचल (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर ओ जी)	[(वर्तमान वर्ष की धनराशि/विगत वर्ष की धनराशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा भुगतान औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष की राजकीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष के राजकोषीय दायित्व)2]*100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण भंडार*ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर ब्याज प्राप्ति का *प्रतिशत*	प्राप्त ब्याज [(आदि शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतिम शेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम का निवल - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी सी आर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाया समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय जिसमें मुख्य शीर्ष 2048- ऋण की परिहार्यता के न्यूनीकरण के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय शामिल नहीं है।

परिशिष्ट-1.2

भाग ब

(संदर्भः उत्तराखण्ड का विवरण; पृष्ठ-1)

राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005

(तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ के अनुरुप मार्च 2011 में आंशिक संशोधित)

राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करते हुए राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करके और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण द्वारा विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग तथा राज्य सरकारों के राजकोषीय संचालनों में अधिक पारदर्शिता के माध्यम से सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे सम्बन्धित अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करना निहित है।

विशेष रूप से राज्य सरकार–

(क) 1 अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य करेगी;

(ख) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथासंस्तुत वर्ष 2011-12 व 2012-13 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 *प्रतिशत* व तत्पश्चात् वर्ष 2013-14 व 2014-15 में 3 *प्रतिशत* रखेगी।

(ग) 1 अप्रैल 2011 से मार्च 2015 तक के आगामी चार वर्षों में जी एस डी पी की तुलना में राजकोषीय दायित्व का अनुपात 41.40 *प्रतिशत*, 40.00 *प्रतिशत*, 38.50 *प्रतिशत* व 37.20 *प्रतिशत* से अधिक न होना सुनिश्चित करेगी;

(घ) खण्ड (ग) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति से, खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के *प्रतिशत* के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी करेगी;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त लक्ष्य प्रत्येक छः माही में समीक्षित किए जाएँगे ।

(च) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं देगी; एवं

(छ) 1 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले दस वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगी कि अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व, उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 *प्रतिशत* से अधिक न हो।

मध्यकालिक राजकोषीय नीति के द्वारा राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ के सूचकों का परिणाम

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12 (बजट)	2011-12 (संशोधित)	2012-13	2013-14	2014-15
क. राज्य का राजस्व लेखा :							
1. स्वयं का कर राजस्व	3,559.11	4,405.48	4759.74	5581.64	5,980.26	6,937.10	8047.04
2. स्वयं का करेत्तर राजस्व	631.86	678.06	1647.11	1043.95	1208.17	1,314.82	826.01
3. स्वयं का कर + करेत्तर राजस्व (1+2)	**4,190.97**	**5,083.54**	**6406.85**	**6625.59**	**7188.43**	**8,251.93**	**8873.05**
4. केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में अंश	1,549.94	2,460.07	2955.31	2839.17	3388.45	3,795.06	4250.47
5. आयोजनागत अनुदान	2,595.96	2,629.36	4567.49	4389.10	4831.67	5,314.84	5846.32
6. आयोजनेत्तर अनुदान	1,149.26	1,435.20	705.34	689.03	750.40	435.00	485.00
7. कुल केन्द्रीय अन्तरण (4 से 6)	**5,295.16**	**6,524.63**	**8228.14**	**7917.30**	**8970.52**	**9,544.90**	**10581.79**
8. कुल राजस्व प्राप्तियाँ (3+7)	**9,486.13**	**11,608.17**	**14634.99**	**14542.89**	**16,158.95**	**17,796.83**	**19454.84**
9. आयोजनागत व्यय	3,810.16	4,367.29	6564.29	5819.39	7,048.96	7,753.86	8529.24
10. आयोजनेत्तर व्यय	10,386.79	10,348.56	12802.62	13153.43	14,882.81	16,371.09	18008.20
11. वेतन व्यय	4,811.21	4,966.14	5670.25	5410.23	6,513.18	7,164.50	7880.95
12. पेंशन	1,304.65	1,141.72	1414.95	1414.95	1,439.80	1,612.58	1806.09
13. ब्याज भुगतान	1,510.91	1,479.58	1812.03	1797.02	2,025.00	2,322.00	2653.82
14. उपदान-सामान्य							
15. उपदान-विद्युत							
16. कुल राजस्व व्यय (9+10)	**10,657.47**	**11,621.08**	**14325.70**	**14321.53**	**15,717.11**	**17,288.82**	**19017.70**
17.वेतन+ब्याज+पेंशन (11+12+13)	7,626.77	7587.44	8897.23	8622.20	9977.98	11099.08	12340.85
18. राजस्व प्राप्ति *प्रतिशत* के रूप में (17/8)	*80.40*	*65.36*	*60.79*	*59.29*	*61.75*	*62.37*	*63.43*

19. राजस्व अधिशेष/घाटा (8-16)	**-1171.34**	**- 12.91**	**309.29**	**221.36**	**441.84**	**508.01**	**437.14**
ख. समेकित राजस्व लेखा:							
1. विद्युत के क्षेत्र में हानि/वास्तविक उपदान अन्तरण के निवल लाभ	-	-			-	-	-
2. वर्ष के दौरान विद्युत उपयोगिता लेखा में बकायेदारों की वृद्धि (वृद्धि (-))	-	-			-	-	-
3. आयव्ययक ऋण और पी एस यूज और एस पी यूज द्वारा लिये गये आयव्ययक ऋण पर ब्याज भुगतान	-	-			-	-	-
4. योग (1 से 3)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
समेकित राजस्व अधिशेष/घाटा	**-1171.34**	**-12.91**	**309.29**	**221.36**	**441.84**	**508.01**	**437.14**
ग. समेकित ऋण:							
1. बकाया ऋण एवं दायित्व	17,029.45	19806.99	22089.26	21859.24	25028.11	28328.16	32014.97
2. कुल अनिस्तारित प्रत्याभूतियाँ	1,801.60	2042.28	1510.99	1739.45	1739.45	1739.45	1739.45
ए) बजटकृत तथा एस पी वी ऋण हेतु प्रत्याभूतियाँ	-						
घ. पूँजीगत लेखा:							
1. पूँजीगत परिव्यय	2136.74	1854.85	3094.50	2524.49	3653.18	3836.15	4143.05
2. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	30.06	59.68	307.91	570.87	264.05	90.00	99.00
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	554.83	84.87	474.96	474.96	118.10	118.10	118.10
4. अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ	1613.11	2382.29	2431.00	2361.18	3966.00	3300.05	3686.81
ड. सकल राजकोषीय घाटा (जी एफ डी):	**2783.31**	**1842.57**	**2618.24**	**2346.04**	**3357.59**	**3300.05**	**3686.81**
चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	63,352.18	75475.73	87349.99	87349.99	98356.09	110749.00	124703.30
च. राजकोषीय घाटा :							
वास्तविक/मान ली गई नगण्य वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	*19.27*	*13.67*	*15.73*	*15.73*	*12.60*	*12.60*	*12.60*

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: प्रस्तर 1.3, 1.7.2 एवं 1.8; पृष्ठ-8, 26 & 28)

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. ***राजस्व प्राप्तियाँ***	**7,891**	**8,635**	**9,486**	**11,608**	**13,691**
(i) कर राजस्व	**2,739(*35*)**	**3,045(*35*)**	**3,559(*38*)**	**4,405(*38*)**	**5,616(41)**
कृषि आय पर कर	…	…	…	-	--
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1628(59)	1911(63)	2247 (63)	2940 (67)	3644(65)
राज्य आबकारी	442(16)	528(17)	705(20)	756(17)	844(15)
वाहनों पर कर	155(6)	167(5)	184(5)	227(5)	335(6)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	424(15)	357(12)	399(11)	440(10)	524(9)
भू-राजस्व	23(1)	18(1)	9(0.25)	18(0.41)	10(--)
माल एवं यात्रियों पर कर		6(-)	-	-	-
अन्य कर	-	***58(2)***	15(0.42)	24(0.54)	259(5)
(ii) करेत्तर राजस्व	***668(8)***	***699(8)***	**632(7)**	**678(6)**	**1136(8)**
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	***1,428(18)***	**1,507(18)**	**1,550(16)**	**2,460(21)**	**2866(21)**
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	***3,056(38)***	**3,384(39)**	**3,745(39)**	**4,065(35)**	**4073(30)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**-**	-	-	-	-
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**68**	**54**	**65**	**85**	**91**
4. कुल राजस्व एवं ऋणेत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**7,959**	**8,689**	**9,551**	**11,693**	**13782**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**1,398**	**1,544**	**1,682**	**2,427**	**2336**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,210(87)	1,399(91)	1,582(94)	2,384(98)	2289(98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	172(12)	127(8)	69(4)	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	16(1)	18(1)	319(2)	43(2)	47 (2)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ(4+5)	**9,357**	**10,233**	**11,233**	**14,120**	**16,118**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**27**	**02**	**37**	**582**	**126**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**12,412**	**13,658**	**14,226**	**18,829**	**19,668**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**21,769**	**23,891**	**25,459**	**33,531**	**35,912**

भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**7,255**	**8,394**	**10,657**	**11,621**	**12,975**
आयोजनागत	*1,834(25)*	2,174(26)	2,299(22)	2,472(21)	2,321(18)
आयोजनेत्तर	*5,421(75)*	6,220(74)	8,358(78)	9,149(79)	10,654(82)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतानों सहित)	2,655(37)	3,104(37)	3,694(35)	4,180(36)	4,475(35)
सामाजिक सेवायें	2,829(39)	3,392(41)	4,980(47)	5,169(44)	6,019(46)
आर्थिक सेवायें	1,461(20)	1,623(19)	1,658(16)	1,864(16)	2,102(16)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	310(4)	275(3)	325(3)	408(4)	379(3)
11. पूँजीगत व्यय	**2235**	**2016**	**1647**	**1,855**	**2,317**
आयोजनागत	*2,157(97)*	1,902(94)	995(60)	1,859(100)	2,071(89)
आयोजनेत्तर	*78(3)*	114(6)	651(40)	(-) 4	246(11)
सामान्य सेवायें	201(9)	174(9)	109(7)	105(5)	77(3)
सामाजिक सेवायें	418(19)	281(14)	109(7)	235(13)	369(16)
आर्थिक सेवायें	1,616(72)	1,561(77)	1,429(87)	1,515(82)	1,871(81)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	**213**	**122**	**30**	**60**	**247**
13. **योग** *(10+11+12)*	**9,703**	**10,532**	**12,334**	**13,536**	**15,539**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**273**	**355**	**473**	**519**	**1,016**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	240(88)	318	437	448	667
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	45	323
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	33(12)	37	36	26	26
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	**–**		**-**	**515**	**(-) 400**
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	**9,976**	**10,887**	**12,807**	**14,570**	**16,155**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	**1**	**32**	**71**	**537**	**69**
18. लोक लेखा संवितरण	**11,864**	**13,477**	**12,322**	**17,733**	**19,832**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**21,841**	**24,396**	**25,200**	**32,840**	**36,056**
*भाग ग. घाटा/*आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	**(+) 636**	**(+) 241**	**(-) 1,171**	**(-) 13**	**(+)716**
21. राजकोषीय घाटा (4-13)	**1,744**	**1,843**	**2,783**	**1,843**	**1,757**

22. प्राथमिक घाटा (21+23)	**(-) 648**	**(-) 655**	**(-) 1,445**	**(-) 363**	**(+) 12**
भाग घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**1,096**	**1,188**	**1,338**	**1,480**	**1,769**
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	310	275	324	408	379
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)	52	83	107/09	93	73
26. अर्थोपाय अग्रिम ओवरड्राफ्ट/पर ब्याज	0.66	3	2	1	0.88
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी)@	45,856	56,025	70,851	82,460	95,201
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)	14,392	16,276	18,748	21,598	23,609
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	1,677	1,802	1,511	1,511	1,739
30. प्रतिभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)	1,738	1,677	1,386	2,122	2,722
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)	367	382	140	89	63
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	487	539	2,081	63	121.80
भाग ङ. राजकोषीय सुदृढता-सूचक					
I *संसाधन का जुटाव*			0.05		
स्वयं का कर राजस्व/जी एस डी पी	0.06	0.05	0.01	0.05	0.06
स्वयं का करेत्तर राजस्व /जी एस डी पी	0.01	0.01	0.07	0.01	0.01
केन्द्रीय अन्तरण/जी एस डी पी	0.10	0.09		0.08	0.07
II *व्यय प्रबन्धन*					
कुल व्यय/जी एस डी पी	0.21	0.19	0.17	0.16	0.16
कुल व्यय /राजस्व प्राप्तियाँ	1.23	1.22	1.30	1.17	1.13
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	0.75	0.80	0.86	0.86	0.83
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.33	0.35	0.41	0.40	0.41
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.32	0.30	0.25	0.25	0.26
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.23	0.19	0.13	0.14	0.15
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.21	0.17	0.12	0.13	0.14

III *राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन*					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/जी एस डी पी	(+)0.014	(+)0.004	(-) 0.017	*	(+)0.008
राजकोषीय घाटा/जी एस डी पी	0.038	0.033	0.039	0.022	0.018
प्राथमिक घाटा (अधिशेष) /जी एस डी पी	0.014	0.012	0.020	0.004	*
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा	(+)0.365	(+)0.131	(-)0.420	(-)0.007	(+)0.408
प्राथमिक राजस्व शेष/जी एस डी पी	(-)0.010	(-)0.016	(-)0.036	(-)0.018	(-)0.011
IV *राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन*					
राजकोषीय दायित्व/जी एस डी पी	0.314	0.291	0.265	0.262	0.248
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	1.82	1.88	1.98	1.86	1.72
मात्रात्मक विस्तार के सापेक्ष प्राथमिक घाटा	(+) 1745	(+) 1694	(+)2083	(+)1592	(+)1811
ऋण पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ	0.94	0.95	0.95	0.83	0.94
V *अन्य राजकोषीय सुदृढता सूचक*					
निवेश का प्रतिफल	0.53	0.23	0.07	0.21	0.05
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	(+) 842	(+) 357	(-) 1,384	(-) 46	(-)250
वित्तीय परिसम्पतियां/दायित्व	0.71	0.76	0.82	0.77	0.82

कोष्ठकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से *प्रतिशतता* (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

@ सरकार द्वारा सूचित जी एस डी पी के आँकड़े ग्रहण किये गये हैं।

* संगणन योग्य नहीं।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: प्रस्तर 1.1, एवं 1.7.2; पृष्ठ -1 एवं 26)

भाग अः

वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)					*(₹ करोड़ में)*					
प्राप्तियाँ					**संवितरण**					
विविध मद	**2010-11**		**2011-12**		**विविध मद**	**2010-11**	**2011-12**			
							आयोज-नेत्तर	**आयोज-नागत**	**योग**	
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**
खण्ड-अ राजस्व										
I-राजस्व प्राप्तियाँ		**11,608.16**		**1,3691.24**	**I-राजस्व व्यय**	**11,621.07**				**12,975.19**
(i) कर राजस्व	4,405.47		5,615.62		सामान्य सेवायें	**4180.15**	**4471.39**	**3.72**	**4,475.11**	
(ii) करेत्तर राजस्व	678.06		1,136.13		सामाजिक सेवायें	**5169.49**	**4368.07**	**1651.58**	**6,019.65**	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	2,460.07		2,866.04		शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	3177.17	2,987.28	4,75.58	3,462.86	
(iv) आयोजनेत्तर अनुदान	1,435.20		762.09		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	615.11	436.27	261.78	698.05	
(v) राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2,252.56		2,839.85		जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	511.70	82.69	352.66	435.35	
(vi) केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	376.80		471.51		सूचना एवं प्रसारण	37.40	35.12	1.25	36.37	
					अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	166.68	65.91	111.46	177.37	
	–				श्रम तथा श्रमिक कल्याण	55.75	39.58	14.42	54.00	

					समाज कल्याण एवं पोषण	576.25	707.57	428.79	1,136.36	
					अन्य	29.43	13.65	5.64	19.29	
					आर्थिक सेवायें	**1863.75**	**1435.85**	**665.78**	**2,101.63**	
					कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	889.90	793.59	397.99	1,191.58	
					ग्राम्य विकास	455.06	149.31	185.98	335.29	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		-	-	-	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	292.28	284.48	4.37	288.85	
					ऊर्जा	11.39	2.92	7.06	9.98	
					उद्योग एवं खनिज	41.85	25.38	17.48	42.86	
					परिवहन	119.80	166.69	8.61	175.30	
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	10.15	0.60	13.02	13.62	
					सामान्य आर्थिक सेवायें	43.32	12.88	31.27	44.15	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	**407.68**	**378.80**	**-**	**378.80**	
योग				**13,691.24**	**योग**	**11,621.07**				**12,975.19**
II-राजस्व घाटा खण्ड-ब को अन्तरित		**12.91**		**–**	**II-** राजस्व अधिशेष खण्ड-ब को अन्तरित	**-**				**716.05**
योग		**11,621.07**		**13,691.24**	**योग**	**11621.07**				**13,691.24**
III-स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष		**538.91**		**1,229.40**	**III- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट**					
IV- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			–	**-**	**IV- पूँजीगत परिव्यय**	**1854.84**	**245.94**	**2071.00**	**2,316.94**	**2,316.94**
					सामान्य सेवायें	**104.71**	**7.11**	**70.36**	**77.47**	
					सामाजिक सेवायें	**235.24**	**-**	**368.58**	**368.58**	
					शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	121.37	-	131.47	131.47	

					स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	72.82	-	93.66	93.66	
					जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	27.25	-	119.62	119.62	
					सूचना एवं प्रसारण	-	-	-	-	
					अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	8.37	-	11.93	11.93	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	5.44	-	4.16	4.16	
					अन्य	-	-	7.74	7.74	
					आर्थिक सेवायें	**1514.89**	**238.83**	**1632.06**	**1,870.89**	
					कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	19.47	238.80	20.84	259.64	
					ग्राम्य विकास	91.82	-	226.03	226.03	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	346.84	0.08	455.74	455.82	
					ऊर्जा	56.71	-	41.78	41.78	
					उद्योग एवं खनिज	3.15	-	0.62	0.62	
					परिवहन	939.38	-0.05	857.35	857.30	
					सामान्य आर्थिक सेवायें	57.52	-	29.70	29.70	
					योग	**1854.84**	**245.94**	**2,071.00**	**2,316.94**	**2,316.94**
V-***ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ***		**84.87**		**90.65**	V- ***संवितरित ऋण एवं अग्रिम***	**59.68**				**246.83**
विद्युत परियोजनाओं से	76.53		84.75		*विद्युत परियोजनाओं के लिए*	58.27	12.07	117.02	129.09	
सरकारी कर्मचारियों से	6.53		5.36		*सरकारी कर्मचारियों को*	1.05	1.17	-	1.17	
अन्य से	1.81		0.54		*अन्य को*	0.36	0.55	116.02	116.57	
VI- राजस्व अधिशेष नीचे लाया गया	**–**		**--**	**716.05**	**VI- राजस्व घाटा नीचे लाया गया**	**12.91**			**-**	**-**
VII- लोक ऋण प्राप्तियाँ		**2427.18**		**2,335.52**	**VII- लोक ऋण की पुनर्भुगतान**	**519.36**				**1,015.78**
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	2384.24		2289.12		अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	447.86			666.62	

ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-		-		अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	44.89			322.90	
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	42.94		46.40		केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	26.61			26.26	
VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोग	–				**VIII-** आकस्मिकता निधि को विनियोग	**515.00**				**(-)400.00**
IX- आकस्मिकता निधि में अन्तरित राशि		**5,81.62**		**126.13**	**IX-** आकस्मिकता निधि से व्यय	**536.71**				**69.07**
X- लोक लेखा प्राप्तियाँ		**18,703.51**		**19,668.05**	**X- लोक लेखा संवितरण**	**17608.20**				**19,832.00**
लघु बचत एवं भविष्य निधि	1,372.66		1,272.45		लघु बचत एवं भविष्य निधि	502.93			646.40	
आरक्षित निधियाँ	153.10		648.94		आरक्षित निधियाँ	1.32			592.74	
जमा एवं अग्रिम	2,463.70		2,330.92		जमा एवं अग्रिम	2,418.11			2,298.02	
उचंत एवं विविध	11,460.15		12,366.08		उचंत एवं विविध	11,129.03			12,779.05	
प्रेषण	3,253.90		3,049.66		प्रेषण	3,556.81			3,515.79	
XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अन्तिम ओवर ड्राफ्ट					**XI-अन्त में रोकड़ शेष**	**1229.40**				**1,085.18**
					कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	(-) 5.45			(-) 5.38	
					स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	(-)3.02			(-) 3.02	
					रिजर्व बैंक में जमा	334.25			116.01	
					रोकड़ शेष का निवेश व नैमित्तिक निधि के निवेश	903.62			977.57	
योग	**22,336.09**			**24,165.80**	**योग**	**22,336.09**				**24,165.80**

परिशिष्ट-1.4 (क्रमशः)

भाग ब

(संदर्भः प्रस्तर 1.1, 1.7.1 एवं 1.7.2; पृष्ठ-1 एवं 26)

31 मार्च 2012 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.03.2011 को	दायित्व	31.03.2012 को
15,548.50	**आन्तरिक ऋण**	**16,848.09**
7,234.92	ब्याज वहन करने वाले बाजार ऋण	83,94.18
0.13	ब्याज वहन न करने वाले बाजार ऋण	0.14
1.50	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.50
7,958.35	अन्य संस्थाओं से ऋण	8421.58
353.60	अर्थोपाय अग्रिम	30.69
-	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	-
435.32	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**	**455.46**
0.53	1984-85 से पहले के ऋण	0.53
9.25	आयोजनेत्तर ऋण	7.95
397.45	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	420.82
0.04	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.04
28.05	केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	26.12
45.65	**आकस्मिकता निधि**	**102.70**
3,823.17	**लघु बचत, भविष्य निधि आदि**	**4,449.22**
1,619.79	**जमा**	**1,652.70**
1,075.26	**आरक्षित निधियाँ**	**1,131.46**
-	**प्रेषण शेष**	-
22,547.69	**योग**	**24,639.63**

परिशिष्ट-1.4 भाग ब (क्रमशः)

31.03.2011 को	परिसम्पत्तियां	31.03.2012 को
13,522.94	**अचल परिसमपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय**	**15,839.88**
1,295.97	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	1,338.47
12,226.97	अन्य पूँजीगत परिव्यय	14,501.41
717.90	**ऋण एवं अग्रिम**	**874.08**
370.33	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	414.67
346.50	अन्य विकास ऋण	462.38
1.07	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	(-) 2.97
515.00	**आकस्मिकता निधि को विनियोग**	**115.00**
874.34	**प्रेषण**	**1,340.47**
425.38	**उचंत एवं विविध शेष**	**838.34**
1229.41	**रोकड़**	**1,085.19**
(-) 5.45	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	(-)5.38
334.25	रिजर्व बैंक में जमा	116.01
(-) 2.15	विभागीय रोकड़ शेष सहित	(-) 2.15
(-)0.86	स्थायी अग्रिम	(-)0.86
903.62	रोकड़ शेष निवेश	977.57
5,262.72	**सरकारी लेखों में घाटा**	**4,546.67**
12.91	(i) चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य को घटायें	716.05
	(ii) विविध घाटा	-
5,249.81	वर्ष के प्रारम्भ में संचित घाटा	5,262.72
22,547.69	**योग**	**24,639.63**

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्वोक्त विवरण पत्रों में दर्शाये गये संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़ना होगा। **परिशिष्ट 1.4** में यथादर्शित सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर होने के कारण, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत रोकड़ आधार पर होने की स्थिति को इंगित करता है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मदें या मूल्य ह्रास अथवा भण्डार के आँकड़ो में भिन्नता इत्यादि जैसी मदें लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं। उचंत तथा विविध अवशेषों में, जारी परन्तु भुगतान नहीं किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन आदि सम्मिलित हैं। " रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत लेखों में प्रदर्शित एवं रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए आँकड़ों के मध्य ₹ 7.79 करोड़ (डेबिट) का अन्तर था जिसका मिलान किया जा रहा है।

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.2; पृष्ठ-6)

2011-12 के दौरान राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत राज्य बजट से बाहरी अन्तरित निधियों को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	कार्यक्रम/योजना	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राशि
1	राष्ट्रीय एस जे ई संस्थाओं के निधीयन हेतु योजना	राष्ट्रीय दृष्टीबाधितार्थ संस्थान	8.16
2	आजीविका	डी आर डी ए व पी एम यू	22.12
3	प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास योजना	राज्य साक्षरता अभियान	28.47
4	स्वायत्त शासित संस्थान और व्यक्सायिक निकाय	वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान	46.96
5	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	पी एम यू स्वजल परियोजना	8.05
6	डी आर डी ए प्रशासन	डी आर डी ए	10.98
7	टी एच डी सी इंडिया लिमिटेड में इक्विटी बढ़ाना	टी एच डी सी लिमिटेड	45.00
8	वन एवं वन्य जीवन संस्थाओं को सहायता अनुदान	पी आर आई व डब्ल्यू आई आई	116.07
9	ग्रिड इन्ट्रेक्टिव रिन्यूएबल पावर एम एन आर ई	यू जे वी एन एस, उरेडा	6.26
10	अस्पताल व औषधालय (एन आर एच एम के अन्तर्गत)	उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	5.81
11	जलविज्ञान परियोजना	राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान	8.66
12	आई आई टी यों व डी एच ई (ओ एस सी समेत)	भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान	120.00
13	एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (आई डब्ल्यू एम पी)	डी आर डी ए व जलागम पी एम यू	15.97
14	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	डी आर डी ए	373.51
15	महिला समाख्या	महिला समाख्या	4.34
16	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिलाधिकारी	28.00
17	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी	11.31
18	मवेशियों एवं भैंसों हेतु राष्ट्रीय परियोजना	उत्तराखण्ड पशुधन परिषद	5.41
19	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	एच डब्ल्यू एस एम उत्तराखण्ड	75.57
20	ऑफ ग्रिड	उरेडा, सिलिकॉन केमिकल्स लिमिटेड	9.98

21	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	131.18
22	विशेष श्रेणी राज्यों के लिए पैकेज़ (पूर्वोत्तर को छोड़कर)	सिडकुल	75.51
23	प्रोजेक्ट/इन्फ्रास्ट्रकचर डेवलपमेन्ट फॉर डेस्टिनेशन एण्ड सर्किट्स	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद	75.53
24	शहरी सुविधाओं हेतु प्रावधान	डी आर डी ए	6.92
25	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए)	उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद	34.07
26	संरक्षण और विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास	एच एन बी गढ़वाल यूनिवर्सिटी	11.46
27	एस ई आर सी अनुसंधान एवं विकास सहायता	हिमालयन, पर्यावरण एवं विकास अभिकरण संस्थान	5.61
28	जल संसाधन एवं विकास	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एन आई एच)	8.57
29	ग्रामीण आवास (आई ए वाई)	डी आर डी ए	58.29
30	सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)	उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद	208.92
31	विकास हेतु परियोजना (एफ बी आई)	आई आई ई देहरादून	5.53
32	नए आई आई एम ओ की स्थापना	आई आई एम काशीपुर	7.90
33	पी पी पी के द्वारा 1396 आई टी आई यो का उच्चीकरण	आई आई टी यों की आई एम सी समिति	35.00
34	औषधि निर्मात्री प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण	आई एम पी सी लिमिटेड	24.00
35	अन्य	विविध कार्यदायी संस्थाएँ	400.99
योग			**2040.11**

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ: प्रस्तर 1.6.3; पृष्ठ-23)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों का सारांशित वित्तीय

(₹ लाख में)

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	शासकीय पूँजी का मध्यमान	ह्रासित लागत पर ब्लॉक परिसम्पतियां	वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया मूल्य ह्रास	कारोबार	निवल लाभ/हानि	पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल (8+9)	पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रूड़की	2009-10	188.81	90.43	6.61	608.22	(-) 0.79	27.76	26.97	31.62
2(क)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2002-03	-	58.25	6.64	7,112.3	(-) 3,164.61	-	(-) 3,164.61	-
2(ख)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2002-03	-	9.97	1.00	8,357.23	(-) 1,350.21	-	(-) 1,350.21	-

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.1 ; पृष्ठ-38)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता ₹ 1 करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	*प्रतिशत*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		राजस्व-दत्तमत			
1.	01	विधानमण्डल	17.29	1.67	9.66
2.	03	मंत्रिपरिषद	62.76	1.31	2.09
3.	04	न्याय प्रशासन	104.45	28.05	26.85
4.	05	निर्वाचन	33.22	4.71	14.18
5.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	887.26	43.94	4.95
6.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2299.68	580.10	25.23
7.	08	आबकारी	10.00	2.23	22.30
8.	10	पुलिस एवं कारागार	711.00	50.52	7.11
9.	11	शिक्षा,क्रीड़ा,युवा कल्याण एवं संस्कृति	3650.33	283.38	7.76
10.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	820.11	153.99	18.78
11.	13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	649.01	235.77	36.33
12.	14	सूचना	38.28	2.11	5.51
13.	15	कल्याण	647.07	197.45	30.51
14.	16	श्रम एवं रोजगार	71.43	12.39	17.35
15.	17	कृषि कार्य एवं शोध	464.41	44.73	9.63
16.	18	सहकारिता	42.31	10.30	24.34
17.	19	ग्राम्य विकास	387.85	92.71	23.90
18.	20	सिंचाई व बाढ़	323.70	25.02	7.73
19.	21	ऊर्जा	14.03	6.38	45.47
20.	22	लोक निर्माण	437.53	35.43	8.10
21.	23	उद्योग	78.77	14.47	18.37
22.	24	परिवहन	20.64	1.37	6.64

23.	25	खाद्य	327.72	123.52	37.69
24.	26	पर्यटन	58.78	30.66	52.16
25.	27	वन	322.55	19.81	6.14
26.	28	पशुपालन	106.83	4.48	4.19
27.	29	उद्यान विकास	113.88	14.94	13.12
28.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	571.83	193.63	33.86
29.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	143.80	45.36	31.54
योग			**13416.52**	**2260.43**	**16.85**
		राजस्व-प्रभारित			
1.	04	न्याय प्रशासन	*30.59*	*13.87*	*45.34*
2.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	*1.72*	*0.38*	*22.09*
3.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	*2013.00*	*217.95*	*10.83*
4.	09	लोक सेवा आयोग	*9.99*	*1.46*	*14.61*
5.	22	लोक निर्माण	*3.44*	*1.40*	*40.70*
योग			**2058.74**	**235.06**	**11.42**
		पूँजीगत-दत्तमत			
1.	01	विधान मण्डल	24.00	22.00	91.67
2.	04	न्याय प्रशासन	39.00	29.40	75.38
3.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	52.00	24.60	47.46
4.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	150.57	72.43	48.10
5.	10	पुलिस एवं कारागार	59.40	44.60	75.08
6.	11	शिक्षा, क्रीड़ा, युवा कल्याण एवं संस्कृति	287.27	166.32	57.90
7.	12	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	128.60	39.00	30.33
8.	13	जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास	96.55	15.77	16.33
9.	14	सूचना	4.00	3.94	98.50
10.	15	कल्याण	32.20	22.03	64.42
11.	16	श्रम एवं रोजगार	16.93	6.46	30.16
12.	18	सहकारिता	4.70	2.93	62.34
13.	19	ग्राम्य विकास	213.88	66.05	30.88
14.	20	सिंचाई व बाढ़	552.73	36.30	6.57

15.	21	ऊर्जा	676.03	531.92	78.68
16.	23	उद्योग	14.11	13.35	94.61
17.	24	परिवहन	155.42	12.56	8.08
18.	26	पर्यटन	47.28	19.20	40.61
19.	27	वन	25.00	8.64	34.56
20.	28	पशुपालन	11.04	2.85	25.82
21.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	341.49	176.50	51.59
22.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	100.37	54.70	54.50
योग			**3032.57**	**1371.55**	**45.23**
महा योग			**18507.83**	**3867.04**	**20.89**

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.3 ; पृष्ठ-40)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें व्ययाधिक्य प्रत्येक में ₹ 1 करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	कुल व्यय	व्ययाधिक्य	व्ययाधिक्य की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पूँजीगत(प्रभारित)						
1.	07	वित्त कर नियोजन सचिवालय व विविध सेवाएँ	1638.73	1924.05	285.32	17.41
पूँजीगत(दत्तमत)						
2.	17	कृषि कार्य एवं शोध	15.92	34.25	18.33	1,15.14
3.	22	लोक निर्माण	8,25.92	8,45.91	19.99	2.42
4.	25	खाद्य	3.67	12,86.93	12,83.26	3,49,66.21
5.	29	उद्यान विकास	0	4.51	4.51	100.00
योग			**24,84.24**	**40,95.65**	**16,11.41**	**64.86**

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7 ; पृष्ठ-43)

ऐसे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
क - राजस्व(दत्तमत)					
1.	04 न्याय प्रशासन	102.38	76.40	25.98	2.07
2.	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	844.63	843.32	1.31	42.62
3.	07 वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2243.70	1719.58	524.12	55.97
4.	08 आबकारी	9.90	7.77	2.13	0.10
5.	10 पुलिस और कारागार	667.28	660.48	6.80	43.72
6.	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	803.83	666.12	137.71	16.28
7.	13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	646.94	413.24	233.70	2.07
8.	15 कल्याण	552.63	449.62	103.01	94.44
9.	16 श्रम एवं राजगार	68.37	59.04	9.33	3.06
10.	18 सहकारिता	35.23	32.01	3.22	7.08
11.	19 ग्रामीण विकास	323.11	295.14	27.97	64.74
12.	20 सिंचाई एवं बाढ़	307.71	298.68	9.03	15.98
13.	21 ऊर्जा	8.01	7.65	0.36	6.02
14.	22 लोक निर्माण	420.43	402.10	18.33	17.10
15.	23 उद्योग	75.24	64.30	10.94	3.53
16.	24 यातायात	19.95	19.27	0.68	0.69
17.	25 खाद्य	327.52	204.20	123.32	0.20
18.	26 पर्यटन	53.70	28.12	25.58	5.09
19.	29 उद्यान विकास	100.30	98.94	1.36	13.58

20.	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	534.49	378.20	156.29	37.34
21	31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	127.70	98.44	29.26	16.10
कुल राजस्व (दत्तमत)		***8273.05***	***6822.62***	***1450.43***	***447.78***
ख - राजस्व(प्रभारित)					
1.	06 राजस्व और सामान्य प्रशासन	*1.61*	*1.34*	*0.27*	*0.11*
2.	07 वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	*1974.03*	*1795.04*	*178.99*	*38.96*
कुल राजस्व(प्रभारित)		***1975.64***	***1796.38***	***179.26***	***39.07***
ग- पूँजीगत(दत्तमत)					
1.	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	49.00	27.40	21.60	3.00
2.	07 वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	117.80	78.14	39.66	32.77
3.	10 पुलिस और कारागार	49.00	14.80	34.20	10.40
4.	11 शिक्षा, क्रीड़ा, युवा कल्याण एवं संस्कृति	271.05	120.95	150.10	16.22
5.	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	119.66	89.60	30.06	8.94
6.	13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	81.50	80.78	0.72	15.05
7.	15 कल्याण	25.40	10.17	15.23	6.80
8.	16 श्रम एवं रोजगार	16.15	10.47	5.68	0.78
9.	21 ऊर्जा	448.92	144.11	304.81	227.11
10.	24 परिवहन	155.26	142.86	12.40	0.16
11.	26 पर्यटन	46.28	28.08	18.20	1.00
12.	28 पशुपालन	10.04	8.19	1.85	1.00

13.	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	338.68	164.99	173.69	2.80
14.	31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	100.01	45.67	54.34	0.36
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		**1828.75**	**966.21**	**862.54**	**326.39**
महा योग		**12077.44**	**9585.21**	**2492.23**	**813.24**

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7; पृष्ठ-43)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	आधिक्य
1.	17	कृषि कार्य एवं शोध (पूँजीगत-दत्तमत)	0.92	15.00	15.92	34.25	18.33
2.	22	लोक निर्माण (पूँजीगत-दत्तमत)	803.20	22.72	825.92	845.91	19.99
योग			**804.12**	**37.72**	**841.84**	**880.16**	**38.32**

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.8; पृष्ठ-43)

₹ 10 लाख या अधिक की बचत (निधियों के उपयोग में कमी)/आधिक्य में परिणत निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ लाख में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोग	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत (-)
1.	04	न्याय प्रशासन	2014-00-105-03	(+)30.06	(+)17.83
2.			2014-00-800-01	(-)762.57	(-)567.34
3.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2029-00-101-03	(-)170.68	(+)101.14
4.			2029-00-103-03	(-)206.12	(+)126.37
5.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2030-03-001-05	(-)0.02	(-)106.26
6.			2030-01-101-03	(-)0.05	(+)353.94
7.			2030-02-102-03	(-)0.04	(+)953.46
8.	10	पुलिस एवं कारागार	2055-00-104-03	(-)344.24	(+)169.31
9.			2055-00-109-04	(+)2.65	(+)41.02
10.			2055-00-109-03	(+)191.46	(+)620.91
11.	11	शिक्षा, क्रीड़ा, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2202-01-101-04	(-)6010.00	(-)198.81
12.			2202-01-102-07	(+)1100.00	(+)200.44
13.			2202-02-109-03	(+)3079.45	(+)152.56
14.					
15.			2202-02-101-03	(-)52.33	(+)11.36
16.			2202-02-109-05	(-)76.00	(+)52.44
17.			2202-02-109-11	(-)245.50	(+)46.71
18.			2202-02-110-03	(+)833.34	(+)645.94
19.			2202-80-003-01	(+)5.48	(+)17.60
20.	13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	2217-03-191-03	(-)835.64	(-)33.85
21.	15	कल्याण	2235-60-102-05	(-)5.00	(-)188.38
22.	20	सिंचाई एवं बाढ़	4700-05-800-01	(-)17.45	(-)4467.36

23.			4700-06-800-02	(+)362.96	(+)130.02
24.	22	लोक निर्माण	4059-80-800-09	(-)7.00	(+)43.22
25.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	2225-01-277-06	(-)7.95	(-)50.29
26.			2225-01-277-91	(+)43.83	(-)32.59

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.9; पृष्ठ-43)

वर्ष 2011-12 के दौरान किए गए भारी अभ्यर्पण

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या व शीर्षक	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल अनुदान/विनियोग (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹ लाख में)	अभ्यर्पण का *प्रतिशत*
1.	02-राज्यपाल	2012-03-800-05	2.50	2.50	100.00
2.		2012-03-800-06	1.00	1.00	100.00
3.	03-मंत्री परिषद	2013-00-101-04	8.80	5.08	57.73
4.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	4059-60-051-09	200.00	112.30	56.15
5.	11-शिक्षा, क्रीड़ा, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2202-02-107-05	2.60	2.35	90.38
6.		2202-02107-07	1.80	1.56	86.67
7.		2202-02-800-01	8416.66	7218.40	85.76
8.		2202-05-102-13	98.99	58.27	58.86
9.		2205-00-102-12	80.00	70.09	87.61
10.		2205-00-102-36	15.00	14.00	93.33
11.					
12.		4202-01-202-19	150.00	150.00	100.00
13.		4202-04-106-03	250.00	139.13	55.65
14.	14-सूचना	4059-60-051-03	400.00	394.36	98.59
15.	20- सिंचाई एवं बाढ़	4701-80-800-04	200.00	200.00	100.00
16.	24-परिवहन	5053-02-800-99	500.00	500.00	100.00
17.	28- पशुपालन	2404-00-102-08	40.00	40.00	100.00
योग			**10367.35**	**8909.04**	**85.93**

परिशिष्ट-2.7 अ

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ-44)

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या व नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
राजस्व-दत्तमत					
1.	10-पुलिस एवं कारागार	711.00	50.52	54.79	4.27
2.	18- सहकारिता	42.31	10.30	11.47	1.17
3.	20-सिंचाई	323.70	25.02	39.20	14.18
योग		**1077.01**	**85.84**	**105.46**	**19.62**

परिशिष्ट-2.7 ब

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ-44)

अन्तिम आधिक्य के बावजूद अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या व नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य	अभ्यर्पित राशि
पूँजीगत- दत्तमत					
1.	17-कृषि कार्य एवं अनुसंधान	15.92	34.25	18.33	0.92
2.	22-लोक निर्माण	825.92	845.91	19.99	73.21
योग		**841.84**	**880.16**	**38.32**	**74.13**

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ-44)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ 10 करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

I – अनुदान			
क्रम सं.	**अनुदान सं.**	**अनुदान/विनियोग का नाम**	**बचत**
1.	01	विधानसभा (पूँजीगत-दत्तमत)	22.00
2.	19	ग्रामीण विकास (पूँजीगत-दत्तमत)	66.05
3.	21	ऊर्जा (पूँजीगत-दत्तमत)	531.92
4.	23	उद्योग (पूँजीगत-दत्तमत)	13.35
5.	25	खाद्य (राजस्व-दत्तमत)	123.52
6.	26	पर्यटन (राजस्व-दत्तमत)	30.66
7.	26	पर्यटन (पूँजीगत-दत्तमत)	19.20
8.	27	वन (राजस्व-दत्तमत)	19.80
योग			**826.50**
9.	7	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (राजस्व-प्रभारित)	*217.95*
योग			***217.95***
महा योग			**1044.45**

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ-44)

₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष था
1	2	3	4	5
1.	04-न्याय प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	28.05	22.63	5.42
2.	04-न्याय प्रशासन (राजस्व-प्रभारित)	*13.87*	*8.97*	*4.90*
3.	05- चुनाव (राजस्व-दत्तमत)	4.71	0	4.71
4.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	43.94	12.12	31.82
5.	07-वित्त कर नियोजन सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (राजस्व-दत्तमत)	580.10	33.10	547.00
6.	07- वित्त कर नियोजन सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (पूँजीगत-दत्तमत)	72.43	11.31	61.12
7.	09 – लोक सेवा आयोग (राजस्व-प्रभारित)	*1.46*	*0*	*1.46*
8.	10- पुलिस एवं कारागार (पूँजीगत-दत्तमत)	44.60	37.78	6.82
9.	11-शिक्षा, क्रीड़ा, युवा कल्याण एवं संस्कृति (राजस्व-दत्तमत)	283.38	177.86	105.52
10.	11-शिक्षा, क्रीड़ा, युवा कल्याण एवं संस्कृति (पूँजीगत-दत्तमत)	166.31	68.58	97.73
11.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	153.99	11.38	142.61
12.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत-दत्तमत)	39.01	1.69	37.32
13.	13-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास(राजस्वदत्तमत)	235.76	112.51	123.25
14.	13-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (पूँजीगत-दत्तमत)	15.77	0.41	15.36
15.	15-कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	197.45	116.28	81.17
16.	16-श्रम एवं रोजगार (राजस्व-दत्तमत)	12.39	4.31	8.08
17.	16-श्रम एवं रोजगार (पूँजीगत-दत्तमत)	6.46	1.3	5.16
18.	17-कृषि कार्य एवं शोध (राजस्व-दत्तमत)	44.73	39.35	5.38
19.	19-ग्राम्य विकास (राजस्व-दत्तमत)	92.71	40.00	52.71
20.	20- सिंचाई एवं बाढ़ (पूँजीगत-दत्तमत)	36.30	26.69	9.61
21.	22-लोक निर्माण (राजस्व-दत्तमत)	35.43	11.64	23.79

22.	23- उद्योग (राजस्व-दत्तमत)	14.47	7.16	7.31
23.	24-परिवहन (पूँजीगत-दत्तमत)	12.55	7.66	4.89
24.	28-पशुपालन (राजस्व-दत्तमत)	4.48	2.04	2.44
25.	28- पशुपालन (पूँजीगत-दत्तमत)	2.85	1.79	1.06
26.	29-उद्यान विकास (राजस्व-दत्तमत)	14.94	0.95	13.99
27.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	193.63	53.33	140.30
28.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण (पूँजीगत-दत्तमत)	176.49	79.21	97.28
29.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	45.35	8.74	36.61
30.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (पूँजीगत-दत्तमत)	54.70	26.90	27.80
योग		**2628.31**	**925.69**	**1702.62**

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ-44)

30/31 मार्च 2012 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान का *प्रतिशत*
1	2	3	4	5
1.	04	2014-न्याय प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	22.63	21.67
2.	04	4059- लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	29.64	76.00
3.	06	4059- लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	23.91	45.98
4.	10	2055-पुलिस (राजस्व-दत्तमत)	54.79	7.95
5.	10	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	37.78	76.48
6.	11	2202- सामान्य शिक्षा (राजस्व-दत्तमत)	172.42	4.95
7.	11	4202- शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	68.58	23.87
8.	12	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (राजस्व-दत्तमत)	11.38	1.54
9.	13	2217- ग्राम्य विकास (राजस्व-दत्तमत)	112.51	41.22
10.	15	2235- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	116.33	21.76
11.	17	2401- फसल कृषि कर्म (राजस्व-दत्तमत)	39.35	11.46
12.	18	2425- सहकारी (राजस्व-दत्तमत)	11.47	27.11
13.	19	2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम (राजस्व-दत्तमत)	40.00	12.50
14.	20	2700- मुख्य सिंचाई (राजस्व-दत्तमत)	26.98	10.99

15.	22	5054- सड़क व पुल पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	71.58	8.76
16.	30	2202- सामान्य शिक्षा (राजस्व-दत्तमत)	17.74	18.20
17.	30	4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	15.71	48.73
18.	30	5054- सड़क व पुल पर पूँजीगत परिव्यय	54.95	49.55
19.	31	5054- सड़क व पुल पर पूँजीगत परिव्यय	21.59	59.15
योग			**949.34**	**11.44**

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.12; पृष्ठ-44)

व्यय की तीव्रता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखाशीर्ष योजना/सेवा	जनवरी-मार्च 2012 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2012 के दौरान किया गया व्यय	कुल व्यय	....के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
					जनवरी-मार्च 2012	मार्च 2012
1.	2011	4.34	1.98	16.10	26.92	12.30
2.	2012	1.29	0.55	4.47	28.92	12.29
3.	2014	24.27	10.48	93.12	26.06	11.25
4.	2015	21.56	13.75	28.51	75.62	48.23
5.	2029	21.95	6.89	102.71	21.37	6.71
6.	2030	18.47	13.68	27.56	67.02	49.65
7.	2039	1.71	0.41	7.77	21.99	5.32
8.	2040	9.79	3.64	45.92	21.31	7.93
9.	2045	2.10	1.08	3.74	56.25	28.87
10.	2047	0.88	0.18	3.68	23.85	4.98
11.	2049	761.95	544.07	1,769.21	43.07	30.75
12.	2051	2.01	0.74	8.53	23.51	8.62
13.	2052	15.85	2.66	70.56	22.46	3.77
14.	2053	16.88	6.10	65.63	25.72	9.29
15.	2054	9.38	2.49	43.60	21.52	5.72
16.	2055	176.00	69.25	642.85	27.38	10.77
17.	2056	5.31	1.99	17.63	30.15	11.29
18.	2058	2.11	0.55	8.52	24.73	6.48
19.	2070	10.21	4.20	42.12	24.24	9.97
20.	2071	265.61	58.21	1,135.00	23.40	5.13
21.	2203	35.17	22.37	78.00	45.09	28.68
22.	2204	12.15	6.48	35.06	34.67	18.49
23.	2205	4.37	2.53	11.67	37.45	21.66
24.	2210	181.29	82.27	618.93	29.29	13.29
25.	2215	117.93	48.09	262.51	44.92	18.32
26.	2216	0.76	0.57	1.74	43.92	32.53
27.	2217	58.30	33.98	171.10	34.07	19.86
28.	2220	7.57	1.37	36.37	20.80	3.77
29.	2225	48.40	21.33	177.37	27.29	12.03
30.	2230	18.75	9.39	54.00	34.73	17.39
31.	2235	189.96	110.44	507.21	37.45	21.77
32.	2250	4.02	2.02	19.27	20.87	10.48
33.	2251	0.03	0.03	0.03	83.96	80.88
34.	2401	168.43	126.79	429.13	39.25	29.55
35.	2403	18.36	10.36	90.64	20.25	11.43
36.	2404	2.87	0.56	11.13	25.82	5.06
37.	2405	1.98	1.16	5.14	38.53	22.67
38.	2406	100.49	49.54	305.13	32.93	16.24

39.	2408	186.05	182.88	199.73	93.15	91.56
40.	2415	29.93	29.93	114.76	26.08	26.08
41.	2425	12.88	6.67	35.16	36.63	18.97
42.	2501	28.96	26.96	70.81	40.90	38.06
43.	2515	81.18	26.50	264.48	30.69	10.02
44.	2700	46.84	13.46	219.78	21.31	6.13
45.	2701	7.59	2.78	12.39	61.25	22.43
46.	2702	23.58	12.08	53.44	44.12	22.61
47.	2711	0.94	0.52	3.24	29.12	15.91
48.	2801	0.07	0.01	0.24	28.47	2.56
49.	2810	5.47	4.97	9.74	56.14	51.01
50.	2851	11.90	3.69	37.77	31.51	9.76
51.	3053	2.21	1.44	5.09	43.46	28.30
52.	3054	105.61	95.24	156.45	67.50	60.87
53.	3055	2.89	1.62	13.75	21.00	11.79
54.	3451	8.22	1.01	10.34	79.49	9.80
55.	3452	6.37	5.45	28.12	22.63	19.39
56.	3456	1.09	0.78	2.82	38.48	27.62
57.	3475	0.41	0.09	1.65	25.02	5.17
58.	3604	116.15	99.53	378.80	30.66	26.28
59.	4059	33.63	13.12	65.70	51.19	19.97
60.	4202	42.13	21.07	131.47	32.05	16.03
61.	4210	43.32	15.20	88.13	49.16	17.24
62.	4215	24.48	4.95	80.69	30.33	6.13
63.	4216	10.44	7.39	38.84	26.88	19.04
64.	4225	6.41	5.19	11.93	53.74	43.46
65.	4235	3.25	0.00	4.16	78.14	0.03
66.	4406	15.56	12.84	16.36	95.11	78.51
67.	4700	127.40	75.79	234.70	54.28	32.29
68.	4701	1.81	1.63	4.02	44.94	40.47
69.	4702	110.16	75.02	201.67	54.63	37.20
70.	4711	9.77	0.86	15.44	63.28	5.61
योग		**3449.20**	**2020.85**	**9463.33**	**36.45**	**21.35**

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भः प्रस्तर 2.4.1 ; पृष्ठ-45)

वर्ष 2011-12 तक के लम्बित डी. सी. बिल

(30 जून 2012 को स्थिति)

(₹ लाख में)

विभाग	ए.सी. बिलों की संख्या	राशि
मत्स्य	06	2.20
पशुपालन	30	44.39
जिला कार्यक्रम अधिकारी	39	243.91
चुनाव	37	197.58
लोक निर्माण विभाग	04	190.42
शिक्षा	90	92.21
राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	37	1763.84
चिकित्सा	10	598.28
कृषि	10	1208.32
अन्य	52	161.90
योग	**315**	**4503.05**

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भः प्रस्तर 3.2; पृष्ठ-54)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखो के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखो की अवधि	अन्तिम रूप दिए गए पिछले लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखों को तैयार करने में विलम्ब हेतु अभ्युक्ति/कारण
सिंचाई विभाग:				
1.	सिंचाई कार्यशाला, खण्ड, रूड़की	2009-10	1.89	-
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग				
2.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2002-03	-	
3.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2002-03	-	

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भः प्रस्तर 3.3; पृष्ठ-54)

दुर्विनियोग, चोरी/हानि आदि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/अवधिवार विवरण (वे मामलें जिनमें मार्च 2012 के अन्त में अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी)

क्रम सं.	विभाग का नाम	विलम्बित मामलों की संख्या						
		5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष या अधिक	कुल मामलों की संख्या
1.	शिक्षा	03	--	--	--	--	--	03
2.	एकीकृत शिशु विकास योजना	01	--	--	--	--	--	01
3.	पर्यटन	01	--	--	--	--	--	01
4.	चिकित्सा	01	--	--	--	--	--	01
5.	सामाजिक कल्याण	03	--	--	--	--	--	03
6.	पशुपालन	02	--	--	--	--	--	02
7.	कृषि	01	--	--	--	--	--	01
8.	ग्राम्य विकास	02	--	--	--	--	--	02
9.	वन	01						01
योग		**15**	**–**	**–**	**–**	**–**	**--**	**15**

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भः प्रस्तर 3.3; पृष्ठ-54)

चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सम्पत्ति की हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सम्पत्ति का दुर्विनियोग/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
शिक्षा	01	2.33	03	48.22	04	50.55
एकीकृत शिशु विकास योजना	--	--	01	0.52	01	0.52
पर्यटन	--	--	01	1.78	01	1.78
चिकित्सा	--	--	01	11.96	01	11.96
सामाजिक कल्याण	--	--	03	84.31	03	84.31
पशुपालन	--	--	02	144.49	02	144.49
कृषि	--	--	01	14.11	01	14.11
ग्राम्य विकास	--	--	02	10.58	02	10.58
लोक निर्माण विभाग	01	1.80	--	--	01	1.80
वन	--	--	01	72.69	01	72.69
योग	**02**	**4.13**	**15**	**388.66**	**17**	**392.79**

परिशिष्ट-4.1

शब्दावली

क्रमांक	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या स्थिर कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय आँकड़ों की तन्यता अथवा प्रभावनीयता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ उ में एक *प्रतिशत* तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 *प्रतिशत* बिन्दुओं तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	*कोर पब्लिक गुड्स* ऐसी वस्तुएँ है जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु के दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुडस ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की कामना रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों के पोषण हेतु मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर पोषण के समर्थन हेतु प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।

6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण विकासपरक और अविकासपरक में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती है जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।
7.	ऋण वहन क्षमता	ऋण वहन क्षमता को किसी समयावधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके ऋण को चुकाने की क्षमता के बारे में चिन्ता को मूर्त रूप देती है। इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियाँ की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।
8.	ऋण स्थिरीकरण	स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर – ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्तें बताती है कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात गिरेगा।
9.	ऋणेत्तर प्राप्तियाँ की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियाँ की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सक्ता था यदि बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सक्ते।
10.	उधार ली गई निधियाँ की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियाँ से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण निधियाँ की निवल उपलब्धता को बताते हुए ऋण प्राप्तियाँ का प्रयोग ऋण विमोचन में किया जाता है।

11.	ऋणेत्तर प्राप्तियाँ	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियाँ की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणेत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।